



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 511]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 8, 2013/आश्विन 16, 1935

No. 511]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 8, 2013/ASVINA 16, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

महानिदेशक (रक्षोपाय)

सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादकर

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2013

**विषय:- मिथाइल एसिटोएसिटेट के आयातों से सम्बंधित रक्षोपाय जांच-अंतिम जांच परिणाम ।**

सा.का.नि.676 (अ).—सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 को ध्यान में रखते हुए;

**I. प्रक्रिया**

1. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 (जिसे एतदपश्चात् रक्षोपाय शुल्क कहा गया है) के नियम 5 के अंतर्गत मेरे समक्ष मैसर्स लक्ष्मी आर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई ने अपने परामर्शदाता मैसर्स ईएलपी एडवोकेट्स एंड सालिसिटर्स के माध्यम से, एक आवेदनपत्र भारत में मिथाइल एसिटोएसिटेट के बढ़े हुए आयातों द्वारा मिथाइल एसिटोएसिटेट के घरेलू उत्पादकों को कारित की जा रही गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती से उनकी रक्षा की जा सके।
2. उक्त रक्षोपाय नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की घरेलू उत्पादकों के संयंत्रों का स्थल दौरा करके यथावश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन कराया गया। इस सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय पाठ सार्वजनिक फाइल के रूप में रखा गया है। इस बात से संतुष्ट होकर कि नियम 5 की अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है, भारत में मिथाइल एसिटोएसिटेट के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच रूप करने का नोटिस सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के अंतर्गत दिनांक 06 जून, 2013 को जारी किया गया और उसी दिन उसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित कराया गया।

3. घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए आवेदनपत्र के अगोपनीय पाठ की एक प्रति के साथ दिनांक 06 जून, 2012 के जांच शुरुआत नोटिस की एक प्रति केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य मंत्रालय तथा अन्य सम्बंधित मंत्रालयों, प्रमुख निर्यातकर्ता देशों की सरकारों को उनके भारत स्थित राजदूतावासों के जरिए तथा अधोलिखित सूची में दिए गए हितबद्ध पक्षकारों को सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6(2) और 6(3) के अनुसार प्रेषित की गई।

**(क) घरेलू उत्पादक**

- (i) मैसर्स लक्ष्मी आर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चन्द्रमुखी, तीसरा तल, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021

**ख. आयातकर्ता/प्रयोक्ता:**

- (i) सी.जे.शाह, 105, 10वां तल, बजाज भवन, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021  
(ii) हैजेल एम्बेसी सेंटर, जमनालाल बजाज रोड, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021  
(iii) सरना कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, जी आईडीसी, वापी परुडी वलसाड, गुजरात-396185  
(iv) एएसएम कैमिकल्स, 2-2-1137/5/बी, न्यू नलकुन्टा, विजया अपार्टमेंट्स के सामने, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500044  
(v) आर्क फार्मलैब्स इंडिया "एच" विंग, 4था तल, टेक्स सेण्टर आफ पाकी विहार रोड, चांदीवली, अंधेरी (पूर्व) मुम्बई-400072  
(vi) अरबिन्दो फार्मा लिमिटेड प्लॉट#2, मैत्री विहार, अमीरपेट, हैदराबाद-500038 आंध्र प्रदेश  
(vii) कलरटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सर्वे सं.91, नवीन फ्लोरीन इंडस्ट्रीज के सामने, भिस्तान-395023, सूरत गुजरात  
(viii) कैलाश कैमिकल्स, 191 फेज-1, जीआईडीसी एस्टेट, वात्वा, जीआईडीसी, अहमदाबाद-382445  
(ix) दिया कैमी, द्वितीय तल, 56/58, गरीबदास स्ट्रीट, वडगढ़ी, मुम्बई-400003  
(x) नूतन डार्ड केम, प्लॉट नं.2428 जीआईडीसी सचिन, जिला-सूरत-394230  
(xi) पोलिगन कैमिकल्स, प्लॉट सं. 337, जी आई डी सी इंडस्ट्रियल एस्टेट, औधव, अहमदाबाद-382415  
(xii) प्राइमा कैमिकल्स, प्लॉट नं. 337, जीआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, उदव, अहमदाबाद-382415

**ग. निर्यातकर्ता**

- (i) क्विंगदाओ डबल पीच स्पेशियलिटी कैमिकल्स (ग्रुप) कंपनी लिमिटेड, 28 हांगझोऊ रोड, क्विंगदाओ, चीन पीसी 266031  
(ii) झांगजियांग होप कैमिकल्स कंपनी लिमिटेड नाशा टाउन, झांगजियांगसिटी  
(iii) चीन नैन्टोंग एसिटिक एसिड कैमिकल कंपनी लिमिटेड नं. 968, जियांगशान रोड, इकोनामिक एंड टेक्निकल डिवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट, नान्टांग सिटी, जियांगसु प्राविस, चीन  
(iv) वेंग लांग ग्रुप कंपनी लिमिटेड, वेंगलांग इंडस्ट्रियल जोन, मुआओ 315476, निन्गबो, चीन  
(v) डाइसेल, 1-1, शिन्को चो मायोको शि, नीगाटा 944850 जापान  
(vi) मित्सुबोशी, 1818, ओहाजा निशिनोशि कोमाकी 485-0077, जापान  
(vii) लोन्झा चा 3930 विस्प, स्विट्जरलैंड  
(viii) ईस्टमैन पीओ बाक्स 431 किंगसपोर्ट टेन्नेस्सी 37662 यूएसए

**घ. निर्यातकर्ता राष्ट्र**

- (i) संयुक्त राज्य अमेरिका का राजदूतावास, शांति पथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021  
(ii) रूसी परिसंघ का व्यापार प्रतिनिधिमंडल, ब्लॉक 50-ई, न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021  
(iii) चीन जनवादी गणराज्य का राजदूतावास, 50-डी, शांति पथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021  
(iv) स्विट्जरलैंड का राजदूतावास, न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021  
(v) व्यापार एवं आर्थिक प्रभाग, भारत में यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधिमंडल, 65, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली-110003

4. भारत में ज्ञात निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा उपलब्ध जानकारी के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावलियां इस अनुरोध के साथ भेजी गई कि वे इस जांच शुरुआत नोटिस के 30 दिनों के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराये। निम्नलिखित पक्षकारों से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए।
- क. एडवोकेट्स एजेडबी एंड पार्टनर्स के जरिए मैसर्स ईस्टमैन कैमिकल कंपनी।
- ख. मैसर्स नैनटॉग एसिटिक एसिड कैमिकल कंपनी लिमिटेड चीन जन.गण. से मैसर्स डब्ल्यूटीसी एंड एडवोकेट्स के माध्यम से।
- ग. मैसर्स जिनहूआ फार्मास्यूटिकल्स (सौंगुवांग) कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. से मैसर्स डब्ल्यूटीसी एंड एडवोकेट्स के माध्यम से।
- घ. मैसर्स जियांगशु टियानचेंग बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. से मैसर्स डब्ल्यूटीसी एंड एडवोकेट्स के माध्यम से।
- ड. मैसर्स क्विंगडाओ डब्ल पीच स्पेशलिटी कैमिकल (ग्रुप) कंपनी लिमिटेड डब्ल्यूटीसी एंड एडवोकेट्स के माध्यम से।
- च. मैसर्स सी जे शाह एंड कंपनी से मैसर्स टीपीएम कंसलटेन्ट्स के जरिए।
- छ. मैसर्स प्राइमा कैमिकल्स से मैसर्स टीपीएम कंसलटेन्ट्स के जरिए।
- ज. मैसर्स पोलिगन कैमिकल्स से मैसर्स टीपीएम कंसलटेन्ट्स के जरिए।
- झ. मैसर्स अरबिन्दो फार्मा लिमिटेड।
5. (क) निम्नलिखित पक्षकारों से यह अनुरोध प्राप्त हुआ कि उन्हें हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना जाए-
  - क. आयातकर्ता: मैसर्स नूतन डाई कैम, सूरत (गुजरात)
  - ख. आयातकर्ता: मैसर्स पोलिगन कैमिकल्स, अहमदाबाद
  - ग. आयातकर्ता: मैसर्स प्राइमा कैमिकल्स, अहमदाबाद
  - घ. निर्यातकर्ता राष्ट्र: व्यापार एवं आर्थिक अनुभाग, भारत में यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधिमंडल, 65, गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली-110003
- ड. निर्यातकर्ता राष्ट्र: भारत गणराज्य में रूसी परिसंघ का व्यापार प्रतिनिधि मंडल और रूस का आर्थिक विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।  
सभी अनुरोध स्वीकार कर लिए गए।
- (ख) निम्नलिखित पक्षकारों ने रक्षोपाय शुल्क नियमावली, 1997 के नियम 6(4) में उल्लिखित विस्तृत उत्तर प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित पक्षकारों ने समय बढ़ाये जाने की मांग की जिसकी अनुमति दे दी गई, जैसा कि निम्नलिखित है:
  - क. मैसर्स पोलिगन एवं प्राइमा कैमिकल्स
  - ख. मैसर्स सी जे शाह एंड कंपनी
  - ग. मैसर्स लॉन्जा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
  - घ. मैसर्स अरबिन्दो फार्मा लिमिटेड
6. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिव्यक्त विचारों पर समुचित निर्धारण करने के लिए विचार किया गया। प्राप्त अथवा अधिप्राप्त अगोपनीय सूचना को सार्वजनिक फाइल में रखा गया है।
- II. **हितबद्ध पक्षकारों के विचार (जांच शुरुआत के पश्चात)**
7. निम्नलिखित आयातकों/निर्यातकों/निर्यातकर्ता राष्ट्रों से जांच शुरुआत नोटिस के प्रत्युत्तर प्राप्त हुए:-
  1. ताईपेई इकनामिक एंड कलचरल सेंटर नई दिल्ली से दिनांक 17 जून, 2013 का पत्र
  2. मैसर्स सोजित्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
  3. मैसर्स लॉन्जा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद
  4. मैसर्स नूतन डाई कैम, सूरत
  5. मैसर्स अरबिन्दो फार्मा लिमिटेड, हैदराबाद

6. मैसर्स ईस्टमैन कैमिकल कंपनी, टेन्निसी
7. मैसर्स पोलिगन कैमिकल, अहमदाबाद
8. मैसर्स सी जे शाह एंड कंपनी मुम्बई
9. मैसर्स प्राइमा कैमिकल्स अहमदाबाद
10. मैसर्स क्यूनडाओ डबल पीच स्पेशलिटी कैमिकल्स (ग्रुप) कंपनी लिमिटेड चीन जन.गण.
11. मैसर्स नान्तोंग एसिटिक एसिड कैमिकल्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
12. मैसर्स जियांगशु टायनकेंग बायोकैमिकल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड चीन जन. गण.
13. मैसर्स जिनहुआ फार्मास्यूटिकल्स (शौगुओंग) कंपनी लिमिटेड चीन जन. गण.
14. मैसर्स लक्ष्मी आर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड (घरेलू उद्योग)

उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों को यहां संक्षिप्तता के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है परंतु उन पर निर्धारण किये जाते समय समुचित स्थानों पर विस्तृत चर्चा की गई है।

### III. सार्वजनिक सुनवाई

8. 26 अगस्त, 2013 को एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया गया। इस सार्वजनिक सुनवाई के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 5 अगस्त, 2013 को नोटिस भेजा गया था। उक्त सार्वजनिक सुनवाई में घरेलू उद्योग अर्थात् मैसर्स लक्ष्मी आर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड सहित निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने प्रतिभागिता की :-
  1. चीन जन.गण. के निम्नलिखित निर्यातकों, जिनका प्रतिनिधित्व मैसर्स डब्ल्यूटीसी कंसल्टेंट्स एंड एडवोकेट्स द्वारा किया गया :-
    - क. चाईना पेट्रोलियम एंड कैमिकल इंडस्ट्री फेडरेशन।
    - ख. क्विंगडाओ डबल पीच स्पेशलिटी कैमिकल्स (ग्रुप) कंपनी लिमिटेड
    - ग. नानतोंग एसिटिक एसिड कैमिकल कंपनी लिमिटेड
    - घ. जियांगशु टियानचेंग बायोकैमिकल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड
    - ड. जिनहुआ फार्मास्यूटिकल्स (शौगेंग) कंपनी लिमिटेड
  2. भारत के निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा इनका प्रतिनिधित्व मैसर्स टीपीएम एडवोकेट्स द्वारा किया गया :-
    - क. सी जे शाह, मुम्बई
    - ख. प्राइमा कैमिकल्स, अहमदाबाद
    - ग. अरबिन्दो फार्मा लिमिटेड, हैदराबाद
    - घ. पोलिगन कैमिकल्स, अहमदाबाद
3. भारत में आयातक/प्रयोक्ता- मैसर्स नूतन डाई कैम, जिनका प्रतिनिधित्व मैसर्स पी के शाह द्वारा किया गया।
4. संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यातकर्ता-मैसर्स ईस्टमैन कैमिकल एंड कंपनी जिसका प्रतिनिधित्व मैसर्स एजेडबी एंड पार्टनर्स द्वारा किया गया।
9. उन सभी हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने इस सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया था, से यह अपेक्षा की गई कि वे सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 के नियम (6) के उपनियम (6) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मौखिक रूप से अपने व्यक्त किये गये विचार लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें। उसके पश्चात् किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा दायर किये गये लिखित प्रस्तुतिकरण की प्रति अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध करा दी गई। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गए लिखित प्रस्तुतिकरण, यदि कोई हो तो, उसका प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। इस मामले में 26 अगस्त, 2013 को आयोजित की गई सार्वजनिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग ने मौखिक प्रस्तुतिकरण किये और उसके पश्चात् लिखित प्रस्तुतिकरण भी दिये। इस सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप में व्यक्त किये गये अपने

विचारों को सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 के नियम (6) के उपनियम (6) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मौखिक रूप में भी प्रस्तुत करें। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये लिखित प्रस्तुतिकरणों की प्रतियां अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध करा दी गई। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गए लिखित प्रस्तुतिकरण, यदि कोई, का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया गया। मैसर्स डब्ल्यूटीसी कंसल्टेंट्स और मैसर्स ईएलपी एडवोकेट्स की ओर से लिखित प्रस्तुतिकरण/अद्यतन क्षति आंकड़े प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को उनके द्वारा दिये गये कारणों पर विचार करते हुए क्षमा कर दिया गया।

10. इस सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने और अपने विचार प्रस्तुत करने में अपनी प्रतिभागिता के लिए व्यापार एवं आर्थिक अनुभाग, भारत में यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधिमंडल से संपुष्टि प्राप्त हुई थी। तथापि, उनकी ओर से किसी भी प्रतिनिधि ने इस सार्वजनिक सुनवाई में न तो प्रतिभागिता की और न ही कोई लिखित प्रस्तुतिकरण किया।
11. तदनुसार, सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात और जांच शुरुआत के पश्चात के दौरान लिखित प्रस्तुतिकरण के रूप में प्राप्त सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिव्यक्त विचारों की जांच की गई और समुचित निर्धारण करने के लिए उन पर विचार किया गया।

#### IV. हितबद्ध पक्षकारों के विचार (सुनवाई के पश्चात)

**मैसर्स इएलपी एडवोकेट्स एंड सोलिसिटर्स के जरिए प्रस्तुत घरेलू उद्योग के विचार**

12. घरेलू उद्योग ने निम्नवत प्रस्तुतिकरण किया:-

#### (क) संबद्ध वस्तु के भारत में बढ़ते हुए आयात

- (i) यह कि, जहां तक पांच वर्ष की अवधि के दौरान आयातों की प्रवृत्ति की जांच करने का संबंध है, उनके विचार अर्जेंटिना-फुटवियर मामले में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के विचार उनके विचारों से भिन्न है। वाक्यांश रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 और गाट के अनुच्छेद-:1 (क) दोनों ने क्रिया वाक्यांश "आयात किया जा रहा है के लिए वर्तमान काल का प्रयोग किया जाना यह संकेत करता है कि विगत पांच वर्षों के दौरान आयातों की प्रवृत्ति की ही जांच न करके अत्यधिक अभिनव आयातों की जांच किया जाना आवश्यक है।
- (ii) आयातों में क्षति अवधि के दौरान निरुपाधि रूप से तथा उत्पादन, बिक्री और मांग के संबंध में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। अंतिम बिन्दु से अंतिम बिन्दु के आयात पर 28 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है जबकि आयातों की वार्षिक आधार पर वर्ष 2012-13 में केवल 42 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है।
- (iii) वर्ष 2010-11 की चौथी तिमाही से आयातों में अचानक, तीव्र और भीषण वृद्धि हुई है।
- (iv) वर्ष 2009-10 के आयातों, जब घरेलू उद्योग प्रचालनरत नहीं था, का विश्लेषण करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय घरेलू उद्योग सक्रिय या प्रचालनरत नहीं थी, सही नहीं है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुतिकरण किया है कि घरेलू उद्योग ने अपना प्रचालन मई, 2010 से प्रारंभ किया था और यह भारत में संबद्ध वस्तु का एक मात्र उत्पादक है। इसके अतिरिक्त पूर्ववर्ती घरेलू उत्पादक मैसर्स क्लेरियंट ने अपना प्रचालन वर्ष 2009-10 में बंद कर दिया था और इस कारण वर्ष 2009-10 में कोई घरेलू उद्योग नहीं था। अतः, वर्ष 2009-10, जब घरेलू उद्योग प्रचालन में नहीं था, से आयातों का विश्लेषण करना न केवल गलत एवं दुष्प्रतिनिधित्वपूर्ण है बल्कि इससे भारत में आयातों के विश्लेषण में गंभीर विकृति भी उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012-13 में, घरेलू उद्योग की मौजूदगी के बावजूद, आयातों के स्तर में भारी वृद्धि हुई जो स्पष्टतः यह स्थापित करता है कि भारत में आयातों में अचानक, तीव्र एवं भारी वृद्धि हुई है।

#### (ख) अनपेक्षित परिस्थितियां

घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित कारण प्रस्तुत किये हैं जो उनकी समझ में वर्तमान मामले में अप्रत्याशित परिस्थितियां बनती हैं :-

**(i) यूरोप की बाजारों में खपत में अप्रत्याशित गिरावट:**

विदेशों में संबद्ध वस्तु की व्यापक क्षमताओं के परिणाम स्वरूप यूरोप की बाजारों में मांग में अप्रत्याशित गिरावट आयी है और विदेशी उत्पादकों ने भारत को अपने निर्यात बढ़ाने का आश्रय लिया है।

**(ii) चीन जन.गण. में अतिरिक्त क्षमताएं**

चीन जन.गण. की क्षमताओं में अचानक वृद्धि हुई है जिससे भारत को आयातों का विपथन किया गया। वास्तव में, दायर की गई अगोपनीय निर्यातक प्रश्नावलियों से यह स्पष्टतः देखा जा सकता है कि मैसर्स जिन्हुआ फार्मास्युटिकल्स (शोगैंग) कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. और मैसर्स क्विंगडाओ डबल पीच स्पेशलिटी (ग्रुप) कंपनी लिमिटेड दोनों ने अभी हाल ही में वर्ष 2012-13 में अपने संयंत्र स्थापित किये हैं और उन्होंने भारत को निर्यात करने की बात मानी है। इसके अतिरिक्त, चीन के एक अन्य उत्पादक अर्थात् मैसर्स निंगवो वेंगलांग टेक कंपनी लिमिटेड में उल्लेख किया है कि उनकी कंपनी भारत को निर्यात करना प्रारंभ करना चाहती है। वास्तव में, बाजार आसूचना के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि मैसर्स निंगवो वेंगलांग टेक कंपनी लिमिटेड की संस्थापित क्षमता घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता से लगभग आठ गुना ज्यादा है। उपर्युक्त स्वीकृतियां स्पष्टतः यह संकेत करती हैं कि भारत को लगातार संवर्धित मात्रा में आयात होना बाध्यकर है।

**(iii) कच्चे माल की लागत में बढ़ोत्तरी के बावजूद आयातों का अप्रत्याशित रूप से न्यून कीमत निर्धारण**

जांच की अवधि के दौरान कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई है। तथापि, कच्चे माल की कीमतों में वैश्विक रूप से वृद्धि होने के बावजूद आयात कीमतों में केवल मामूली सी वृद्धि हुई है। चूंकि भारत एक कीमत आकर्षक बाजार है, इसलिए उपभोक्ताओं द्वारा कम कीमत के इन आयातों का अच्छा स्वागत किया गया। अतः, कम कीमत के आयातों के कारण भारत में आयातों की बढ़ोतरी हुई है।

**(ग) गंभीर क्षति**

कच्चे माल की कीमतों में वैश्विक रूप से भारी वृद्धि होने के बावजूद आयात कीमतों में केवल मामूली सी बढ़ोतरी हुई है।

- (i) वर्ष 2012-13 में घरेलू उद्योग के उत्पादन में भारी गिरावट आई है।
  - (ii) वर्ष 2012-13 में घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में 41 प्रतिशत तक भारी गिरावट आई है।
  - (iii) वर्ष 2012-13 में घरेलू बिक्रियां तेजी से घटकर 2017 मी.टन तक रह गयी ।
  - (iv) घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वर्ष 2011-12 तक वृद्धि हुई और उसके पश्चात इसमें तीव्र गिरावट आई।
  - (v) संबद्ध वस्तु की मांग में जांच की अवधि के दौरान 24 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्रियों में केवल 16 प्रतिशत वृद्धि ही हुई है, जबकि आयातों में 28 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। आयातों में वृद्धि की दर मांग में हुई वृद्धि की दर से बहुत अधिक है।
  - (vi) इन बड़े हुए आयातों द्वारा घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को गंभीर रूप से प्रभावित किया गया। अभी हाल ही की अवधि में इसमें गिरावट आई है।
  - (vii) वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान घरेलू उद्योग को भारी घाटा सहन करना पड़ा है।
13. यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यद्यपि जांच की अवधि में कच्चे माल की कीमतों में हुई वृद्धि के अनुरूप बिक्री लागत में 18 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में केवल 8 प्रतिशत तक ही वृद्धि हुई जिससे कि वह आयातों की उतराई कीमत से प्रतिस्पर्धा कर सके। वास्तव में, घरेलू उद्योग को आयातों द्वारा प्रस्तुत कीमतों पर अपने माल की बिक्री करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अतः, यद्यपि न्यूनतम अधोरदन हुआ है तथापि इसका भारी अधोबिक्रयण हुआ और घरेलू उद्योग बिक्री लागत से कम कीमतों पर अपने माल की बिक्री कर रहा है।

**(घ) गंभीर क्षति की चुनौती**

14. यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत में संबद्ध वस्तु के निरंतर आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का स्पष्ट एवं आसन खतरा है वास्तव में, घरेलू उद्योग को विदेशी उत्पादक से ऐसा पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उसने यह प्रस्ताव किया है कि घरेलू उद्योग अपना घरेलू उत्पादन बंद कर दे जिससे कि घरेलू उद्योग द्वारा सृजित की जा रही प्रतिस्पर्धा का शमन हो सके और देश में आयात सुलभ हो सकें।
15. इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर संबद्ध वस्तु के संवर्धित आयातों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। संबद्ध वस्तु के बेरोकटोक आयातों के आलोक में, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में और अधिक गिरावट आने की चुनौती उत्पन्न हो रही है। इसके परिणामस्वरूप होने वाली गंभीर क्षति का घरेलू उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी है।
16. यह नोट करना भी संगत है कि चीन जन.गण. में नई क्षमताएं संस्थापित की गई हैं और यूरोपियन यूनियन तथा संयुक्त राज्य में पर्याप्त क्षमता निष्क्रिय पड़ी है। चूंकि वर्तमान आयात ही घरेलू उद्योग को गंभीर क्षतिकारित कर रहे हैं इसलिए इन देशों से और अधिक उत्पादन तथा निर्यातों की संभावना को देखते हुए यह आवश्यक है कि घरेलू उद्योग को लगातार क्षति बनी रहेगी।
17. अतः, भारत में संबद्ध वस्तु के सतत आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का स्पष्ट एवं आसन्न खतरा है।

**(ङ.) कारणात्मक संबंध**

18. संवर्धित आयातों तथा घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के बीच प्रत्यक्ष कारणात्मक संबंध है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संबद्ध वस्तु की बिक्री आयातों की प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा में की जाती है। आयातों की उतराई कीमत तर्कसंगत लागत से बहुत कम है और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत का निर्धारण आयात कीमतों द्वारा किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, कम कीमतों वाले आयातों की लगातार मौजूदगी के कारण उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री, लाभ, निवेश पर अर्जन और नकदी प्रवाह में गिरावट आ रही है।
19. विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे न्यून कीमतों को ध्यान में रखते हुए आयातों में घरेलू उद्योग द्वारा कम कीमतें प्रस्तुत किये जाने के बावजूद लगातार वृद्धि हो रही है घरेलू उद्योग को अपनी कीमते बिक्री लागत से भी कम पर निर्धारित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। संवर्धित आयातों के परिणामस्वरूप आयातों के बाजार हिस्से में भारी वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आयी है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट ने घरेलू उद्योग की उत्पादन और क्षमता उपयोग पर विपरीत प्रभाव डाला है। अतः, यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को बढ़ते आयातों के कारण क्षति सृजित की जा रही है।

**(च) समायोजन योजना**

20. घरेलू उद्योग ने एक विस्तृत समायोजन योजना प्रस्तुत की है जिसमें आयात प्रतिस्पर्धा से सकारात्मक समायोजन करने के प्रयासों की उस योजना का वर्णन किया गया है जिसे घरेलू उद्योग दो तीन वर्ष की अवधि में क्रियान्वित करने की योजना बना रहा है।

**(छ) जन हित**

21. इस मामले के तथ्यपरक पहलुओं के अनुरूप, घरेलू उद्योग ने भारी निवेश किया है और बढ़ती हुई भारतीय मांग को घरेलू रूप से पूरा करने के लिए महाराष्ट्र के महाड में एक नवीन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है और भारत में रोजगार का सृजन किया है। घरेलू उद्योग अभी शैशव अवस्था में है और इसे विदेशी उत्पादकों द्वारा न्यून कीमतों के आयातों और आक्रमक विपरण के कारण पतन से बचने के लिए तत्काल राहत की आवश्यकता है क्योंकि भारत एक कीमत आकर्षक बाजार है।
22. अतः, भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना, और अविकसित घरेलू उद्योग को तत्काल सुरक्षा प्रदान कराना तथा उसकी वृद्धि एवं घरेलू उद्योग द्वारा सृजित रोजगार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवसरों की रक्षा करना जन हित में है।

### निर्यातकर्ता राष्ट्रों के विचार

23. भारत में यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि व्यापार एवं आर्थिक खंड से सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने और प्रस्तुतिकरण करने की संपुष्टि प्राप्त हुई थी। तथापि, उनकी ओर से न तो कोई सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित हुआ और ना ही उन्होंने कोई लिखित प्रस्तुतिकरण किया।

### निर्यातकों के विचार

#### मैसर्स ईस्टमैन कैमिकल कंपनी, मैसर्स एजेडबी एंड पार्टनर्स के माध्यम से दायर

24. मैसर्स एजेडबी एंड पार्टनर्स ने अपने दिनांक 3 सितम्बर, 2013 के पत्र के तहत अनुरोध किया था कि दिनांक 12 जुलाई, 2013 के पत्र के तहत किये गये उनके प्रस्तुतिकरण और सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात किये गये उनके प्रस्तुतिकरण को रिकार्ड में ले लिया जाए और तदनुसार उनके द्वारा प्रस्तुतिकरणों का सार संक्षेप में निम्नलिखित है:-

- (क) घरेलू उद्योग ने भारतीय एमएए बाजार में प्रवेश करने के केवल तीन वर्षों के अंदर काफी अच्छी तरह से कार्यनिष्पादन किया है और उसका रक्षोपाय से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने का इरादा है।
- (ख) आयातों की वृद्धि के लिए कोई अनपेक्षित परिस्थिति जिम्मेदार नहीं है।
- (ग) यूएस-लैम्ब मामले में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के निर्णय के अनुसार संवर्धित आयात अनपेक्षित विकास का परिणाम नहीं है।
- (घ) याचिका और जांच शुरुआत नोटिस में ऐसे किसी अनपेक्षित परिस्थिति के मामले का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे भारत में मिथाइल एसिटोएसिटेट के आयातों में तथाकथित वृद्धि हुई हो।
- (ङ.) यह कि विदेशी उत्पादक निर्यातानुमुखी उत्पादक हैं, इसे अनपेक्षित परिस्थिति के रूप में उल्लिखित नहीं किया जा सकता है।
- (च) अर्जेंटिना फुटवियर मामले में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के निर्णय के अनुसार आयातों में यह वृद्धि गुणात्मक रूप से और परिमाणात्मक रूप से अभिनव, अचानक, तीव्र एवं इतनी अधिक वृद्धि हुई है जिससे गंभीर क्षति सृजित हो सके या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो सके।
- (छ) आयातों में वृद्धि अंतिम बिन्दु से अंतिम बिन्दु तक तुलना के रूप में स्पष्ट होना चाहिए जांच की अवधि में हस्तक्षेप करने वाली प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने में भी यह स्पष्ट होना चाहिए।
- (ज) वर्ष 2012-13 की द्वितीय और चौथी तिमाई के बीच छह माह की अल्प अवधि के अंदर ही आयातों में 40 प्रतिशत तक की गिरावट आई है।
- (झ) याचिकाकर्ता को न तो गंभीर क्षति हो रही है और न ही उसके समक्ष गंभीर क्षति की कोई चुनौती है। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान अच्छा कार्य किया है।
- (ञ) चूंकि जांच की अवधि की विगत तिमाही से प्रारंभ करके भारत में मिथाइल एसिटोएसिटेट के आयातों में प्रतिबोधगम्य गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में सुधार हो रहा है इसलिए यह दावा की घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है पूर्णतया भ्रामक है।
- (ट) याचिकाकर्ता को वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान भारी लाभ हुआ है।
- (ठ) याचिकाकर्ता का यह दावा कि उसकी लाभप्रदायकता में कमी आई है, इसका कारण हो सकता है कि उसे अन्य डाइकेटिन अवकलजों अथवा उत्पादों के उत्पादन में घाटा हुआ हो।
- (ड) याचिकाकर्ता का क्षमता उपयोग संगत है क्योंकि इसमें अभी हाल ही में बाजार में प्रवेश किया है। केवल तीन वर्षों की अवधि में 25 प्रतिशत बाजार पर कब्जा कर लेना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- (॥) वर्ष 2012-13 की अभिनवतम तिमाही अर्थात् चौथी तिमाही में याचिकाकर्ता के उत्पादन में सुधार हुआ है।
- (ण) आयातों तथा याचिकाकर्ता द्वारा सहन की गई तथाकथित क्षति के बीच कोई यथार्थ एवं पर्याप्त कारणात्मक संबंध मौजूद नहीं है।
- (त) घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई, आयातों में वृद्धि के अलावा कई अन्य कारणों से भी हो सकती है जिनमें से किसी को भी संवर्धित आयातों से क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।



- (थ) घरेलू उद्योग को क्षति अपने स्वयं के कारणों से हुई है और इसके लिए आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- (द) रक्षोपाय मामला जन हित में नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता एकमात्र उत्पादक है और रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण करने से उन्हें एकाधिकार की स्थिति प्राप्त हो जाएगी जिससे उन भारतीय ग्राहकों से एकाधिकारपूर्ण लाभ प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है जो मिथाइल एसिटोएसिटेट का प्रयोग करके उससे बनने वाली वस्तुओं का उत्पादन करते हैं।
- 25. चाईना पेट्रोलियम एंड कैमिकल इंडस्ट्री फेडरेशन, जियांगशू टियानचेंग बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड, नैनटोंग एसिटिक एसिड कैमिकल कंपनी लिमिटेड, विंगंडाओं डबल-पीच स्पेशलिटी कैमिकल्स (ग्रुप) कंपनी लिमिटेड, जिन्हुआ फार्मास्युटिकल (शौगोंग) कंपनी लिमिटेड, सभी चीन जन.गण से जिन्होंने बर्ड ट्रेड कंस्टलेटन्ट्स एंड एडवोकेट्स के जरिए अपने विचार दायर किये।**
- (क) रक्षोपाय शुल्क नियमावली, 1997 के नियम 5(3) के अंतर्गत यथा निर्धारित साक्ष्यों की पर्याप्तता की जांच नहीं की गई है।
- (ख) घरेलू उद्योग ने घरेलू उत्पादकों के लिए प्रश्नावली दायर नहीं की है और इसलिए जांचकर्ता प्राधिकारी के साथ सहयोग करने में असफल रहा है।
- (ग) आवेदन पत्र में अनपेक्षित विकास का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है।
- (घ) आवेदनकर्ता ने कोई व्यवहार्य समायोजन योजना प्रदान नहीं की है। समायोजन योजना के संबंध में कोई तकनीकी ब्यौरा भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- (ङ.) डीजीसीआईएस आंकड़ों, जिन्हें आयात आकड़ों के सर्वाधिक प्राधिकृत स्रोत के रूप में माना जाता है, पर इस मामले में भरोसा नहीं किया गया है।
- (च) अभी हाल ही अवधि में समग्र रूप से या संगत रूप से आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
- (छ) घरेलू उद्योग का दावा कि संबद्ध वस्तु की आयात कीमत में गिरावट आयी है पूरी तरह से गलत एवं त्रुटिपूर्ण है।
- (ज) माल सूची का कोई संग्रह नहीं हुआ है।
- (झ) घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के लिए आयातों को उत्तरदायी ठहराना पूर्णतया गलत। वास्तव में यह घाटा अन्य कारकों जैसे एक अन्य कंपनी से पुराने संयंत्र की खरीद करना, जैसे कारणों से हुआ है।
- (ञ) आयातों में वृद्धि होने और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- (ट) याचिकाकर्ता अपना विस्तार करना चाहता है तथा भारत में आयातों का प्रशमन करके बाजार पर एकाधिकार स्थापित कर लेना चाहता है।
- (ठ) यह याचिका इस बात को स्पष्ट नहीं करती है कि क्या विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना जनहित में होगा।
- (ड) अनंतिम रक्षोपाय शुल्क के संबंध में विचार करने का कोई कारण मौजूद नहीं है क्योंकि इस मामले में नाजुक परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं।

#### आयातकों/ प्रयोक्ता उद्योग के विचार

- 26. मैसर्स अरबिन्दो फार्मा, मैसर्स सी जे शाह एंड कंपनी, मैसर्स नूतन डाइकेम, मैसर्स प्राइमा कैमिकल्स और मैसर्स पोलिगन कैमिकल्स के मैसर्स टीपीएम कंस्टलेटन्ट्स के जरिए प्रस्तुत किये गये विचार**
- (क) मैसर्स लक्ष्मी आर्गेनिक्स ने ऐसे उत्पाद का यह जानते हुए भी जोखिम उठाया कि इस उत्पाद में क्लेरियंट अच्छा निष्पादन नहीं कर रहा है।
- (ख) याचिकाकर्ता द्वारा दावा किये गये अनपेक्षित विकास के समर्थन में कोई साक्ष्य दिया जाना चाहिए। इस मामले में उनके द्वारा दावा किये गये अनपेक्षित विकास के समर्थन में घरेलू उद्योग द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- (ग) कोई कीमत अधोरदन भी नहीं हुआ है क्योंकि याचिकाकर्ता आयात कीमतों के समान कीमतों पर ही अपने माल की बिक्री कर रहा है।
- (घ) महानिदेशक रक्षोपाय ने विगत की जांचों में कम से कम तीन संपूर्ण वर्षों के आंकड़ों पर अभिन्न रूप से विचार किया है।
- (ङ.) संवर्धित आयातों का भी कोई साक्ष्य नहीं है। घरेलू उद्योग ने गंभीर क्षति को भी प्रमाणित नहीं किया है। आंकड़ा संग्रहण अवधि भी अनश्चितताओं से भरी हुई है।
- (च) याचिकाकर्ता ने भारत सरकार के सर्वाधिक प्रमाणित आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया है और गौण स्रोत से प्राप्त आंकड़ों को अपनाया है। डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों को अपनाया जाना चाहिए क्योंकि वे आंकड़ें ही तात्कालिक रूप से उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, आयातकर्ताओं ने भी जहां प्रश्नाधीन उत्पाद के लिए समर्पित वर्गीकरण के अलावा अन्य वर्गीकरण का प्रयोग किया है वहीं डीजीसीआईएस परिशुद्ध वर्गीकरण/ समर्पित वर्गीकरण की रिपोर्ट करती है।
- (छ) यह आयात स्पष्टतः सीजन में उपलब्ध होता है। प्रथम तिमाही और द्वितीय तिमाही में आयात की मात्रा अधिक है जबकि तृतीय तिमाही और चतुर्थ तिमाही में आयात की मात्रा कम है। पहली दो तिमाहियों में आयात की मात्रा अधिक है क्योंकि इन दिनों में घरेलू उद्योग द्वारा मिथाइल एसिटोएसिटेट का उत्पादन कम किया गया इसलिए आयात अधिक हुए और अगली दो तिमाहियों में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन अधिक किया गया इसलिए आयात कम हुए।
- (ज) डाइकेटेन की क्षमता, इसकी खपत प्रणाली और बाजार कीमत आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी याचिकाकर्ता से मांगी जानी चाहिए।
- (झ) याचिकाकर्ता इस उत्पाद की देश में होने वाली मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं है।
- (ञ) कंपनी के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही में सुधार हुआ है। अत्यधिक हाल ही की अवधि में मालसूची में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। इसलिए, घरेलू उद्योग को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है।
- (ट) विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जन हित में नहीं होगा। पाइराजोलोन उद्योग जो मिथाइल एसिटोएसिटेट का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है उसे पहले से ही गंभीर क्षति हो रही है और पाइराजोलोन पर पाटन रोधी शुल्क अधिरोपित किया गया है। मिथाइल एसिटोएसिटेट पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से पाइराजोलोन उद्योग को और अधिक क्षति होने लगेगी जो सार्वजनिक/उपभोक्ताओं के हित में नहीं होगा।
- (ठ) याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन पत्र में समायोजन योजना में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- (ड) याचिकाकर्ता द्वारा सूचीबद्ध किये गये विचार वास्तविक समायोजन योजना नहीं है।

#### **v. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई प्रत्युक्ति**

#### **27. घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स ईएलपी एडवोकेट्स एंड सोलिसिटर्स द्वारा प्रस्तुत की गई प्रत्युक्ति**

- (क) हितबद्ध पक्षकारों का साक्ष्य की अपर्याप्तता के संबंध में किया गया दावा बिना किसी तथ्यपरक आधार पर है क्योंकि महानिदेशक (रक्षोपाय ने जांच शुरुआत के नोटिस से पहले विनिर्माण यूनिट का दौरा करके उत्पाद कर तथा अन्य संगत रिकार्डों सहित संपूर्ण सत्यापन और संगत आंकड़ों का संपूर्ण सत्यापन किया है।
- (ख) हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि आयात कीमत में अपेक्षित वृद्धि के बिना कच्चे माल की कीमत में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है, इस मामले में गलत है, ऐसा नहीं है और वास्तव में कच्चे माल की कीमतों में हुई वृद्धि के अनुरूप आयात कीमतों में वृद्धि नहीं हुई।
- (ग) यद्यपि आयातों के बाजार हिस्से में पर्याप्त वृद्धि हुई है, परंतु घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पिछले वर्ष गिरावट होकर यह केवल 28 प्रतिशत की रह गया। कीमतें कम करने के बावजूद घरेलू उद्योग आयातों की अननुपातिक कम कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में अक्षम रहा है जिसके कारण उत्पादन में कमी आई है।

- (घ) जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग द्वारा किये गये निवेश को अनपेक्षित विकास नहीं माना जा सकता है और यह कि लक्ष्मी आर्गेनिकस ने इस तथ्य को भली भांति जानते हुए कि उनका विगत उत्पादक अच्छी तरह से कार्यनिष्पादन नहीं कर रहा है, फिर भी इस उद्योग में जोखिम उठाने का साहस किया, यह उल्लेख किया जाता है कि निवेश को अन्य कई अनपेक्षित विकास को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए जैसे न्यून आयात कीमतें, विदेशी बाजारों में गिरावट और चीन में बेशी क्षमता का निर्माण यह सभी कारक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
- (ङ.) हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क गलत है कि घरेलू उद्योग कि मालसूची में दृष्टिगोचर संग्रहण नहीं हुआ है। संबद्ध वस्तु की मालसूची में सतत रूप से वृद्धि हुई है और स्पष्टतः न्यूनतर मालसूची को संवर्धित बारम्बारता और तथा घरेलू उद्योग द्वारा बंदी करने के लिए मजबूर किये जाने के लिए स्पष्टतः उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जिसके कारण न्यून उत्पादन हुआ।
- (च) उपलब्ध पक्षकारों के इस तर्क से कि बिक्रियों में वृद्धि के साथ-साथ घरेलू उद्योग के घाटे में भी वृद्धि हुई, यह संकेत मिलता है कि कई अन्य ऐसे कारक हैं जो घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता को प्रभावित कर रहे हैं, निराधार है क्योंकि घरेलू उद्योग को अपना माल उन कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिनसे उसको घाटा होगा। अतः, यह स्पष्ट है कि वर्ष 2011-12 में बिक्रियों में वृद्धि होने के बावजूद घरेलू उद्योग के घाटे में वृद्धि हुई है।
- (छ) हितबद्ध पक्षकारों ने डीओपी और पीएएन के अंतिम जांच परिणामों तथा वर्तमान जांच के बीच भिन्नता करने का प्रयास यह दावा करके किया है कि इन दोनों अनंतिम जांच परिणामों में पर्याप्त साक्ष्य प्रदान कराये गये हैं जबकि घरेलू उद्योग के दावे को प्रमाणित करने के लिए वर्तमान जांच में कोई साक्ष्य प्रदान नहीं कराया गया है। यह पूरी तरह से गलत है। घरेलू उद्योग ने यूरोपियन यूनियन की बाजार में खपत में अप्रत्याशित कमी के संबंध में आईसीआईएस रिपोर्टें तथा कैमिस्ट्री वर्ल्ड की रिपोर्टें पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग ने इस तथ्य पर विशेषीकृत रूप से संक्षेप में प्रकाश डालते हुए निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर पर भरोसा किया है कि चीन जन.गण के इस उत्पादक ने इस उत्पाद के लिए बेशी क्षमता संस्थापित की है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने आयात की न्यून कीमतों को अप्रत्याशित विकास के रूप में सिद्ध करने के लिए कच्चे माल की कीमतों और भारत में विचाराधीन उत्पाद की आयात की कीमतों के बीच तुलना की है।
- (ज) कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि आयातों की न्यून कीमत को अनपेक्षित विकास के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि न्यून आयात कीमतों से लागत में वृद्धि होना कीमत निग्रहण/अवमंदन की एक स्थिति है जो क्षति पैरामीटर हैं, न कि अनपेक्षित विकास। यह निराधार है। केवल एक पैरामीटर क्षति विश्लेषण के लिए प्रासंगिक होने का आशय यह नहीं होता है कि यह अनपेक्षित विकास नहीं हो सकता है। कीमत निग्रहण/अवमंदन को इस कारण से संगत आर्थिक प्रक्रिया के रूप में माना जा सकता है। वे आयात की मात्रा में अचानक होने वाली वृद्धि के संभावित कारणों के संकेतक हो सकते हैं। यह एक व्यापक रूप से ज्ञात आर्थिक सिद्धांत है कि उपभोक्ता की मांग में वृद्धि होने से कीमतों में विपर्यय अनुपात में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को निर्यातकों की कीमत निर्धारण नीतियों के बारे में ऐसी भविष्यवाणी करने का उत्तरदायित्व नहीं होता है जिससे कितने न्यून कीमत वाले आयातों में वृद्धि हुई है और यह अप्रत्याशित विकास बना हुआ है।
- (झ) हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव की बजह से घरेलू उद्योग को क्षति कारित हुई है और घरेलू उद्योग अपनी बिक्री उन कीमतों पर करने में सक्षम है जो आयात कीमतों से मेल खाती हो और जिसके द्वारा कोई अधोरदन या क्षति न की जाती है यह दोनों ही तर्क अस्वीकार कर दिये जाते हैं। घरेलू उद्योग की लागत में कच्चे माल की कीमतों का अनुपात उपलब्ध कराने में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिया गया अनुमान प्रमाणिक नहीं है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को आयात कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा अतः यद्यपि न्यूनतम अधोरदन हुआ है

तथापि भारी अधोबिक्रयण हुआ और घरेलू उद्योग बिक्री लागत से कम कीमतों पर अपनी बिक्री कर रही है।

- (ज) हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है कि रक्षोपाय के विगत मामलों के अनुसार जांच की न्यूनतम अवधि 36 महीने होनी चाहिए जो कि इस मामले में नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा अपने आंकड़ों में प्रदर्शित की गई क्षति इस मामले की शुरुआत करने के लिए पर्याप्त है और घरेलू उद्योग ने अब अद्यतन अवधि के लिए आंकड़े दायर कर दिये हैं जो तीन वर्षों से अधिक की अवधि को कवर करते हैं।
- (ट) हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किये गये आयात आंकड़ों की अविश्वनीयता के संबंध में तर्क प्रस्तुत किया है और डीजीसीआईएस आंकड़ों का उपयोग करने की सिफारिश की है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों ने बड़े सुविधाजनक ङग से इस तथ्य की अनदेखी कर दी है कि विचाराधीन उत्पाद एक जटिल रसायन उत्पाद है जिसका आयात कई एचएस वर्गीकरणों के अंतर्गत किया जाता है। इसके तहत आईबीआईएस से सौदावार आंकड़े प्राप्त करना उपयुक्त माना गया। महानिदेशक (रक्षोपाय) डीजीसीआईएस से सौदावार आंकड़े प्राप्त करने और उस पर विचार करने की मांग कर सकते हैं बशर्ते कि इन आंकड़ों से विचाराधीन उत्पाद से संबंधित आंकड़ों का अनुचित अपवर्जन न किया गया हो।
- (ठ) हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि आयातों में वृद्धि अचानक, तीव्र और भारी नहीं है और आयातों का विश्लेषण मौजूदा घरेलू उद्योग के प्रचालनों से काफी पहले से दीर्घतर समयवधि के लिए किया जाना चाहिए। यह तर्क दिया जाता है कि घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध करने के लिए कि आयातों में यह वृद्धि अचानक तीव्र और बहुत अधिक हुई है, रिकार्ड में पर्याप्त आंकड़े और विश्लेषण पहले ही उपलब्ध करा दिया है। क्षति अवधि के दौरान आयातों में समग्र रूप से तथा उत्पादन, बिक्री और मांग के संबंध में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2009-10 से आयातों का विश्लेषण करना, जब घरेलू उद्योग प्रचालन में नहीं था, न केवल गलत एवं अप्रतिनिधित्वपूर्ण है बल्कि यह विधि की अपेक्षाओं के विपरीत भी है।
- (ड) घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि आंकड़ों की तिमाही रूप से जांच करने से आयात मात्रा में गिरावट प्रदर्शित होती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अपने प्रचालनों की शुरुआत वर्ष 2010-11 में की थी, आयातों में गिरावट की प्रवृत्ति का संकेत वर्ष 2010-11 की चौथी तिमाही तक प्राप्त होता रहा और उपभोक्तागण आयातों के बजाय घरेलू उद्योग पर भरोसा करते रहे। तथापि, वर्ष 2010-11 की चौथी तिमाही के पश्चात से आयातों में अचानक, तीव्र एवं भारी वृद्धि हुई और यह आयात वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही में 66 प्रतिशत तक बढ़ गये और वर्ष 2010-11 की चौथी तिमाही की तुलना में वर्ष 2012-13 की दूसरी तिमाही में आयातों में 127 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई और इनमें वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही तक वृद्धि होती रही। आयातों की जांच चाहे तिमाही आधार पर या वार्षिक आधार पर की जाए परंतु आयातों में अचानक, तीव्र एवं भारी वृद्धि हुई है।
- (II) घरेलू उद्योग को एक विदेशी उत्पादक का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उसने अपने घरेलू प्रचालनों को बंद करने का प्रस्ताव किया है जिससे कि घरेलू उद्योग द्वारा सृजित प्रतिस्पर्धा का उपशमन कर दिया जाए और देश में आयातों को सुविधाजनक बना दिया जाए।
- (ण) हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के प्रचालन सुनियोजित हैं जिससे कि संसाधनों का उन उत्पादों को जिनमें सर्वाधिक लाभ होता है, आवंटित करके अधिकतम समग्र लाभ अर्जित करना है। इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आरोप रिकार्ड में उपलब्ध कराए गये आयात आंकड़ों के विरुद्ध है। पिछले तीन वर्षों से आयातों में सर्वाधिक वृद्धि हो रही है और आयातों में यह वृद्धि वित्तीय वर्ष की द्वितीय तिमाही में भी लगातार बनी हुई है। दूसरी ओर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष चतुर्थ तिमाही ने आयात न्यूनतम होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि कम कीमत वाले संवर्धित आयातों के कारण अपने भंडार को समाप्त करने के लिए घरेलू उद्योग को अपना माल तर्क संगत लागत से कम कीमत पर बेचने का आश्रय लेने को मजबूर किया जाता है।

- (त) हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि भारत में मांग घरेलू उद्योग की तुलना में अधिक है जिसके कारण मांग-आपूर्ति अंतराल होना लाजमी है जिससे आयात होना अनिवार्य हो गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग का इस समय केवल 40 प्रतिशत क्षमता उपयोग ही हो पाता है और हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क तभी सिद्ध हो सकता है जब घरेलू उद्योग अपनी 100 प्रतिशत क्षमता अर्जित कर ले और मांग पूरी न होने के कारण आयातों का अभी भी भारी मात्रा में प्रचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग का संयंत्र एक प्रेक्षण संयंत्र है और घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए अपनी क्षमताओं में और अधिक विस्तार करके देश में होने वाली संपूर्ण मांग को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम है बशर्ते कि उचित कीमत वाले आयात सुनिश्चित करने के लिए रक्षोपाय शुल्क का संरक्षण प्राप्त हो।
- (थ) हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि इस उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जन हित के विरुद्ध होगा। जहां तक अधोगामी उत्पादकों के भाग्य, खासकर फार्मास्युटिकल सेक्टर के भविष्य का, सवाल है यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि घरेलू उद्योग को बंद करने के लिए मजबूर किया जाता है तो समुद्रपारीय उत्पादकों से पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नहीं होगी और वे अपने बाजार हिस्से और प्रतिस्पर्धा की कमी का फायदा उठाने के लिए अपनी कीमतें बढ़ाना शुरू कर देंगे। अतः, आत्मनिर्भर तथा सुदृढ़ घरेलू उद्योग की मौजूदगी अधोगामी उत्पादकों के सार्वजनिक हितों के अनुरूप होगी और इससे विदेशी उत्पादक भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के अभाव के कारण उसका शोषण करने से वंचित हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त कई अधोगामी फार्मास्युटिकल उत्पादक निर्यातोन्मुखी उत्पादक हैं जो अनन्य रूप से निर्यात करने के लिए स्थापित किये गये हैं और वे भारत की घरेलू मांग को पूरा नहीं करते हैं। जहां तक भारत में पाइराजोलोन के उत्पादकों को होने वाली संभावित क्षति का संबंध है, जैसा कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने चिंता जताई है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधोगामी उत्पाद के पाटन के कारण अधोगामी उत्पादकों को होने वाली क्षति के लिए इस विचाराधीन उत्पाद पर उद्ग्रहण किये जा रहे रक्षोपाय शुल्क को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पाइराजोलोन उत्पादक एमएएई पर रक्षोपाय शुल्क न लगा होने के बावजूद गंभीर क्षति का सामना पहले से ही कर रहे हैं जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि इन उत्पादकों के लिए चिंता का कारण अपर्याप्त पाटनरोधी शुल्क है न कि इस विचाराधीन उत्पाद पर उद्ग्रहण किया जा रहा शुल्क।
- (द) हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने अपेक्षित समायोजन योजना प्रदान नहीं कराई है और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई समायोजन के लिए अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आयात प्रतिस्पर्धा से सकारात्मक समायोजन करने के लिए नियोजित प्रयासों का विस्तृत विवरण समायोजन योजना में प्रस्तुत किया गया है जिसे घरेलू उद्योग की 2-3 वर्ष की अवधि में प्रभावित करने की योजना है। लागत कम करने वाले विशिष्ट उपायों के संबंध में किये गये विशिष्ट प्रयासों का उल्लेख किया गया है और घरेलू उद्योग ने खरीदी गई मशीनरी का उन्नयन करने और उसमें वृद्धि करने तथा उसका उन्नयन करके उसे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों तक लाने के लिए भारी निवेश किया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने रक्षोपाय शुल्क नियमावली की अपेक्षाओं के अनुरूप सम्पूर्ण संपुष्टता में गोपनीयता का अनुरोध किया है।
- (ध) कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कार्य कारण संबंध का कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि समवर्धित आयातों तथा घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के बीच प्रत्यक्ष कारणात्मक संबंध है। संबद्ध वस्तुओं की बिक्री आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करके की जा रही है। आयातों की उतराई कीमत तर्क संगत लागत से बहुत कम है और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत का निर्धारण आयात कीमत द्वारा किया जाता है उसके परिणामस्वरूप कम कीमत वाले आयातों की सतत मौजूदगी के कारण उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री, लाभ, निवेश पर अर्जन और नकदी प्रवाह में गिरावट आ रही है।

# VI. निर्यातकर्ताओं द्वारा की गई प्रत्युक्ति

## 28. मैसर्स ईस्टमैन कैमिकल कंपनी की ओर से मैसर्स एजेडबी एंड पार्टनर्स द्वारा किया गया प्रत्युक्ति प्रस्तुतिकरण

- (क) इन प्रत्युक्ति प्रस्तुतिकरणों को 12 जुलाई, 2013 को दिये गये लिखित प्रस्तुतिकरणों के साथ मिलाकर पढ़ा जा सकता है।
- (ख) घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में उल्लिखित अधिकांश तर्कों का ही बार-बार उल्लेख किया है और अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। घरेलू उद्योग ने यूरोप की बाजारों में मंदी के परिणामस्वरूप खपत में भारी अप्रत्याशित गिरावट, चीन जन गण में अतिरिक्त क्षमताओं और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद आयातों की कीमतों में अनपेक्षित रूप से कमी होना जैसी तीन घटनाओं को अनपेक्षित घटनाओं के रूप में उद्धृत किया है। तथापि इन तीन घटनाओं में से कोई भी घटना सही एवं ऐसी नहीं है जिसे अनपेक्षित के रूप में माना जा सके।
- (ग) घरेलू उद्योग ने एक आन लाइन रिपोर्ट का उल्लेख किया है जो वर्ष 2008 में आये वित्तीय संकट से उत्पन्न मंदी के प्रभावों के कारण यूरोपियन यूनियन ने सामान्य रसायनिक उत्पादों की मांग में गिरावट के बारे में वर्णन करती है। यदि यह परिकल्पना भी कर ली जाती है कि यूरोपियन यूनियन में रसायनों की मांग में गिरावट आयी है तथापि यह गिरावट घरेलू उद्योग को अच्छी तरह से ज्ञात एवं पूर्वाभाषित होनी चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग ने इस बाजार में वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के प्रारंभ से दो वर्ष पश्चात से अधिक की अवधि के बाद वर्ष 2010 में प्रवेश किया। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा की गई रिपोर्ट न तो यह उद्घाटित करती है कि आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप यूरोपियन यूनियन के बाजारों में मिथाइल एसिटोएसिटेट की मांग में कमी आई है और रिपोर्ट में न ही इस बात का उल्लेख है कि इस मंदी के कारण भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों में मिथाइल एसिटोएसिटेट के निर्यातों में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत, रिपोर्ट से यह संकेत मिलता है कि रसायनिक उत्पादों की कम मांग के कारण अधिकांश उत्पादकों ने अपने उत्पादन में कटौती कर दी। इससे घरेलू उद्योग के तर्क का विरोध होता है।
- (घ) घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि जिन्हुआ फार्मास्युटिकल्स (शौगैंग) कंपनी लिमिटेड और क्विंगडाओ डबल-पीच स्पेशलिटी कैमिकल (ग्रुप) कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान क्षमता संवर्धन करना अनपेक्षित घटना थी और इसके कारण भारत को संवर्धित निर्यात होना अनिवार्य हो गया था। तथापि यह आकलन करना गलत है कि यह अनपेक्षित घटनाएं थीं और इनसे भारत को मिथाइल एसिटोएसिटेट के आयातों में अचानक, तीव्र और अत्यधिक बढ़ोतरी होना अनिवार्य हो गया। इसके विपरीत, बाजार में वर्ष 2010 में नवागन्तुक होने के कारण घरेलू उद्योग को ज्ञात होना चाहिए था कि इसका संभावित प्रतिस्पर्धी कौन होगा।
- (ङ.) जहां तक कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद आयात की कीमतें कम होने के संबंध में घरेलू उद्योग का दावा है, यह कहा जा सकता है कि यह आकलन गलत है क्योंकि इनपुट लागत अंतिम उत्पाद की लागत को प्रभावित करती है और वह संभावित अनुपात जिसमें अंतिम उत्पाद की लागत में परिवर्तन आ सकता है परिवर्तन अनुपात पर निर्भर करता है। यह कल्पना करना सही नहीं है कि अंतिम उत्पाद की कीमतों में भी उसी सीमा तक वृद्धि होगी जिस सीमा तक वृद्धि कच्चे माल की कीमतों में हुई है।
- (च) घरेलू उद्योग द्वारा अप्रैल-जुलाई, 2013 के लिए प्रस्तुत किये गये अतिरिक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि इस अवधि के दौरान आयातों में गिरावट आयी है क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है।
- (छ) आयातों की प्रवृत्ति से तुलना करने पर घरेलू उद्योग का उत्पादन जांच की अवधि के दौरान अधिकांश समय तक आयातों में प्रवृत्ति के ऊपर ही बना रहा और अत्यधिक हाल की अवधि में भी यह निरंतर आयातों से ऊपर ही बना हुआ है।
- (ज) घरेलू उद्योग ने अपने दावे को क्षति पर और आयातों की संगत रूप से न्यूनतर कीमतों के साथ कारणात्मक संबंध से जोड़ा है। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के अनुसार आयात कीमतें जांच की अवधि के अधिकांश समय के लिए घरेलू उद्योग की कीमतों से अधिक ही बनी रही हैं।

- (झ) घरेलू उद्योग यह निश्चय पूर्वक कहता है कि आयातों में वृद्धि ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी ला दी और इसके कारण ही उत्पादन और क्षमता उपयोग में भी कमी आयी। तथापि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में, यह बाजार में संगत रूप से नवागन्तुक होने के बावजूद, जांच की अवधि में पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित हुई है। केवल यह कथन कि आयातों में तथाकथित वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और वह भी अकाट्य तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कारणात्मक संबंध स्थापित किये बिना, गलत है तथा बिना किसी सकारात्मक साक्ष्य के घरेलू उद्योग हानि के कारणों का उल्लेख नहीं कर सकता है।
- (ज) आयातों में उतार चढ़ाव होना अनिवार्य है। पहली और दूसरी तिमाही में आयातों की मात्रा अधिक है वहीं तीसरी और चौथी तिमाही में आयातों की मात्रा कम है। इसीलिए तीसरी और चौथी तिमाही में जब आयातों की मात्रा कम थी तब घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में अचानक वृद्धि आ जानी चाहिए थी। ऐसा इसलिए कि पहली दो तिमाहियों के दौरान घरेलू उद्योग में मोनोमिथाइल एसिटोएसिटेट (एमएमएए) के विनिर्माण में अपनी सीमित क्षमता का उपयोग किया होगा जो मिथाइल एसिटोएसिटेट की बिक्री से अधिक लाभ प्रदान करता है। चूंकि मोनोमिथाइली एसिटोएसिटेट की मांग सीजनल होती है और यह पहले दो तिमाहियों तक ही रहती है। उसके बाद घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन सुविधाओं का उपयोग मिथाइल एसिटोएसिटेट का उत्पादन करने में लगाता है। अतः घरेलू उद्योग का यह अभिकथन कि आयात घरेलू उद्योग को मिथाइल एसिटोएसिटेट की भारतीय बाजार से विस्थापित कर रहे हैं, गलत है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग को होने वाली किसी भी क्षति, यदि कोई, के लिए इसकी संस्थापित क्षमता का चुनिंदा उपयोग करने को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जिसका उपयोग मिथाइल एसिटोएसिटेट और मोनोमिथाइल एसिटोएसिटेट का उत्पादन करने के लिए अदल-बदल कर किया जा सकता है।
- (ट) सांविधिक अपेक्षा होने के बावजूद घरेलू उद्योग, घरेलू उद्योग प्रश्नावली में अपना प्रत्युत्तर देने में असफल रहा है।

#### VII. आयातकर्ता/ उपयोक्ता उद्योग द्वारा प्रत्युक्ति

#### 29. मैसर्स टीपीएम कंसलटेंट्स द्वारा मैसर्स अरबिन्दो फार्मा, सी जे शाह एंड कंपनी, नूतन डाईकैम, प्राइमा कैमिकल्स और पोलिगन कैमिकल्स की ओर से किया गया प्रत्युक्ति प्रस्तुतिकरण

- (क) इस कारण से एक लम्बी अवधि पर विचार किया जाना अपेक्षित है कि घरेलू उद्योग की वर्ष 2010-11 में पूर्ण अवस्थिति नहीं थी।
- (ख) महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा सुनवाई के समय विशिष्ट अनुदेश दिये जाने के बावजूद याचिकाकर्ता ने अप्रैल-जून, 2013 की अवधि के लिए संगत सूचना हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने को अधिमानता प्रदान नहीं की। तथापि, यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने महानिदेशक को अद्यतन सूचना 5 सितम्बर, 2013 को ही प्रदान की और उक्त जानकारी नियमों के अंतर्गत गोपनीयता के प्रावधानों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान कराने में असमर्थ रहा है। इस तथ्य पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए कि हितबद्ध पक्षकारों ने विशेष रूप से यह तर्क दिया कि लंबी अवधि के लिए आंकड़े प्रदान कराये जाने चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों को महानिदेशक के निदेश के अनुसार प्रत्युक्ति दायर करने की अंतिम तारीख से एक दिन पहले 10 सितम्बर को आंकड़े प्राप्त हुए। चूंकि हितबद्ध पक्षकारों को अधिक समय उपलब्ध नहीं था इसलिए इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों के संबंध में पर्याप्त प्रस्तुतिकरण नहीं किया जा सका। तथापि, उनके द्वारा की गई टिप्पणियों को संक्षेप में निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- (ग) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये लिखित प्रस्तुतिकरण में अप्रैल-जून, 2013 की अवधि के लिए संगत सूचना नहीं है। अतः यह एक ऐसी स्थिति है जहां याचिकाकर्ता ने केवल चुनिंदा जानकारी उपलब्ध करायी है और महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा सुनवाई के दौरान दिये गये अनुदेशों की स्पष्ट अवहेलना की है।
- (घ) याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा यह दावा किया गया है कि उसने अपना वाणिज्यिक उत्पादन मई, 2010 में प्रारंभ किया था फिर भी उसने वर्ष 2010-11 की तीन तिमाहियों के लिए तिमाही वार आंकड़ों को उपलब्ध नहीं

- कराया है। और न ही याचिकाकर्ता ने इस अंतराल को सुधारने का कोई प्रयास किया हालांकि सार्वजनिक सुनवाई के दौरान इसका उल्लेख किया गया था। यह स्पष्टतः कदाशयता है।
- (ड.) याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों की अनदेखी करने और आईबीआईएस आंकड़ों को अपनाने का कोई कारण बताया है। याचिका ने इस मुद्दे के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस मामले में आईबीआईएस सूचना का उपयोग करना निम्नलिखित कारणों से उचित नहीं है। (1) आईबीआईएस ने कई सौदों का उल्लेख किया है जिन्हें दोहराया गया है (2) डीजीसीआईएंडएस आंकड़ें उपलब्ध होने पर उसे ही अधिमानता दी जानी चाहिए थी।
- (च) आयात प्रणाली याचिकाकर्ता द्वारा मिथाइल एसिटोएसिटेट के उत्पादन के संबंधी व्यवहार को स्पष्टतः प्रतिविम्बित करती है।
- (छ) याचिकाकर्ता कई उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए उसी मध्यवर्ती डाइकेटिन का उपयोग करता है और इसीलिए जब मोनोमिथाइल एसिटोएसिटेट का उत्पादन चरण सीमा पर होता है तो मिथाइल एसिटोएसिटेट के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है।
- (ज) याचिकाकर्ता ने महानिदेशक (रक्षोपाय) से यह निग्रहण कर लिया कि इस उत्पाद की एक विशिष्ट सीजन में अधिक महत्ता होती है क्योंकि उस विशिष्ट सीजन में मोनोमिथाइल एसिटोएसिटेट का उत्पादन किया जाता है। मोनोमिथाइल एसिटोएसिटेट की जनवरी से जून के दौरान भारी सीजनल मांग होती है इस कारण इस अवधि में मिथाइल एसिटोएसिटेट का उत्पादन कम रहता है इसके अतिरिक्त जुलाई से दिसम्बर माह में जब मोनोमिथाइल एसिटोएसिटेट की मांग कम हो जाती है तो याचिकाकर्ता मिथाइल एसिटोएसिटेट का उत्पादन करना बढ़ा देता है। इसके परिणाम स्वरूप मिथाइल एसिटोएसिटेट के आयात वर्ष के पहले छह माह के दौरान अधिक होते हैं और उसके बाद बाले छह माह के दौरान कम रहते हैं।
- (झ) याचिकाकर्ता की क्षमता 4950 मी.टन की है जो देश में इस उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए सकल रूप से अपर्याप्त है। विगत में मांग में हुई वृद्धि को देखते हुए यह अनुमान लगाया जाता है कि चालू वर्ष के दौरान लगभग 7000 मी.टन की मांग होगी और यदि अगले वर्ष के दौरान वर्ष 2014-15 में जब रक्षोपाय शुल्क प्रचालनात्मक किये जाने का प्रस्ताव है यह मांग बढ़कर 8500 मी.टन हो जायेगी। इस प्रकार इस उत्पाद की मांग लगभग 8500 मी.टन अर्थात् संस्थापित क्षमता की 170 प्रतिशत और प्रस्तावित रक्षोपाय शुल्क प्रचालनात्मक होने पर यह मांग याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्तव्य उत्पादन का 215 प्रतिशत होगी।
- (ञ) वर्ष 2012-13 की तीसरी तिमाही में याचिकाकर्ता के उत्पादन को नुकसान हुआ क्योंकि इस अवधि में याचिकाकर्ता ने कुछ पूंजीगत व्यय अपने हाथ में ले लिया था जिसके कारण इस तिमाही में उत्पादन में व्यवधान उत्पन्न हो गया। चूंकि मिथाइल एसिटोएसिटेट का उत्पादन याचिकाकर्ता द्वारा कम किया गया था इसलिए उपभोक्ताओं को इस उत्पाद के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने हेतु आयातों पर निर्भर होना पड़ा।
- (ट) वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही में याचिकाकर्ता की बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग आदि में सुधार प्रदर्शित होता है। याचिकाकर्ता ने अप्रैल-जून, 2013 के लिए क्षति से संबंधित कोई सूचना प्रदान नहीं की है। वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही में बाजार हिस्से में सुधार हुआ है। मालसूची में गिरावट आयी है। याचिकाकर्ता द्वारा सहन किये गये घाटे में भी वर्ष 2012-13 में गिरावट आयी है।
- (ठ) रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण उपयोक्ता उद्योग अर्थात् पाइराजोलोन और फार्मा उद्योग के हितों के विपरीत है। पाइराजोलोन उद्योग जो इस समय वित्तीय घाटा सहन कर रहा है कच्चे माल की लागत में हुई अपनी बढ़ोतरी को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में असमर्थ रहेगा। इस उद्योग को चीन से पाइराजोलोन के आयातों और पाटन के कारण भारी क्षति हो रही है।
- (ड) मिथाइल एसिटोएसिटेट पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण करने से फार्मा उद्योग की विनिर्माण प्रक्रिया में परिवर्तन आ जायेगा और यह मिथाइल एसिटोएसिटेट के पीएचपीजी डेन लवण का उत्पादन करने के बजाय पीएचपीजी डेन लवण के आयातों पर निर्भर हो जायेगी।



**30. भारत में संबद्ध वस्तु का संवर्धित आयात**

रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण केवल तभी किया जा सकता है जब जांच से यह सिद्ध हो जाए कि विचाराधीन उत्पाद का भारत को इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी दशाओं में आयात किया जा रहा है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति कारित की जा रही है और गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो रही है। तथापि, वर्तमान मामले में इन पूर्वोक्ताहरण शर्तों को पूरा नहीं किया गया है इसलिए रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण नहीं किया जाना चाहिए।

क. उपर्युक्त की अनुप्रयोज्यता के लिए निम्नलिखित मामलों का उल्लेख किया गया है:-

- (i) अर्जेंटीना-फुटवियर मामले में डब्ल्यूटीओ अपीलरीय निकाय (डब्ल्यूटी/डीएस 121/एबी/आर दिनांक 14 दिसम्बर, 1999)
- (ii) यूएस-लाइन पाइप मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल (डब्ल्यूटी/ डीएस 202/आर दिनांक 29 अक्टूबर, 2001)
31. ऊपर उद्धृत किये गये मामले में सूचीबद्ध शर्तों को वर्तमान मामले में पूरा किया गया है और इसलिए रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाना चाहिए।
  - (i) याचिकाकर्ता ने महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा विशिष्ट अनुदेश दिये जाने के बावजूद अप्रैल-जून, 2013 की अवधि के लिए आंकड़े प्रदान नहीं कराये हैं। हमने यह स्थापित किया है कि इस अवधि में आयातों में भारी गिरावट आयी है।
  - (ii) याचिकाकर्ता ने वर्ष 2009-10 की अवधि के लिए आयात आंकड़े शामिल नहीं किये क्योंकि इससे यह स्पष्ट प्रदर्शित होता है कि आयातों में गिरावट आयी है।
  - (iii) स्वीकार रूप से, याचिकाकर्ता ने वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष 2010-11 में प्रारंभ किया जिसके परिणामस्वरूप उस वर्ष आयातों में गिरावट आयी। वर्ष 2012-13 में आयातों में कुछ वृद्धि विगत वर्ष के दौरान विदेशी उत्पादकों द्वारा घाटे की मात्रा की प्रतिक्रिया स्वरूप और याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2012-13 की तीसरी तिमाही में उत्पादन बंद कर देने के कारण हुई है। चूंकि याचिकाकर्ता ने अपना उत्पादन बंद कर दिया था इसलिए मांग को आयात द्वारा पूरा किया गया।
32. आयात प्रवृत्ति आयात में अचानक, तीव्र एवं अभिनव वृद्धि प्रदर्शित नहीं होती है। यह केवल पिछले वर्ष खोई गई बाजार की स्थिति में सुधार प्रदर्शित करती है और यह दर्शाती है कि यह घरेलू उद्योग द्वारा छोड़ी गई मांग को पूरा करने के लिए किया गया। यह कल्पना करते हुए कि वर्ष 2009-10 में घरेलू उद्योग नहीं था और इस कारण इस अवधि के दौरान आयातों में अधिकता आई और तब यह प्रदर्शित करती है कि आयात वर्ष 2010-11 में कम रहे उनकी याचिकाकर्ता ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया था और इस अवधि में आयातों का भारी मात्रा में विस्थापन कर दिया था।

**अनपेक्षित विकास**

33. महानिदेशक ने इन सभी मामलों में अनपेक्षित विकास की जांच की है इसके अतिरिक्त महानिदेशक ने सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर इन सभी मामलों में अनपेक्षित विकास को स्पष्टता सिद्ध किया। वर्तमान मामले में अनपेक्षित विकास स्थापित करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया है। यह तथ्य मात्र एक अभिकथन है कि विदेशी उत्पादकों ने अपनी लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं की है जो एक अनपेक्षित विकास नहीं बनता है।

**गंभीर क्षति और गंभीर क्षति की चुनौती**

34. वर्ष 2012-13 में उत्पादन में गिरावट याचिकाकर्ता द्वारा कुछ पूंजीगत व्यय अपने हाथ में लिये जाने के कारण उत्पादन रोके जाने की वजह से आयी है।
35. वर्ष 2012-13 में क्षमता उपयोग में गिरावट याचिकाकर्ता द्वारा कुछ पूंजीगत व्यय अपने हाथ में लिये जाने के कारण उत्पादन रोके जाने की वजह से आयी है।
  1. वर्ष 2012-13 में घरेलू बिक्री में गिरावट याचिकाकर्ता द्वारा कुछ पूंजीगत व्यय अपने हाथ में लिये जाने के कारण उत्पादन रोके जाने की वजह से आयी है।

2. रोजगार में वृद्धि के कारण कोई क्षति स्थापित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त उत्पादन में गिरावट पूंजीगत व्यय अपने हाथ में लिये जाने के कारण उत्पादन रोके जाने की वजह से आयी है।
3. घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री में वृद्धि मांग में होने वाली वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि याचिकाकर्ता द्वारा कुछ पूंजीगत व्यय अपने हाथ में लिये जाने के कारण उत्पादन रोके जाने की वजह से हुई है। इसके अतिरिक्त, इस उत्पाद की मांग घरेलू उद्योग की क्षमता की तुलना में अधिक है और इसलिए मांग को आयात से पूरा किया गया।
4. वर्ष 2012-13 में बाजार हिस्से में गिरावट याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2012-13 की तीसरी तिमाही में उत्पादन रोके जाने के कारण आयी है। चूंकि याचिकाकर्ता उपभोक्ताओं की मांग को पूरे करने की स्थिति में नहीं था इसलिए उसे आयातों द्वारा पूरा किया गया।
36. इसके विपरीत जब वर्ष 2012-13 में तथाकथित वृद्धि हुई तब घरेलू उद्योग को हुई क्षति कम हो गयी इसके अतिरिक्त जब वर्ष 2011-12 में आयातों में वृद्धि नहीं हुई और घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्रियां और क्षमता उपयोग सर्वाधिक रहा तब घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई क्षति, व्यंग्यात्मक रूप से सर्वाधिक रही। एक विदेशी उत्पादक द्वारा याचिकाकर्ता को अपना व्यवसाय बंद कर दिये जाने का सुझाव देने का आशय नियमों के आशय के अंतर्गत गंभीर क्षति की चुनौती देना नहीं है। यह सामान्यतः एक व्यवसाय प्रस्ताव है याचिकाकर्ता को वर्ष 2010-11 में जब उसके आयात की मात्रा सबसे कम थी तब उसे वित्तीय घाटा हुआ। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011-12 में जब आयात समान स्तर पर बने रहे और याचिकाकर्ता के उत्पादन और बिक्री में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई तब उसे भारी घाटा सहन करना पड़ा। अतः याचिकाकर्ता को तब भी वित्तीय घाटा सहन करना पड़ रहा था जब आयात न्यून स्तर पर थे। यह स्पष्टतः दर्शाता है कि याचिकाकर्ता के समक्ष कतिपय अन्य मुद्दे मौजूद थे जिसके कारण याचिकाकर्ता को अपने व्यवसाय की घाटे में बिक्री करने और उत्पादन बंद करने पर मजबूर होना पड़ा।
37. जहां तक घरेलू उद्योग के इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि चीन जन.गण में कई संयंत्र स्थापित हो गये हैं और यूएस एवं यूके की भारी क्षमता से निरंतर क्षति होगी, यह केवल एक अभिकथन है और इसका साक्ष्यों द्वारा समर्थन नहीं किया जा सकता है।

#### कारणात्मक संबंध

38. संवर्धित आयातों और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। आयात केवल इस कारण किये गये कि घरेलू उद्योग ने अपनी मध्यवर्ती क्षमता का विपथन अन्य उत्पादों के लिए करने का निश्चय कर लिया। चूंकि याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध मध्यवर्ती पर्याप्त मात्रा में नहीं था इसलिए इसने अनुकरण किया कि याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन अधिक नहीं कर सका।

#### समायोजन योजना

39. याचिकाकर्ता ने इस संबंध में कोई ठोस सूचना उपलब्ध नहीं कराई है और इसलिए कोई अन्य प्रत्युत्तर अपेक्षित नहीं है।

#### जन हित

40. लिखित प्रस्तुतिकरणों पर भरोसा किया गया।

#### जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़े

41. विचाराधीन उत्पाद के लिए अप्रैल, 2013 से जुलाई, 2013 के लिए महानिदेशक (रक्षोपाय) के निदेशों पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराये गये अद्यतन आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि:-
  1. विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही तथा जुलाई, 2013 की अद्यतन अवधि में आयातों में गिरावट और आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आयी है।
  2. याचिकाकर्ता के उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सा, रोजगार, उत्पादकता और उत्पादन क्षमता में वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही और उसके पश्चात जुलाई, 2013 में भारी वृद्धि हुई है। उसी अवधि के दौरान मालसूची में गिरावट आयी। उत्पाद की मांग में भारी वृद्धि हुई।

3. याचिकाकर्ता द्वारा किये गये दावे के अनुसार वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही में मांग 7700 मी.टन के बराबर थी जो जुलाई, 2013 में बढ़कर 9100 मी.टन से अधिक हो गयी। इसके विपरीत याचिकाकर्ता की क्षमता केवल 4950 मी.टन ही थी। अतः याचिकाकर्ता की क्षमता देश में इस उत्पाद की मांग की तुलना में बहुत कम थी। मांग एवं आपूर्ति के बीच भारी एवं बढ़ते अंतराल को देखते हुए यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता देश में इस उत्पाद की मांग को किसी भी हाल में पूरा करने में असमर्थ था और रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जन हित में नहीं होगा।
42. मोनोमिथाइल एसिटोएसिटेट का सीजनल उत्पादन होने के कारण इस उत्पाद की सीजनल मांग होती है। लिखित प्रस्तुतिकरण में की गई प्रस्तुति के अनुसार, याचिकाकर्ता कई उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए एक ही मध्यवर्ती डाइकिटेन का उपयोग करता है और इसलिए जब मोनोमिथाइल एसिटोएसिटेट का उत्पादन चरम सीमा पर होता है तब मिथाइल एसिटोएसिटेट का उत्पादन कम हो जाता है। रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण करने से उपभोक्ताओं पर भारी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। याचिकाकर्ता देश में विचाराधीन उत्पाद की मांग को किसी भी हाल में पूरा करने में असमर्थ था और इसलिए आयात जरूरी हो गये थे और इस कारण पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करना किसी भी रूप में जनहित में नहीं होगा।
43. **चीन जन.गण. के निर्यातकों की ओर से मैसर्स डब्ल्यूटीसी कंसलटेंट्स द्वारा की गई प्रत्युक्ति** चीन जन.गण के निर्यातकों की ओर से पेश हुए मैसर्स डब्ल्यूटीसी कंसलटेंट्स ने सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात केवल लिखित प्रस्तुतिकरण किया परंतु कोई प्रत्युक्ति दायर नहीं की।

#### VIII. जांच एवं निष्कर्ष

44. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस मामले के रिकार्डों, घरेलू उत्पादकों प्रयोक्ताओं/आयातकों, निर्यातकों और निर्यातक राष्ट्रों द्वारा दायर किये गये प्रत्युत्तरों की सावधानीपूर्वक जांच की है। विभिन्न पक्षकारों द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरणों और उनसे उत्पन्न मुद्दों का इस जांच परिणाम में उचित स्थानों में निराकरण कर दिया गया है।
45. सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने का वर्णन करती है। धारा 8ख (1) में केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का प्रावधान है जब उस वस्तु का भारत में आयात इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में किया जा रहा हो जिससे कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गयी हो।
46. सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और उसका आकलन) नियमावली, 1997 में जांच को शासित करने वाले तरीके और सिद्धांतों का प्रावधान है।
47. यह जांच उक्त नियमों के अनुसार आयोजित की गई है और इस अधिसूचना के जरिए अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किये गये हैं।

#### (क) विचाराधीन उत्पाद

48. वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद मिथाइल एसिटोएसिटेट है (जिसे एमएए/एमएई/एएएमई के नाम से भी जाना जाता है) जो ईस्टर या एसिटो-एसिटेट ईस्टर आधारित एक रसायन यौगिक होता है जो हाइड्रोआक्सिल यौगिकों जैसे फिनोल या अल्कोहल की आक्सो एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके अवकलित किया जाता है इस उत्पाद के संबंध में इसका रसायनिक फार्मूला  $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_3$  होता है। इस उत्पाद को मिथाइल-3-कीटोव्यूटाइरेट, मिथाइल एसिटोइलेसिटेट, मिथाइल-3 आक्जोब्यूटानोएट, मिथाइल एसिटोन कारबाक्सीलेट, मिथाइल-3-आक्जोब्यूटाइरेट, एसिटोएसिटिक मिथाइल ईस्टर, एमएएई के नाम से भी जाना जाता है।
49. मिथाइल एसिटोएसिटेट को सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अध्याय-29 के सीमा शुल्क प्रशुल्क शीर्षक 29183040 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी रूप में वर्तमान जांच के दायरे में बाध्यकारी नहीं है। किसी भी

हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है। इसीलिए यह संपुष्टि की जाती है कि विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अध्याय-29 के सीमा शुल्क प्रशुल्क शीर्षक 29183040 के अंतर्गत आने वाला 'मिथाइल एसिटोएसिटेट' हैं। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा जांच की कार्यवाई के दौरान आयातित मिथाइल एसिटोएसिटेट और घरेलू रूप से उत्पादित मिथाइल एसिटोएसिटेट के बीच उत्पादन प्रक्रिया, गुणधर्म और अंतिम प्रयोग के बीच कोई अंतर के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है अतः यह भी धारित किया जाता है कि घरेलू रूप से उत्पादित मिथाइल एसिटोएसिटेट आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में समान या प्रत्यक्षता प्रतिस्पर्धी दायरे के अंतर्गत आता है और यह कि घरेलू रूप से उत्पादित मिथाइल एसिटोएसिटेट सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 2 (ड.) के आशय के अंतर्गत आयातित मिथाइल एसिटोएसिटेट का समान उत्पाद है।

**(ख) घरेलू उद्योग**

50. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8(ख) (6) (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नवत परिभाषित किया गया है-

(ख) "घरेलू उद्योग" का आशय

- (i) भारत में समान वस्तु अथवा प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी वस्तु के समग्र रूप से उत्पादनकर्ताओं; अथवा
  - (ii) उन उत्पादनकर्ताओं से है जिनका समान वस्तु या भारत में प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी वस्तु का सामूहिक उत्पादन भारत में उक्त वस्तु के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है।
51. इस मामले में मैसर्स लक्ष्मी आर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई ही केवल ऐसा आवेदक है जो घरेलू उद्योग बनता है। मैसर्स लक्ष्मी आर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दावा किया है कि उनका उत्पादन देश में मिथाइल एसिटोएसिटेट के कुल उत्पादन का 100 प्रतिशत उत्पादन होता है। अतः आवेदक उत्पादक का सामूहिक उत्पादन भारत में मिथाइल एसिटोएसिटेट के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है। इसके अतिरिक्त किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा आवेदनकर्ता के घरेलू उद्योग के बनने के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया गया है। अतः, यह धारित किया जाता है कि आवेदक घरेलू उत्पादक सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(6)(ख)(i) में यथापरिभाषित और उसके आशय के अंतर्गत अपेक्षित घरेलू उद्योग बनता है और उसका प्रतिनिधित्व करता है।

**(ग) सूचना का स्रोत**

52. विचाराधीन उत्पाद के लिए आयात आंकड़े वर्ष 2010-11 की प्रथम तिमाही से जुलाई 2013-2014 तक की अवधि के लिए आवेदक द्वारा यथाप्रदत्त (खेपवार) आईबीआईएस से लिए गए हैं क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि सम्बद्ध वस्तु का आयात अन्य विभिन्न वर्गीकरणों के अंतर्गत भी किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में, केवल उन्हीं लेन-देनवार आंकड़ों पर विचार करना पड़ा जो केवल आईबीआईएस आंकड़ों में उपलब्ध है। अतः आईबीआईएस आयात आंकड़ों को लिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि के लिए अन्य रक्षोपाय आर्थिक पैरामीटर से संबंधित आंकड़ों का याचिकाकर्ता के केन्द्रीय उत्पाद कर रिकार्ड से यथाअपेक्षित सीमा तक आवेदक की यूनिट का स्थल पर जाकर सत्यापन करके प्रमाणन किया गया और जांच की अवधि के लिए इस तरह स्थापित आंकड़ों को क्षति विश्लेषण के लिए विचारार्थ लिया गया है। वर्ष 2013-14 की प्रथम तिमाही और जुलाई 2013 तक के लिए आंकड़े सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। घरेलू उद्योग ने तीन वर्षों या उससे अधिक की अवधि के लिए आंकड़े दिनांक 6.9.1997 के व्यापार नोटिस संख्या एसजी/टीएन/1/97 के तहत रक्षोपाय शुल्क नियमावली, 1997 के नियम 5 (2) के अंतर्गत महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा निर्धारित स्वरूप और ङग में प्रदान कराये हैं। लागत आंकड़ें और क्षति मार्जिन का परिकलन याचिकाकर्ता द्वारा एक स्वतंत्र सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित रूप में उपलब्ध कराये गये हैं।

**(घ) जांच की अवधि (पीओआई)**

53. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 में विशेष रूप से 'जांच की अवधि' अथवा रक्षोपाय जांच के लिए विचार किये जाने हेतु निम्नतम अवधि को परिभाषित नहीं किया गया है। रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार में जांच की अवधि का चयन करने के लिए किसी विशिष्ट प्रावधान या दिशानिर्देश का उल्लेख नहीं है। तथापि, जांच की अवधि के मुद्दे पर कोरिया के खिलाफ यूएस-लाइन पाइप केस में पैनल निष्कर्षों में विस्तार से विचार किया गया है। इस मामले में पैनल ने यह निर्धारित किया है कि आयातकर्ता सदस्य के जांच प्राधिकारी के विवेक के अनुसार "जांच की अवधि की दीर्घता" और इसकी "समाप्ति" निर्धारित होगी।

"हम नोट करते हैं कि इस करार में ऐसी किसी व्यवस्था का उल्लेख नहीं है कि रक्षोपाय जांच में जांच की अवधि कितनी लम्बी होगी न ही कहीं यह उल्लेख है कि विश्लेषण के उद्देश्यों के लिए इस अवधि को कब समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अतः जांच की अवधि तथा इसे समाप्त करने के समय को जांचकर्ता प्राधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। हमारे समक्ष उपस्थित मामले में आईटीसी द्वारा अवधि का चयन पांच वर्षों और छह माह के लिए किया गया था जो कि अर्जेंटीना- फुटवियर रक्षोपाय मामले में अर्जेंटीना के जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की गई जांच की अवधि के समकक्ष अवधि है। तथापि हम नोट करते हैं कि अपीलीय निकाय ने अपने निष्कर्ष में जांच की अवधि की लम्बाई संबंधी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोरिया द्वारा दिये गये जवाब पर भरोसा किया था जांच की अवधि पर समरूप अवधि के रूप में जो न देकर यह उल्लेख किया गया कि जांच की अवधि में हाल ही में किये गये आयातों पर प्रकाश डाला जाना चाहिए न कि केवल जांच की अवधि की प्रवृत्तियों पर। लाइन पाइप जांच के संबंध में आईटीसी ने न केवल अंतिम बिन्दु की तुलना की अथवा जांच की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्ति की जांच की (जैसाकि अर्जेंटीना ने अर्जेंटीना-फुटवियर रक्षोपाय मुद्दे की जांच में किया है)। इसने पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्ष दर वर्ष आधार पर किये गये आयातों के आंकड़ों का विश्लेषण किया और इस तथ्य पर भी विचार किया कि क्या 1998 के अंतरिम की तुलना में 1999 के अंतरिम ने कोई वृद्धि हुई है हमारा विचार है कि आईटीसी ने जांच की अवधि का चयन 5 वर्षों और 6 माह की अवधि के लिए करके अनुच्छेद 2.1 और अनुच्छेद-XIX के अनुच्छेद के असंगत कोई कार्य नहीं किया है। यह निष्कर्ष निम्नलिखित विचारों पर आधारित है: प्रथम इस करार में जांच की अवधि की दीर्घता के संबंध में कोई विशिष्ट नियम नहीं दिया गया है, द्वितीय आईटीसी द्वारा चयन की गई अवधि में अभी हाल ही के आयातों पर प्रकाश डालने की अनुमति दी गई है और, तृतीय आईटीसी द्वारा चयन की गई अवधि संवर्धित आयातों की मौजूदगी के संबंध में निष्कर्ष निकालने की अनुमति देने के लिए काफी लम्बी है।" (पैरा 7.196, 7.199 और 7.201<sup>1</sup>)

इसी पैनल में यूएस-लाइन पाइप मामले में यह निर्धारित किया कि:

"किसी रक्षोपाय जांच में संबंधित आयातों की प्रवृत्ति की जांच करने के लिए जांच की अवधि वही होनी चाहिए जो घरेलू उद्योग की गंभीर क्षति की जांच करने के लिए निर्धारित की गई है। यह पाटनरोधी अथवा प्रतिवहनकारी शुल्क की जांच में उत्पन्न स्थिति से विपरीत है जहां पाटन अथवा इम्दादीकरण की मौजूदगी का मूल्यांकन करने, वास्तविक क्षति के संबंध में निष्कर्ष निकालने के लिए जांच की अवधि की तुलना में कम अवधि की है। हमारा विचार है कि इस अंतर के पीछे के मुख्य कारणों में से एक कारण यह है कि, जैसा कि अर्जेंटीना-फुटवियर रक्षोपाय संबंधी अपीलीय निकाय द्वारा पाया गया कि यह निर्धारण करना कि क्या "इन संवर्धित मात्रा" के आयातों की जरूरत केवल तकनीकी अथवा गणितीय निर्धारण को पूरा करने के लिए ही नहीं है।" अपीलीय प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि "संवर्धित आयातों का निर्धारण करने के मामले में सक्षम प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जांच की अवधि के लिए आयात की प्रवृत्ति पर विचार करें"। आयातों में प्रवृत्तियों का मूल्यांकन और घरेलू उद्योग की गंभीर क्षति का निर्धारण करने के लिए संगत कारकों में प्रवृत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है तो यह कार्य केवल जांच की अवधि तक ही किया जा

<sup>1</sup> डब्ल्यूटी/ डीएस 202/ आर डीटी, 19.10.2001, यूएस-लाइन पाइप मामले में पैनल रिपोर्ट

सकता है अतः, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि यह विचार की अपीलीय निकाय द्वारा क्षति निर्धारण के संबंध में संगत अवधि संवर्धित आयातों का निर्धारण करने पर भी लागू होती है। (पैरा 7.209<sup>2</sup>)

54. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि न तो घरेलू विधियों में और न ही रक्षोपाय संबंधी करार और गाट के अनुच्छेद-XIX में जांच की अवधि का चयन करने के संबंध में विशिष्ट दिशानिदेश प्रदान किये गये हैं। तथापि, उपर्युक्त उल्लेख किये गये संदर्भ की भावना से ऐसा प्रतीत होता है कि संगत अवधि पर्याप्त रूप से इतनी लम्बी होनी चाहिए जिससे संवर्धित आयातों और गंभीर क्षति के संबंध में निष्कर्ष निकाले जा सकें और यह केवल हाल ही की अवधि तक समाप्त नहीं होनी चाहिए बल्कि यह हाल के विगत की अवधि तक होनी चाहिए।
55. जांच शुरुआत सूचना में जांच की अवधि को वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 तक लिया गया है क्योंकि घरेलू उद्योग ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन मई, 2010 में ही शुरू किया था और तदनुसार ही जांच की इस अवधि पर विचार किया गया। इस मामले में सार्वजनिक सुनवाई के दौरान विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाया गया मुद्दा घरेलू उद्योग द्वारा अपने प्रस्तुतिकरण में वर्ष 2010-11 की चौथी तिमाही से आगे के लिए किये गये तिमाही क्षति विश्लेषण से संबंधित था। पक्षकारों ने आपत्ति जताई की जांच की अवधि तीन वर्ष से कम है जो निदेशालय के परिचलित मानकों/ विगत के पूर्वोदाहरणों की संपुष्टता में नहीं है, यद्यपि यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तथ्यपरक रूप से सही नहीं है कि जांच शुरुआत नोटिस में जांच की अवधि वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और क्षति विश्लेषण भी उसी अवधि के लिए वार्षिक आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त स्थल सत्यापन के दौरान भी वर्ष 2010-11 की प्रथम तिमाही से लेकर वर्ष 2012-13 तक के आंकड़ों का सत्यापन किया गया। यह अलग बात की थी कि घरेलू उद्योग ने उनके पास आंकड़े उपलब्ध होने के बावजूद भी क्षति विश्लेषण का स्पष्टीकरण वर्ष 2010-11 की चौथी तिमाही से किया न कि संपूर्ण वर्ष से।
56. कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया कि छह माह की अल्प अवधि अर्थात् वर्ष 2012-13 की द्वितीय तिमाही और चतुर्थ तिमाही के बीच की अवधि के दौरान आयातों में 40 प्रतिशत तक की गिरावट आयी है और चूंकि मिथाइल एसिटोएसिटेट के भारत से आयातों में जांच की अवधि की अंतिम तिमाही से शुरू करके गिरने की अवबोधगम्य प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में सुधार हुआ है और यह दावा कि घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है पूरी तरह से भ्रामक है। तदनुसार, सार्वजनिक सुनवाई में घरेलू उद्योग से कहा गया कि वह उत्तरवर्ती अवधि के लिए अद्यतन क्षति आंकड़े दायर करे। घरेलू उद्योग ने उक्त आंकड़े अपने दिनांक 5 सितम्बर, 2013 के पत्र के तहत जुलाई, 2013 तक की अवधि के लिए अद्यतन आंकड़े प्रस्तुत किये। इन अतिरिक्त आंकड़ों पर भी गंभीर क्षति/गंभीर क्षति की चुनौती का अंतिम विश्लेषण करते समय विचार किया गया है।
57. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि चयन की गई अवधि काफी लम्बी होनी चाहिए जिससे कि सम्वर्धित आयातों की मौजूदगी के संबंध में निष्कर्ष निकाला जा सके और इस मामले में सीजनल विभिन्नता को निष्क्रिय किया जा सके इस लिए जांच की अवधि को वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 तक के रूप में विचारा गया है। तथापि, जैसा कि उपर्युक्त पैरा में उल्लेख किया गया है गंभीर क्षति के चुनौती का अनंतिम विश्लेषण करते समय घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराये गये अतिरिक्त आंकड़ों पर भी विचार किया गया।

#### (ड.) प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता

- (i) सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 7 और रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.2 में कुछ जानकारी को गोपनीय के रूप में माने जाने का प्रावधान किया गया है। नियमावली में प्रावधान है कि हितबद्ध पक्षकार से ऐसी जानकारी का वास्तविक आधार पर प्रकटन किये जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है जो कम्पनी की गोपनीय जानकारी हो और जिसका प्रकटन करने से उस पक्षकार के व्यापारिक हितों की पूर्वाधारणाओं को गंभीर क्षति पहुंचती हो, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न हो और जिसका याचिकाकर्ता ने विगत में कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रकटन न किया हो।

<sup>2</sup> डब्ल्यूटी/ डीएस 202/ आर डीटी, 19.10.2001, यूएस-लाइन पाइप मामले में पैनल रिपोर्ट

- (ii) घरेलू उद्योग ने कुछ जानकारी गोपनीय आधार पर प्रदान करायी है और प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों की गोपनीयता की मांग की है। घरेलू उद्योग ने रक्षोपाय नियमावली, 1997 और दिनांक 06.09.1997 के व्यापार नोटिस सं. एसजी/टीएन/1/1997 के प्रावधानों के अनुसार रक्षोपाय साधनों के लिए आवेदन का अगोपनीय पाठ प्रदान कराया है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने आवेदन पत्र दायर करते समय गोपनीयता की मांग करने के कारण भी प्रस्तुत किये हैं।
- (iii) इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग तथा हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदन पत्र दायर करते समय और लिखित प्रस्तुतिकरण/प्रत्युक्तियां दायर करते समय गोपनीयता की मांग करने के कारण भी प्रस्तुत किये हैं जो तर्कसंगत प्रतीत होते हैं और इसलिए उनको, जहां कहीं दावा किया गया है, स्वीकार कर लिया गया।

#### (च) संवर्धित आयात

सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा-8ख में रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के संबंध में केन्द्र सरकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है और उसमें निम्नलिखित प्रावधान है:

‘1. केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि किसी वस्तु का भारत में आयात इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत किया गया है जिनसे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो रही है तो यह शासकीय राजपत्र में एक अधिसूचना अधिसूचित करके उस वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण कर सकती है

58. नियमों में रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग करने के लिए आयातों में वृद्धि को आधारभूत पूर्वापेक्षा के रूप में माना गया है। अतः, रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग करने के प्रयोजनार्थ यह निर्धारण करने के लिए कि क्या विचाराधीन उत्पाद का आयात “इतनी अधिक संवर्धित मात्रा” में हुआ है, जितना नियमों में अपेक्षित है, आयातों में वृद्धि का विश्लेषण घरेलू उत्पादन के संगत तथा समग्र रूप में किया जाता है।

59. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 2 में ‘संवर्धित मात्रा’ को निम्नवत् परिभाषित किया गया है:

‘संवर्धित मात्रा’ में आयातों में वृद्धि शामिल होगी चाहे वह घरेलू उत्पादन के समग्र रूप में हो अथवा संगत रूप में’।

60. आयातों में वृद्धि की प्रकृति के संबंध में अर्जेंटिना फुटवियर (ईसी)<sup>3</sup> में अपीलीय निकाय ने, पैनल के विरुद्ध यह धारित किया कि आयातों में वृद्धि अत्यधिक अभिनव, अचानक, तीव्र एवं इतनी अधिक होनी चाहिए कि वह उससे क्षति कारित हो सके अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो सके। उसका संगत सार निम्नलिखित है:-

‘131. इस अपेक्षा का निर्धारण की क्या आयातों में ‘इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में’ वृद्धि को पूरा करने की अपेक्षा केवल गणतीय अथवा तकनीकी निर्धारण ही नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में किसी जांच के लिए केवल यह दर्शाना ही पर्याप्त नहीं होता है कि इस वर्ष किये गये आयात पिछले वर्ष..... विगत पांच वर्ष पहले किये गये उत्पादों के आयात से अधिक हुए हैं। पुनः, और यह पुनरावृत्ति प्रतीत होती है कि केवल आयातों की संवर्धित मात्रा ही पर्याप्त नहीं होगी बल्कि यह वृद्धि ऐसी बड़ी हुई मात्रा में हुई हो जिससे रक्षोपाय साधनों का अनुप्रयोग करने की जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो रही हो। और रक्षोपाय करार के अनुच्छेद-2.1 तथा गाट 1994 के अनुच्छेद-:1(क) दोनों में लिखित इस भाषा से, हमारा विश्वास है कि, यह अपेक्षा की जाती है कि आयातों में यह वृद्धि अत्यधिक अभिनव, अत्यधिक अचानक, अत्यधिक तीव्र और अत्यधिक भारी मात्रा में, परिमाणात्मक और गुणात्मक रूपों में होनी चाहिए जिससे कि गंभीर क्षति हो सके या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो सके।

<sup>3</sup> अर्जेंटिना- फुटवियर (ईसी) संबंधी अपीलीय निकाय की रिपोर्ट दिनांक 14 दिसम्बर, 1999 की डब्ल्यूटी/ डीएस/

यूएस-हीट ग्लुटेन संबंधी पैनल<sup>4</sup> में “ऐसी संवर्धित मात्रा में” वाक्यांश की व्याख्या निम्नवत की गई है:-

“8.31. गाट 1994 के अनुच्छेद-1(क) और रक्षोपाय संबंधी करार (एसए) के अनुच्छेद-2.1 में आयातों में केवल वृद्धि की ही बात नहीं की गई है। बल्कि संबंधित उत्पाद के आयातों में यह वृद्धि परिमाणात्मक और गुणात्मक प्रकृति की होनी चाहिए। गाट 1994 के अनुच्छेद-1(क) और रक्षोपाय संबंधी करार (एसए) के अनुच्छेद-2.1 में यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त उत्पाद का आयात संबंधित सदस्य के भू-भाग में इतनी अधिक बढ़ी हुई मात्रा (घरेलू उत्पादन के संगत या समग्र रूप से) में की जा रही हो कि उससे गंभीर क्षति हो रही हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो रही हो। अतः केवल आयातों में वृद्धि ही पर्याप्त नहीं होगी। बल्कि हम अर्जेंटीना फुटवियर रक्षोपाय में अपीलीय निकाय के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि यह वृद्धि पर्याप्त रूप से अभिनव, अचानक, तीव्र और बहुत अधिक, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में, होनी चाहिए जिससे कि गंभीर क्षति कारित हो सके अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो सके”।

#### (छ) समग्र रूप से वर्धित आयात

61. उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में मिथाइल एसिटोएसिटेट के आयातों की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया है भारत में मिथाइल एसिटोएसिटेट का आयात कई देशों से किया जाता है और यह प्राथमिकतः चीन, यूएसए, स्विटजरलैंड से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2010-11 से वित्तीय वर्ष 2012-13 तक मिथाइल एसिटोएसिटेट के उत्पादन और आयात का विवरण निम्नलिखित है:-

वित्त वर्ष	कुल आयात (मी.टन)	कुल भारतीय उत्पादन (मी.टन)
2010-11	3985	1980
2011-12	3584	2604
2012-13	5084	2045

62. वर्ष 2012-13 में आयातों में समग्र रूप से वृद्धि प्रतीत होती है। आयातों में आधार वर्ष से वृद्धि हुई है और यह आयात जो वर्ष 2011-12 में 3584 मी.टन के हुए थे बढ़कर वर्ष 2012-13 में 5084 मी.टन हो गये जिससे 41.85 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित होती है। अतः यह धारित किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान मिथाइल एसिटोएसिटेट के आयात में समग्र रूप से तीव्र वृद्धि हुई है।

#### (i) उत्पादन के संबंध में आयात

63. जांच की अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में आधार वर्ष तथा पिछले वर्ष से तुलना करने पर भी हुई है। कुल उत्पादन के संबंध में आयात जो वर्ष 2010-11 में 201 प्रतिशत थे बढ़कर वर्ष 2012-13 में 249 प्रतिशत हो गये अर्थात् इनमें 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो बहुत अधिक वृद्धि है। तथापि वर्ष 2011-12 में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन में वृद्धि के कारण आयातों में कुछ कमी आयी परंतु वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में इनमें भारी वृद्धि हुई।

वित्त वर्ष	कुल आयात (मी.टन)	कुल भारतीय उत्पादन (मी.टन)	उत्पादन के संबंध में आयातों का प्रतिशत
2010-11	3985	1980	201
2011-12	3584	2604	138
2012-13	5084	2045	249

#### (ii) मांग के संबंध में आयात

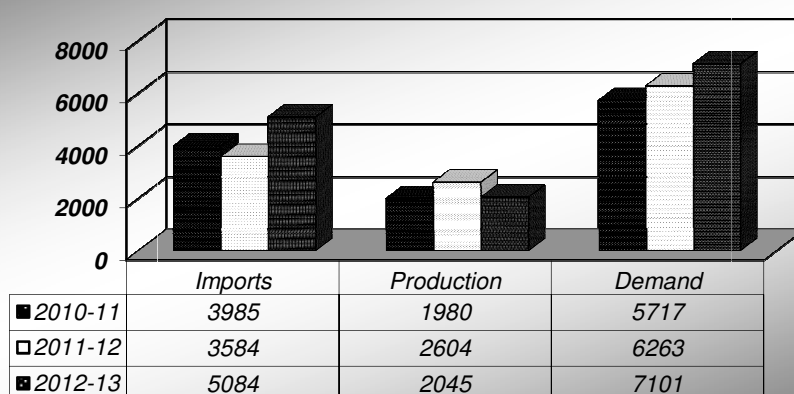
64. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, विचाराधीन उत्पाद की खपत या मांग का निर्धारण विभिन्न देशों से भारत में इस उत्पाद के आयात, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों और अन्य घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों के रूप में किया जाता है। इस अवधि के दौरान इस तरह निर्धारित मांग/खपत में परिवर्तन की तुलना विभिन्न स्रोतों से हुए

<sup>4</sup>यूएस हीट ग्लुटेन संबंधी पैनल दिनांक 31 जुलाई, 2000, डब्ल्यू टी /डी एस 166/आर

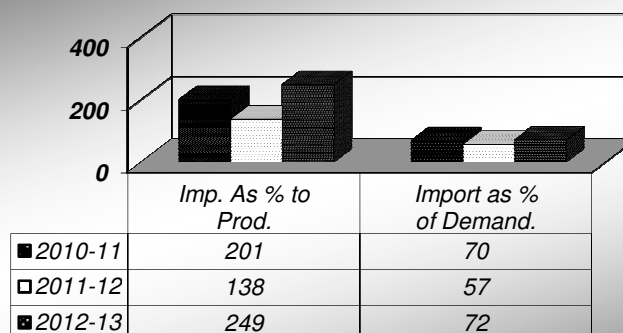


आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा की गई आपूर्तियों में परिवर्तन से की गई है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में देश में इस उत्पाद की समग्र मांग अथवा खपत के संबंध में वृद्धि हुई है/कमी आई है। यह देखा जाता है कि मांग के संबंध में आयातों में यह वृद्धि मामूली सी ही रही है अर्थात् यह वर्ष 2010-11 में 70 प्रतिशत थी, बढ़कर वर्ष 2012-13 में 72 प्रतिशत हो गई। तथापि, पिछले वर्ष से तुलना करने पर मांग के संबंध में आयातों में भारी वृद्धि हुई है अर्थात् यह आयात वर्ष 2011-12 में 57 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 72 प्रतिशत हो गये।

वित्त वर्ष	कुल आयात (मी.टन)	कुल भारतीय मांग (मी.टन)	मांग के संबंध में आयातों का प्रतिशत
2010-11	3985	5717	70
2011-12	3584	6263	57
2012-13	5084	7101	72



उत्पादन और मांग के प्रतिशत के रूप में आयात दर्शाने वाली तालिका:



65. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि आयातों में यह वृद्धि अचानक, तीव्र और बहुत अधिक नहीं हुई है और आयातों का विश्लेषण वर्तमान घरेलू उद्योग के प्रचालन से पहले की काफी लंबी अवधि तक के लिए किया जाना चाहिए। यह तर्क दिया जाता है कि घरेलू उद्योग ने रिकार्ड में पर्याप्त आंकड़े और विश्लेषण यह स्थापित करने के लिए पहले से ही उपलब्ध कराये हैं कि आयातों में यह वृद्धि अचानक, तीव्र और भारी मात्रा में हुई है। आयातों में उत्पादन के संबंध में यह वृद्धि समग्र रूप से हुई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2010-11 से पहले के आयातों का विश्लेषण, जब घरेलू उद्योग प्रचालन में नहीं था, ना केवल अयथार्थ और अप्रतिनिधित्वपूर्ण है बल्कि यह विधि की अपेक्षाओं के विपरीत भी है। इसी तरह जांच की अवधि के दौरान तिमाही बार विश्लेषण पर भी विचार नहीं किया गया है कि क्योंकि विचाराधीन उत्पाद की सीजनल महत्ता को घरेलू उद्योग तथा हितबद्ध पक्षकारों, दोनों द्वारा माना गया है।

66. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि जांच की अवधि के दौरान आधार वर्ष की तुलना में आयातों में वृद्धि हुई है और आयातों में यह वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 की अभिनवतम अवधि में बहुत अधिक हुई है। इस कारण आधार वर्ष की तुलना में आयातों में समग्र वृद्धि बहुत अधिक प्रतीत होती है जो सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के आशय के अंतर्गत “संवर्धित आयात” हैं।

**(iii) आयातों/अनपेक्षित विकास में वृद्धि के कारण**

67. यह नोट किया जाता है कि महानिदेशक (रक्षोपाय) पर ऐसी कोई अभिव्यक्त बाध्यता जरूरत नहीं है कि वह अप्रत्याशित विकास का विश्लेषण करें क्योंकि भारतीय नियमावली अथवा ऐसी कोई क्रियाप्रणाली नहीं है जिसका अप्रत्याशित विकास का विश्लेषण करने में अनुकरण किया जाए। अथवा रक्षोपाय संबंधी करार भी किसी क्रियाप्रणाली के संबंध में ऐसा कोई अनुरेख नहीं करते हैं जिसका अनुपालन किया जाना चाहिए अथवा ऐसे कोई पैरामीटर नहीं है जिनका अप्रत्याशित विकास का निर्धारण करते समय पूरा किया जाना चाहिए। गाट के अनुच्छेद XIX-के साथ पठित रक्षोपाय करार राष्ट्रीय प्राधिकारियों को अधिबद्ध करता है कि वे उन की “शित विकासों/अप्रत्याशित” जांच करे जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंची है। यह माना जाता है कि यह निदेशालय इस जांच में के मुद्दे की निरंतर जांच करता रहा है। “शित विकास/अप्रत्याशित” तथापि यह विचार , किया जाता है कि यह निदेशालय अपनी जांच में “अप्रत्याशित विकास” के मुद्दे की निरंतर जांच करता रहा है। अतः उन परिस्थितियों अथवा अप्रत्याशित विकासों की जांच करना महत्वपूर्ण है जिनके कारण आयातों में वृद्धि हुई।
68. अर्जेंटीना फुटवियर (ईसी मामले में) में अपीलीय निकाय ने धारित किया कि “अप्रत्याशित विकास” का आशय उस विकास से है जिसकी प्रत्याशा न की गई हो। “अप्रत्याशित विकास” में उस विकास की जरूरत होती है जिसके कारण आयात किया जा रहा कोई उत्पाद इतनी अधिक मात्रा में बढ़ गया हो और उससे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हो कि उनसे घरेलू उद्योग को “अप्रत्याशित” क्षति कारित हुई हो अथवा अप्रत्याशित क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो। कोरिया-डेयरी मामले में अपीलीय निकाय ने यह धारित किया कि अप्रत्याशित विकास वे विकास होते हैं कि जिनको सदस्य द्वारा उस बाध्यता को पूरा किया जाते समय पहले से ना देखा गया हो अथवा जिसकी पहले से कोई उम्मीद न हो।
69. तब, अर्जेंटीना-फुटवियर (ईसी) मामले में अपीलीय निकाय ने यह धारित किया कि “अप्रत्याशित विकास” से रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के लिए किसी ऐसी “परिस्थिति” स्थापित होने की अपेक्षा नहीं की जाती है कि बल्कि इसमें “परिस्थितियों” के निश्चित सेट का वर्णन किया गया है।
70. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित कारकों का उल्लेख किया गया है जिसके कारण विभिन्न देशों से उक्त उत्पाद के आयातों में वृद्धि हुई है जिसके कारण वर्तमान मामले में अप्रत्याशित परिस्थितियां सृजित हुई हैं।

**(क) यूरोप की बाजारों में खपत में अप्रत्याशित गिरावट**

71. यूरोप की बाजारों से सूचना प्राप्त हुई कि विदेशों में संबद्ध वस्तु की भारी क्षमताओं के परिणामस्वरूप मांग में अप्रत्याशित गिरावट आयी है और विदेशी उत्पादकों ने भारत को अपना निर्यात बढ़ाने का आश्रय लिया है।

**(ख) चीन जन. गण में अतिरिक्त क्षमताएं**

72. चीन जन. गण. के उत्पादक जैसे मैसर्स जिनहुआ फार्मास्युटिकल्स (सौगेंग) कंपनी लिमिटेड, मैसर्स क्विनगडाओ डबल पीच स्पेशलिटी कैमिकल्स (गुप) कंपनी लिमिटेड और मैसर्स निंगबो वेंगलांग टेक कंपनी लिमिटेड ने भारी क्षमताएं स्थापित कर ली हैं और वे भारत को निर्यात प्रारंभ करने की राह जोह रही हैं। घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया यह विकास स्पष्टतः दर्शाता है कि भारत को निरंतर आयात संवर्धित मात्रा में होते रहना लाजमी हो गया है।

**(ग) कच्चे माल की लागत में वृद्धि के बावजूद आयातों का अप्रत्याशित रूप से न्यून कीमत निर्धारण**

73. कच्चे माल की कीमतों में वैश्विक रूप से वृद्धि होने के बावजूद आयात कीमतों में केवल मामूली सी वृद्धि हुई है। चूंकि भारत एक कीमत आकर्षक बाजार है इसलिए यहां उपभोक्ताओं द्वारा कम कीमत के आयातों का बढ़-चढ़ कर स्वागत किया गया। अतः कम कीमत आयातों के कारण भारत में आयातों में वृद्धि हुई।

74. कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका ने उल्लिखित अधिकांश तर्कों को ही पुनः दोहराया है और कोई अतिरिक्त साक्ष्य प्रदान करने में वह असफल रहा है। घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि मंदी के परिणामस्वरूप यूरोपीय बाजारों में खपत में भारी अप्रत्याशित गिरावट आयी है, चीन जन.गण में अतिरिक्त क्षमताएं सृजित हुई हैं और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद आयातों की अप्रत्याशित रूप से न्यून कीमत तीनों को अप्रत्याशित घटना के रूप में बताया है परंतु उपर्युक्त तीन में से किसी भी घटना को अप्रत्याशित के रूप में माना जाना ना तो सही है और न ही माना जा सकता है। कुछ एक ने तर्क दिया है कि आवेदनकर्ता द्वारा किया गया यह दावा कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए अप्रत्याशित विकास कोई पृथक जरूरत या शर्त नहीं है, स्पष्टतः गाट 1994 के अनुच्छेद- का खुला उल्लंघन है जिसमें स्पष्टतः यह प्रावधान किया गया है कि महानिदेशक द्वारा अप्रत्याशित विकास देखा जाना अपेक्षित है।
75. उपर्युक्त तर्क के विरोध के रूप में ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग ने एक रिपोर्ट का उल्लेख किया है जो वर्ष 2008 के वित्तीय संकट से उत्पन्न मंदी के प्रभावों के कारण यूरोपीय संघ में सामान्यतः रासायनिक उत्पादों की मांग में गिरावट के बारे में सर्वोत्तम वार्ता करता है। यदि यह मान भी लिया जाता है कि यूरोपीय संघ में रसायनों की मांग में कमी आई है फिर भी घरेलू उद्योग यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हो सका कि इस कमी से, वर्ष 2008 में वित्तीय संकट प्रारंभ होने के दो वर्ष से अधिक समय के पश्चात, दक्षिण एशियाई देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, को मिथाइल एसिटोएसिटेट के निर्यातों में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत रिपोर्ट से यह संकेत मिलता है कि रासायनिक उत्पादों के लिए कम मांग के परिणामस्वरूप अधिकांश उत्पादकों ने अपना उत्पादन तेजी से कम कर दिया है। इससे घरेलू उद्योग के तर्क का विरोध होता है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि वर्ष 2012-13 के दौरान जिन्हुआ फार्मास्युटिकल्स (शौगांग) कंपनी लिमिटेड और क्विनगडाओ डब्ल पीच स्पेशलिटी कैमिकल (ग्रुप) कंपनी लिमिटेड द्वारा क्षमता संवर्धन अप्रत्याशित था और इससे भारत को निर्यातों में वृद्धि होना अनिवार्य हो गया था। परंतु यह जांच की अवधि के दौरान चीन जन.गण. से भारत को निर्यातों में परिवर्तन को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हो पाया, जिससे अनिवार्यतः भारत को मिथाइल एसिटोएसिटेट के आयातों में अचानक, तीव्र और महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। जहां तक आयातों की अप्रत्याशित रूप से कम कीमत निर्धारित करने के संबंध में तीसरे दावे का प्रश्न है, यह पाया जाता है कि हो सकता है कि इनपुट लागत से अंतिम उत्पाद की कीमत पर कुछ प्रभाव पड़े परंतु वह ठीक-ठीक अनुपात जिसमें अंतिम उत्पाद की कीमतों में परिवर्तन होगा परिवर्तन अनुपात पर निर्भर होता है और घरेलू उद्योग द्वारा ऐसे किसी अनुपात को प्रदान कराये जाने के अभाव में यह कल्पना करना उचित नहीं है कि अंतिम उत्पाद की कीमतों में उसी हद तक वृद्धि होगी जिस हद तक कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई है।
76. इस लिए घरेलू उद्योग ने अप्रत्याशित विकास संबंधी अपने दावे का समर्थन किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा नहीं किया है इसके कारण उन्हें अप्रत्याशित विकास के रूप में नहीं माना जा सकता है।

### गंभीर क्षति

- (ज) सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख की उप-धारा 6(ग) ने निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:
- “गंभीर क्षति” का आशय ऐसी क्षति से है जिसके कारण घरेलू उद्योग की स्थिति में संपूर्ण अवरोध उत्पन्न होता हो।
- (i) रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद-4.2 (क) और सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 के अनुबंध के नियम 8 में तकनीकी रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण करने के लिए कतिपय सूचीबद्ध कारकों और अन्य संगत कारकों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तथापि इन प्रावधानों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस

मूल्यांकन द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ऐसा मूल्यांकन विभिन्न उद्योगों के लिए विभिन्न मामलों में, किसी एक मामले के तथ्यों और संबंधित उद्योग की स्थिति के तथ्यों के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकता है। इन सूचीबद्ध कारकों का मूल्यांकन अनिवार्य रूप से यह प्रदर्शित नहीं करेगा कि प्रत्येक ऐसे कारक में “गिरावट” आ रही है। उदाहरण के लिए किसी एक मामले में बिक्री, रोजगार और उत्पादकता में भारी गिरावट आ सकती है जिससे घरेलू उद्योग की स्थिति में ‘भारी समग्र परिक्षयण’ प्रदर्शित होता हो और इसलिए यह गंभीर क्षति के निष्कर्ष को न्यायोचित ठहरायेगा। किसी अन्य मामले में हो सकता है कि कतिपय कारकों में गिरावट न आ रही हो परंतु ऐसा होते हुए भी समग्र तस्वीर में उद्योग का “समग्र भारी परिक्षयण” प्रदर्शित होता है। अतः समग्र सूचीबद्ध कारकों का तकनीकी परीक्षण करने के अतिरिक्त यह अनिवार्य है कि घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का उन सभी संगत कारकों के आलोक में मूल्यांकन किया जाए जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।<sup>5</sup>

(ii) तदनुसार गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती का विश्लेषण करने में उन सभी कारकों, जिनका नियमों में उल्लेख किया गया है और उन अन्य कारकों जो गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण करने के लिए संगत है, पर विचार किया गया। किसी एकल कारक को निरर्थक के रूप में नहीं माना गया। संगत व्यवसाय चक्र के संदर्भ के अंतर्गत उन सभी संगत कारकों और प्रतिस्पर्धा की उन सभी शक्तों, जो प्रभावित उद्योग से प्राशंगिक है, विचार किया गया है। गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का उन सभी प्राशंगिक कारकों के आलोक में, मूल्यांकन पर आधारित है जिनका उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।

(झ) सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा 6(घ) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है।

“गंभीर क्षति की चुनौती” का आशय स्पष्ट एवं आसन्न गंभीर क्षति के खतरे से है।

सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 के अनुबंध-1 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है

“यह निर्धारित करने की जांच में कि क्या संवर्धित आयातों से किसी अभिव्यक्त उद्योग को गंभीर क्षति कारित हो रही है अथवा गंभीर क्षति कारित होने की चुनौती उत्पन्न हो रही है, महानिदेशक उद्देश्यपरक एवं परिगणनीय उन सभी प्रासंगिक कारकों का मूल्यांकन करेंगे जिनका उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, खासकर संबंधित वस्तु के आयात में समग्र और संगत रूप से वृद्धि की दर और राशि, संवर्धित आयातों द्वारा घरेलू बाजार में कब्जाए गये हिस्से, बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ एवं हानि तथा रोजगार के स्तर में परिवर्तन शामिल होंगे।”

(ज) गंभीर क्षति:

रिकार्ड उपलब्ध तथ्यों के मद्देनजर मिथाइल एसिटोएसिटेट के संवर्धित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को कारित की गई गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति कारित किये जाने की चुनौती निम्नलिखित आर्थिक पैरामीटरों का विश्लेषण किये जाने से स्पष्टतः प्रदर्शित होती है:

(i) **उत्पादन:** घरेलू उद्योग का उत्पादन जो वर्ष 2010-11 में 1980 मी.टन था बढ़कर वर्ष 2012-13 में 2045 मी.टन हो गया। तथापि तत्कालिन विगत वर्ष 2011-12 की तुलना में उत्पादन में वर्ष 2012-13 में कमी आयी है।

वर्ष	मिथाइल एसिटोएसिटेट का उत्पादन (मी.टन)
2010-11	1980
2011-12	2604
2012-13	2045

<sup>5</sup>अर्जेंटिना फुटवियर मामले में डब्ल्यूटीओ की अपीलिय निकाय की रिपोर्ट के पैरा 139 पर आधारित है

- (ii) **क्षमता उपयोग:** अभी सर्वाधिक अभिनव अवधि में घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में भारी गिरावट आयी है यह वर्ष 2011-12 में 53 प्रतिशत थी, घटकर वर्ष 2012-13 में 41 प्रतिशत रह गयी।

वर्ष	संस्थापित क्षमता (मी. टन)	क्षमता उपयोग (प्रतिशत)
2010-11	4950	40
2011-12	4950	53
2012-13	4950	41

- (iii) **घरेलू मांग में घरेलू उत्पादकों का हिस्सा:** घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आयी है। आवेदनकर्ता का वर्ष 2010-11 में बाजार हिस्सा 30 प्रतिशत था, बढ़कर वर्ष 2011-12 के दौरान 43 प्रतिशत हो गया परंतु इसमें वर्ष 2012-13 में गिरावट आयी और यह घटकर 28 प्रतिशत ही रह गया।

वित्तीय वर्ष	कुल आयात (मी.टन)	घरेलू उद्योग की बिक्री(मी.टन)	कुल मांग (मी.टन)	बाजार हिस्सा (प्रतिशत)		मालसूची (मी.टन)
				डीआई	आयात	
2010-11	3985	1732	5717	30	70	196
2011-12	3584	2679	6263	43	57	84
2012-13	5084	2017	7101	28	72	79

- (iv) **बिक्री के स्तर में परिवर्तन:** जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है घरेलू उद्योग की बिक्री में, जो वर्ष 2010-11 में 1732 मी.टन थी, वृद्धि होकर वर्ष 2011-12 में 2679 मी.टन हो गयी परंतु इसके पश्चात वर्ष 2012-13 में इसमें भारी गिरावट आयी और यह 2017 मी.टन ही रह गयी।
- (v) **रोजगार:** औसत रोजगार जो वर्ष 2010-11 में 183 था बढ़कर वर्ष 2012-13 में 247 हो गया।
- (vi) **लाभ एवं हानि:** घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता निम्नलिखित रही है:-

वित्तीय वर्ष	लाभप्रदायकता (रुपये/लाख) (अनुक्रमित)
2010-11	-100
2011-12	-330
2012-13	-225

ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग घाटे में है परंतु विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 की अभिनवतम अवधि में सुधार होने के चिन्ह प्रदर्शित हो रहे हैं।

77. उपर्युक्त के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को लगभग सभी प्रमुख रक्षोपाय पैरामीटरों अर्थात् उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सा, क्षमता उपयोग में वर्ष 2012-13 के दौरान, उसके तुरंत विगत के वर्ष अर्थात् वर्ष 2011-12 की तुलना में, विपरीत प्रभाव पड़ा है। तथापि यह विपरीतता आधार वर्ष की तुलना में उतनी अधिक नहीं है क्योंकि इन सभी पैरामीटरों ने आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में लाभप्रद प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। यद्यपि यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि संपूर्ण जांच अवधि के दौरान आयातों में लगातार वृद्धि हुई है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है, यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान आयातों में भारी वृद्धि हुई है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित हुई है।

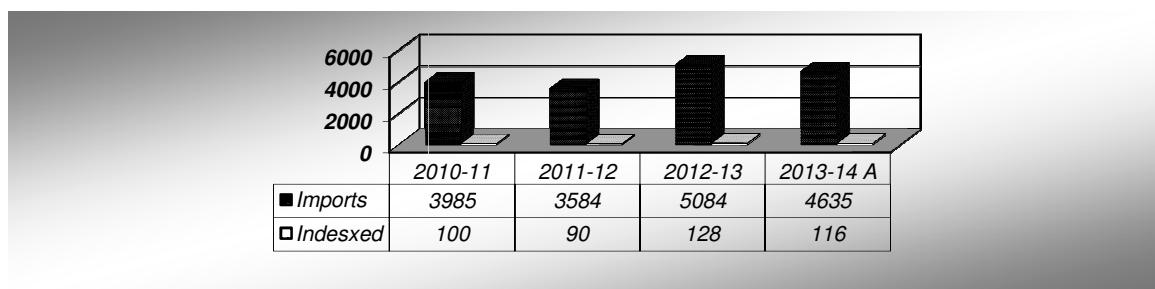
#### (ट) गंभीर क्षति की चुनौती

कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण को देखते हुए सार्वजनिक सुनवाई के दौरान जुलाई, 2013 तक के लिए जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़े मांगे गए जिन्होंने यह तर्क दिया कि चूंकि भारत को एमएए के आयातों में, जांच की अवधि की अंतिम तिमाही से प्रारंभ करके बोधगम्या गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है और घरेलू उद्योग के बाजार-हिस्से में सुधार हो रहा है, इसलिए यह दावा कि घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है पूरी तरह से गलत है। उन्होंने आगे यह प्रस्तुत किया कि छह माह अर्थात् वर्ष 2012-13 की दूसरी और चौथी तिमाही के बीच, की अल्प अवधि में आयातों में 40 प्रतिशत तक गिरावट आई है और यह कि याचिकाकर्ता के उत्पादन में वर्ष 2012-13 की

सर्वाधिक अभिनवतम तिमाही अर्थात् चौथी तिमाही में, जैसा कि घरेलू उद्योग ने प्रस्तुतिकरण किया है, सुधार हुआ है। उपर्युक्त परिस्थितियों में, घरेलू उद्योग को क्षति के संवर्धन की संभावनाओं के बारे में स्पष्ट निष्कर्ष निकालने और घरेलू उद्योग के लिए क्षति की चुनौती का आकलन करने के लिए जांच की अवधि अर्थात् वर्ष 2013-14 (अप्रैल-13 से जुलाई, 13 तक) के पश्चात की अवधि में प्रवृत्तियों का विश्लेषण की जांच किए जाने पर निम्नलिखित प्रेषित किया गया:-

(क) आयात आंकड़े

स्रोत सहित वर्णन	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अप्रैल से जुलाई)	2013-14 (वार्षिकीकृत)
सुनवाई के पश्चात अनुबंध 6 में यथा प्रस्तुत (जुलाई, 13 तक अद्यतनीकृत आईबीआईएस स्रोत से प्राप्त (मी.टन में)	3985	3584	5084	1545	4635
अनुक्रमित (प्रतिशत)	100	90	128		116



(ख) मिथाइन एसिटोएसिटेट से संबंधित विभिन्न आर्थिक/रक्षोपाय पैरामीटरों का विश्लेषण

वित्तीय वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अप्रैल से जुलाई)	2013-14 (वार्षिकीकृत)
आईबीआईएस के अनुसार आयात (मी.टन)	3985	3584	5084	1545	4635
घरेलू उद्योग का उत्पादन (मी.टन)	1980	2604	2045	1094	3282
घरेलू उद्योग की बिक्री (मी.टन)	1732	2679	2017	1141	3423
कुल खपत/मांग (मी.टन)	5717	6263	7101	2686	8058
निर्यात (मी.टन)	51	38	33	Nil	
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा (मी.टन)	30	43	28	42	42
आयातों का बाजार हिस्सा(प्रतिशत)	70	57	72	58	58
संस्थापित क्षमता (मी.टन)	4950	4950	4950	1650	4950

क्षमता उपयोग (प्रतिशत)	40	53	41	66	66
औसत रोजगार संख्या	183	217	247		267
मालसूची (मी.टन)	196	84	79	79	79

- (i) **आयात:** वर्ष 2012-13 से तुलना करने पर वर्ष 2013-14 (वार्षिकीकृत) में आयातों में गिरावट आई है परंतु यह आधार वर्ष की तुलना में अधिक है।
- (ii) **उत्पादन:** वर्ष 2012-13 की तुलना में उत्पादन में वर्ष 2013-14 (वार्षिकीकृत) में तीव्र लगभग 60.48 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। यह आधार वर्ष उत्पादन से बहुत अधिक अर्थात् 66 प्रतिशत तक ज्यादा है।
- (iii) **घरेलू बिक्रियां:** वर्ष 2012-13 से तुलना करने पर घरेलू बिक्रियों में वर्ष 2013-14 (वार्षिकीकृत) में लगभग 70 प्रतिशत तक भारी वृद्धि हुई है जो आधार वर्ष के आंकड़ों से लगभग दो गुना है। आधार वर्ष 2010-11 से तुलना करने पर यह वृद्धि 98 प्रतिशत है।
- (iv) **कुल खपत/मांग:** इसने संपूर्ण अवधि में 2010-11 से वर्ष 2013-14 (वार्षिकीकृत) तक बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन उत्पाद की मांग भी इस उत्पाद की कुल संस्थापित क्षमता से काफी अधिक है जिसके परिणामस्वरूप मांग/आपूर्ति में अंतर उत्पन्न हुआ है। तथापि, घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि उनका संयंत्र स्विंग संयंत्र है और यह विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता बढ़ाकर देश में इस उत्पाद की मांग को पूर्णतया पूरा करने में सक्षम है। तथापि, कम कीमत वाले आयातों की वृद्धि ने आवेदनकर्ता को सम्बद्ध वस्तु के लिए स्विंग क्षमता का उपयोग करने से रोक दिया है। इसके अतिरिक्त, बिक्री लागत उच्चतर होने के बावजूद घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम रखने के लिए विवश किया गया जिससे कि भारत में होने वाले आयातों से प्रतिस्पर्धा की जा सके, जिसे उनके लिए प्राप्त करना अव्यवहार्य हो गया। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्तुतिकरण किया गया है कि आवेदनकर्ता घरेलू उद्योग के संयंत्र के अन्य वर्तमान रिएक्टर्स का उपयोग डाइकेटेन अवकलजों का उत्पादन करने के लिए किया जा रहा है जो आवेदनकर्ता के मामले में संबद्ध वस्तु की बिक्री, उचित बिक्री कीमत पर करने में सक्षम थे, उनका उपयोग सम्बद्ध वस्तु का विनिर्माण करने के लिए किया जा सकता था। तथापि, कम कीमत के आयातों के उद्रेक ने आवेदनकर्ता को इस स्विंग क्षमता का सम्बद्ध वस्तु के लिए प्रयोग करने से रोक दिया। वास्तव में, आवेदनकर्ता के अनुसार वे बाजार की मांग को पूरा करने के लिए जो वर्ष 2012-13 में 7101 मी.टन थी, सम्बद्ध वस्तु की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए अन्य रिएक्टरों की क्षमता का आबंटन कर सकते हैं।
- (v) **निर्यात:** निर्यातों ने संपूर्ण प्रश्नाधीन अवधि में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है।
- (vi) **घरेलू उद्योग/आयातों का बाजार हिस्सा:** वर्ष 2013-14 में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में (वार्षिकीकृत रूप से) वृद्धि हुई है; जबकि वर्ष 2012-13 की तुलना में आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। इससे आयातों की तुलना में घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार प्रदर्शित होता है और आयातों में उद्रेक तथा घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कोई भी कारणात्मक सम्बंध स्थापित नहीं होता है।
- (vii) **क्षमता उपयोग:** विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में (वार्षिकीकृत) क्षमता उपयोग में 25 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।
- (viii) **औसत रोजगार:** संपूर्ण प्रश्नाधीन अवधि में इसने बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है।
- (ix) **मालसूची:** संपूर्ण प्रश्नाधीन अवधि में मालसूची में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तर्क के अनुसार इसका कारण यह है कि भारत में कम कीमत वाले आयातों के उद्रेक तथा आर्डरों के अभाव से निपटने के लिए उत्पादन जानबूझकर कम करना पड़ा।
- (x) **लाभप्रदायकता:** पक्षकार की लाभ/हानि की स्थिति निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित की गई है:

वित्त वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (ए)
अनुक्रमित	-100	-330	-225	-473

विगत वर्ष में घाटे में सुधार की स्थिति दर्शाने के पश्चात पिछले वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान (वार्षिकीकृत) घाटे में और अधिक वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में जहां (वर्ष 2013-14 में जुलाई, 2013 तक) आर्थिक पैरामीटरों में स्पष्ट सुधार प्रदर्शित हो रहा है और आयातों में कमी आई है, घाटे में वृद्धि गंभीर क्षति तथा गंभीर क्षति की चुनौती के लिए आयातों के उद्रेक के अलावा अन्य कारकों की उपस्थिति की महत्ता को प्रदर्शित करती है।

78. उपर्युक्त आंकड़ों की संवीक्षा करने पर जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के लिए यह नोट किया गया कि समग्र आयातों में इतनी अधिक मात्रा में गिरावट आई है कि आयातों के बाजार हिस्से में लगभग 14 प्रतिशत तक गिरावट आ गई जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में उसके समनुरूप ही 14 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू बिक्री में तीव्र वृद्धि के साथ ही उत्पादन, मालसूची की स्थिति, उत्पादकता, रोजगार में भारी सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में, उपर्युक्त को देखते हुए, पूर्ण सदाशयता के साथ, कुछ कमी प्रदर्शित होती है परंतु इसके लिए आयातों में उद्रेक को रंचमात्र भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने वर्ष 2013-14 (वार्षिकीकृत) में उसके तुरंत विगत वर्ष अर्थात् वर्ष 2012-13 की तुलना में स्पष्ट सुधार प्रदर्शित किया है। यहां तक कि उठाए गए घाटे में भी (वर्ष 2012-13 में) सुधार हो गया जब घरेलू उद्योग को लगभग सभी आर्थिक पैरामीटरों के संबंध में गंभीर क्षति सहन करनी पड़ी थी परंतु इसमें जांच की अवधि के पश्चात की अवधि (जुलाई, 2013 तक अर्थात् वर्ष 2013-14 में वार्षिकीकृत) में एकबार पुनः सुधार हुआ जब सभी आर्थिक पैरामीटर सुधार प्रदर्शित करने लगे। अतः, यद्यपि, ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग को आयातों में उद्रेक के कारण वर्ष 2012-13 तक गंभीर क्षति सहन करनी पड़ी, परंतु जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के लिए उसे इस मामले में सच नहीं कहा जा सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि घरेलू उद्योग द्वारा अभिव्यक्त की गई क्षति की चुनौती बहुत कुछ बिना किसी प्रमाण के है।

(ठ) **कीमत अधोरदन:**

79. घरेलू उद्योग ने कीमत अधोरदन तथा क्षति मार्जिन के संबंध में, स्वतंत्र सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित लागत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जो निम्नलिखित हैं:-

विवरण	2010-11 (अनुक्रमित)	2011-12 (अनुक्रमित)	2012-13 (अनुक्रमित)
आयात कीमत (रुपये/मी.टन)	100	107	108
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत (रुपये/मी.टन)	106	113	114
बिक्री लागत (रुपये/मी.टन)	120	143	141
उतराई मूल्य (रुपये/मी.टन)	109	115	117
कीमत अधोरदन (रुपये/मी.टन)	-3	-2	-3
का कीमत अधोरदन का प्रतिशत	-3	-2	-3



80. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के विपरीत कि कच्चे माल की कीमत में उतार-चढ़ाव के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, और घरेलू उद्योग अपने माल की उस कीमत पर बिक्री करने में सक्षम रहा है जो आयात कीमतों से मेल खाती है, इसके द्वारा कोई कीमत अधोरदन अथवा क्षति हुई है, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और आयातित उत्पादों के उतराई मूल्य के बीच ऋणात्मक कीमत अधोरदन है, जैसा कि उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत आयातित उत्पाद के उतराई मूल्य से कम है। इससे पुनः यह स्पष्ट होता है कि यह विचाराधीन उत्पाद घरेलू रूप से तथा आयातित रूप से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध है। इससे यह विश्वास और भी सुदृढ़ होता है कि यद्यपि वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में आयातों में उद्रेक रहा है, तथापि, ऐसा इस विचाराधीन उत्पाद की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हुआ है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण के अनुसार स्व-नियंत्रित उत्पादन के तर्क के साथ-साथ संस्थापित क्षमता की सीमाओं और उत्पाद बास्केट के बीच इस विचाराधीन उत्पाद की सीजनल उपलब्धता ने भी कभी-कभार इसमें अपना योगदान दिया है।
- (ड) **जन हित:** रक्षोपाय करार के अनुच्छेद-3 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है  
 “कोई सदस्य गाट 1994 के अनुच्छेद-10 के अनुसरण में विगत रूप से सुस्थापित और सार्वजनिक की गई प्रक्रियाओं का अनुसरण करके सक्षम प्राधिकारियों के किसी सदस्य द्वारा निम्नलिखित जांच करके रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग कर सकता है। इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को तर्क संगत सार्वजनिक नोटिस और सार्वजनिक सुनवाई अथवा अन्य कोई समुचित साधन शामिल होगा जिसमें आयातक, निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार अपने विचार एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें जिसमें अन्य पक्षकारों द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरण का प्रत्युत्तर देने तथा अन्य बातों के साथ-साथ अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके कि क्या रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग करना जनहित में होगा या नहीं। सक्षम प्राधिकारी एक रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे जिसमें अपने निष्कर्ष बतायेंगे और तथ्यों तथा विधि के सभी संगत मुद्दों के संबंध में तर्कसंगत निष्कर्ष प्रदान करेंगे।”
81. अर्थव्यवस्था में कभी-कभार विभिन्न आर्थिक पक्षकारों के हित विभिन्न एवं परस्पर प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण विभिन्न पक्षकारों को अलग-अलग ढंग से प्रभावित कर सकता है और यह प्रभाव सभी विभिन्न आर्थिक पक्षकारों के लिए हमेशा सर्वाधिक उपयुक्त हो यह भी संभव नहीं है, खासकर तब जबकि उनके हित परस्पर प्रतिस्पर्धी हो। अतः विभिन्न आर्थिक पक्षकारों समूहों के हितों का उपलब्ध सूचना के आधार पर विश्लेषण किया गया।
82. जन हित के प्रश्न के संबंध में किये गये लिखित प्रस्तुतिकरण में घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि उन्होंने भारत में बढ़ती मांग को पूरा करने तथा भारत में रोजगार सृजित करने के लिए उन्होंने महाड, महाराष्ट्र में एक नई उत्पादन सुविधा की स्थापना की है और उस पर भारी निवेश किया है और अतः भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण करना तथा शैशव काल में मौजूद घरेलू उद्योग को तत्काल संरक्षण प्रदान करना जनहित में होगा। तथापि उन्होंने उनके उत्पाद का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले अधोगामी उद्योग पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के न्यूनतम प्रभाव, यदि कोई, और उस अधोगामी उद्योग द्वारा विनिर्मित अंतिम उत्पाद का प्रयोग करने वाली जनता पर उसके परिणामी प्रभाव के संबंध में सांख्यिकीय आंकड़ों के रूप में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।
83. दूसरी ओर, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुतिकरण किया है कि दो उपभोक्ता सेगमेंट अर्थात् पाइराजोलोन उद्योग और फार्मा उद्योग भारत में मिथाइल एसिटोएसिटेट की अधिकांश खपत करते हैं। उन्होंने पुनः यह प्रस्तुतिकरण किया है कि पाइराजोलोन उत्पादकों का बड़े पैमाने का संगठन नहीं है और वे छोटे-छोटे व्यापारी उद्यम हैं जो अपने उत्पाद में काफी लंबे समय तक वित्तीय घाटे को सहन करने में समर्थ नहीं होते हैं। रक्षोपाय शुल्क का किसी प्रकार का अधिरोपण इन विनिर्माताओं को पाइराजोलोन का विनिर्माण बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और इसके परिणाम स्वरूप मिथाइल एसिटोएसिटेट की मौजूदा मांग समाप्त हो जाएगी। इन पक्षकारों ने पुनः यह प्रस्तुतिकरण किया है कि फार्मा उद्योग मिथाइल एसिटोएसिटेट की खपत

एमोक्सी फार्मूलेशनस का उत्पादन करने के लिए करते हैं जो डीपीसीओ के अंतर्गत कवर होता है। चूंकि इस उद्योग का अंतिम उत्पाद डीपीसीओ के अधीन होता है इसलिए यह उद्योग बाजार में अपने उत्पाद की कीमतों में वृद्धि नहीं कर सकता है। तथापि इसके कच्चे माल अर्थात् मिथाइल एसिटोएसिटेट पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से इसकी लागत में वृद्धि हो जाएगी और एमोक्सी फार्मूलेशनस का उत्पादन अर्थक्षम नहीं रहेगा जिससे इस उद्योग को अपना उत्पादन बंद करने अथवा किसी अन्य विकल्प की ओर देखने के लिए मजबूर होना पड़ जायेगा। यह कारक उपभोक्ता/जनहित में नहीं होंगे।

84. घरेलू उद्योग ने अपने प्रत्युक्ति प्रस्तुतिकरणों में उपर्युक्त प्रस्तुतिकरणों का खंडन यह उल्लेख करके किया है कि अधोगामी फार्मास्युटिकल्स उत्पादक अनन्यतः निर्यातोन्मुखी इकाईयां हैं और वे निर्यात के लिए स्थापित की गई हैं तथा भारतीय घरेलू मांग को पूरा नहीं करती हैं। तथापि उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।
85. जहां तक कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाये गये इस प्रश्न का सवाल है कि भारत में पाइराजोलोन के उत्पादकों को संभावित क्षति होगी, इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा यह प्रस्तुतिकरण किया गया है कि अधोगामी उत्पाद के पाटन के कारण अधोगामी उत्पादकों द्वारा सहन की गई क्षति के लिए विचाराधीन उत्पाद पर उदग्रहण किये जा रहे रक्षोपाय शुल्क को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पाइराजोलोन के उत्पादकों को एमएई पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित न होने के बावजूद उन्हें गंभीर क्षति पहले से ही हो रही है जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन उत्पादकों की चिंता का कारण अपर्याप्त पाटन रोधी शुल्क है न कि विचाराधीन उत्पाद पर उदग्रहण किया जा रहा शुल्क।
86. इस मामले की जांच की गई है। यह नोटिस किया गया कि घरेलू उद्योग भारत में विचाराधीन उत्पाद का एक मात्र उत्पादक है और उसका बाजार में 100 प्रतिशत बाजार हिस्सा है। यद्यपि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि यदि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को लाभ होगा इससे घरेलू उद्योग की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति बढ़ जायेगी। तथापि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके साथ ही घरेलू उद्योग ने भी अपने इस तर्क के समर्थन में की रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना अंततः जनहित में होगा कोई मूर्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। उन्होंने केवल उल्लेखन ही किया है। यह भी देखा गया है कि यह विचाराधीन उत्पाद सीजनल रूप से उपलब्ध है। घरेलू उद्योग इस विचाराधीन उत्पाद के साथ-साथ कई अन्य उत्पादों का एक ही फैक्ट्री में अन्य उत्पादों के साथ संयोजन करके उत्पादन करते हैं जिसका पहले वर्णन किया जा चुका है। इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता 4950 मी.टन तक सीमित है परंतु वे उत्पाद के स्विंग मोड का प्रयोग करके अपना उत्पादन 7260 मी.टन तक कर सकते हैं।
87. एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आयातों की चक्रीय प्रवृत्ति विवेकाधीन है। उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि आयातों की मात्रा पहली तिमाही और द्वितीय तिमाही में अधिक रही है जबकि तृतीय तिमाही और चतुर्थ तिमाही में इसकी मात्रा कम रही है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तृतीय तिमाही और चतुर्थ तिमाही के दौरान जब आयात न्यूनतर रहे तो घरेलू बिक्रियों में अचानक वृद्धि हो गयी। यह इस कारण है कि पहली दो तिमाहियों के दौरान घरेलू उद्योग अपनी सीमित क्षमता का उपयोग मोनोमिथाइल एसिटोएसिटेट (एमएमए) का उत्पादन करने में करते हैं जिससे उन्हें मिथाइल एसिटोएसिटेट की बिक्री में अधिक लाभ प्राप्त होता है क्योंकि एमएमए की मांग सीजनल होती है जो केवल पहली दो तिमाहियों तक ही सीमित रहती है। अतः घरेलू उद्योग का यह अभिकथन कि आयातों से घरेलू उद्योग का भारतीय बाजार में मिथाइल एसिटोएसिटेट से विस्थापन हो रहा है, असत्य है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष की पहली दो तिमाहियों में एमएमए के उत्पादन का अनुपात एमए के उत्पादन की तुलना में अधिक रहा है जैसाकि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

	एमएए		एमएमएए	
	उत्पादन	बिक्री	उत्पादन	बिक्री
2010-11 (पहली तिमाही)	100	60	1041	1006
2010-11 (दूसरी तिमाही)	342	232	1362	1340
2011-12 (पहली तिमाही)	305	453	1834	1858
2011-12 (दूसरी तिमाही)	547	520	1521	1507
2012-13 (पहली तिमाही)	514	542	1845	1880
2012-13 (दूसरी तिमाही)	382	336	616	582

88. इस मामले में वास्तविक क्षमता उपयोग को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि इस विचाराधीन उत्पाद की मांग एवं आपूर्ति में भारी अंतर है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति, यदि कोई, के लिए उसकी संस्थापित क्षमता के चुनिंदा उपयोग को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जिसे वे एमएए और एमएमएए का निर्माण करने के लिए अदल-बदल कर प्रयोग करते हैं। जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़े स्पष्टतः यह दर्शाते हैं कि इस उत्पादन के हिस्से में संगत रूप में आयातों की कीमत पर वृद्धि हो रही है और सभी आर्थिक पैरामीटर जैसे उत्पादन, बिक्री, मालसूची, उत्पादकता, रोजगार और लाभप्रदायकता वास्तविक आधार पर पर्याप्त सुधार प्रदर्शित कर रहे हैं। आयातों में गिरावट आ रही है और मांग में वृद्धि हो रही है इसका आशय यह है कि इस विचाराधीन उत्पाद की घरेलू आपूर्ति में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, यह पहले से ही रिकार्ड में उपलब्ध है कि इस विचाराधीन उत्पाद का भारत में भारी संख्या में सेक्टरों जैसे फार्मा, उद्योग, रंजक, पेंट आदि में प्रयोग किया जाता है और कुछ मामलों में इसका प्रयोग पाइराजोलोन का उत्पादन करने के लिए किया जाता है कि जिसपर पाटनरोधी शुल्क पहले से ही अधिरोपित है। प्रासंगिक बिन्दु यह है कि घरेलू उद्योग यह साक्ष्य प्रस्तुत करने में समर्थन नहीं हो पाया है कि इस विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण किस तरह इन उपभोक्ताओं को प्रभावित नहीं करेगा, जिनमें से कुछ तो नाजुक फार्मा सेक्टर में हैं और यह कि यह प्रभाव इतना कम रहेगा कि वह जनहित में होगा। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग द्वारा किये गये दावे के अनुसार वे स्विंग रूट के जरिए मांग को पूरा करने में सक्षम हैं, इस परितर्वन का संभावित प्रभाव इस उत्पाद के अंतिम प्रयोक्ता पर पड़ेगा और यह तथ्य कि उस उत्पाद को बाधित/प्रतिबंधित/आसुशोधित/निरुद्ध करेगा जिसका निर्माण एमएए की लागत पर किया जा रहा है परंतु इसका उल्लेख जांच के दौरान बिल्कुल ही नहीं किया गया है। विभिन्न उत्पादों के अंतिम प्रयोक्ताओं पर ऐसे प्रभाव के परिमाण संबंधी किसी आंकड़े का संपूर्ण अभाव यह स्पष्ट करता है कि घरेलू उद्योग ने जन हित का कोई आकलन नहीं किया गया है।
89. इसके अतिरिक्त ऋणात्मक कीमत अधोरदन का आशय है कि प्रयोक्ता/जनता को अंततः अधिप्रापण का अर्थक्षम विकल्प होता है। इस परिदृश्य में यदि घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क के रूप में संरक्षण प्राप्त करता है तो इससे घरेलू वस्तु की तुलना में आयातित वस्तुएं मंहगी हो जायेगी और उसके द्वारा इस उत्पाद के प्रयोक्ताओं के लिए अनुचित बाजार परिस्थितियां सृजित हो जायेगी और कीमत में उतार-चढ़ाव सस्ते अधोगामी उत्पाद जैसे दवाईयां की उपलब्धता बाधित हो जायेगी। इस संबंध में घरेलू उद्योग का यह तर्क कि आयात कीमतों में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है जिस अनुपात में विदेशों में कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है परंतु इसकी वर्तमान जांच से कोई प्रासंगिकता नहीं है।
90. अतः यह तथ्य स्पष्ट है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात बहुत ही प्रतिस्पर्धी कीमतों पर किया जा रहा है और अप्रैल, 2013 से जुलाई, 2013 (जांच की अवधि के पश्चात की अवधि) की अवधि ने घरेलू उद्योग का निष्पादन घरेलू उद्योग को किसी प्रकार की गंभीर क्षति अथवा गंभीर चिंता कारित करने की किसी चुनौती का संकेत नहीं मिलता है।

91. उपर्युक्त के मद्देनजर, घरेलू उद्योग द्वारा तथा सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये बिन्दुओं पर विचार करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि मिथाइल एसिटोएसिटेट पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना किसी भी रूप में जन हित में नहीं होगा।

**IX. गंभीर क्षति कारित करने वाले अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न करने वाले अन्य कारक**

92. सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 के अनुबंध के पैरा 2 में यह निर्धारित किया गया कि उप पैराग्राफ (1) में उल्लिखित निर्धारण तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक, उद्देश्यपरक साक्ष्यों के आधार पर जांच में यह अभिव्यक्त नहीं हो जाता है कि संबंधित वस्तु के बढ़ते आयातों और गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कोई कारणात्मक संबंध है और यदि घरेलू उद्योग को संवर्धित आयातों के अलावा अन्य कारक भी “गंभीर क्षति” कारित कर रहे हैं तो उस “गंभीर क्षति” के लिए संवर्धित आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

93. इस कारण उन संभावित अन्य कारकों की जांच की गई जो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कारक प्रासंगिक हैं-

**(क) उत्पाद की मांग:** जब मांग में समग्र वृद्धि होती है तो यह उम्मीद की जाती है उसके अनुरूप ही घरेलू उद्योग की बिक्रियां भी बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित होगी; ऐसा भी हो सकता है कि आयातों द्वारा भी ऐसी ही प्रवृत्ति प्रदर्शित की जाए। तथापि, इस मामले में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट प्रदर्शित हुई है जबकि आयातों में वृद्धि प्रदर्शित हुई है। अतः यह स्पष्टतः देखा जा सकता है कि संवर्धित आयातों ने मांग के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। तथापि, यह भी एक तथ्य है कि घरेलू उद्योग की कुल क्षमता जांच की अवधि के पश्चात की अवधि (वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही) इस उत्पाद की मांग की तुलना में कम है जिससे न्यूनीकृत अथवा घरेलू उद्योग को किसी भी प्रकार की क्षति का संकेत और संवर्धित आयातों के कारण कोई अन्य नुकसान होने का संकेत नहीं मिलता है।

**(ख) खपत की प्रणाली में परिवर्तन:** घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि इस विचाराधीन उत्पाद के संबंध में भारतीय बाजार में खपत की प्रणाली में किसी प्रकार का कोई वास्तविक परिवर्तन आया है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने भी घरेलू उद्योग के इस दावे का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और इसलिए इसे स्वीकार कर लिया गया है।

**(ग) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं तथा घरेलू एवं विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा:** रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाओं अथवा घरेलू एवं विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा ने घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति में अपना योगदान दिया है। तथापि, यह एक तथ्य है कि घरेलू उद्योग का 100 प्रतिशत बाजार हिस्सा है और आयात इतनी अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर आ रहे हैं उनसे क्षति मार्जिन का विश्लेषण करने के लिए कोई कीमत अधोरदन नहीं हुआ है।

**(घ) निर्यात निष्पादन:** आवेदनकर्ताओं ने विचाराधीन उत्पाद की कुछ मात्रा का निर्यात किया है। तथापि, घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति घरेलू प्रचालनों के कारण हुई है।

**(ङ.) प्रौद्योगिकी में विकास:** आवेदनकर्ता ने दावा किया है कि इस उत्पाद का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इसका खंडन भी नहीं किया है। इसलिए, प्रौद्योगिकी में विकास इस मामले में क्षति का एक कारण नहीं हो सकता है।

94. अतः, यह नोट किया जाता है कि अन्य संभावित कारकों ने घरेलू उद्योग को निर्णायक रूप से क्षति कारित नहीं की है।

**X. आयातों में उद्रेक तथा गंभीर क्षति और गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध**

95. कोरिया-डेयरी मामले में पैनल ने “कारण” का निर्धारण करने के लिए आधारभूत अधिगम का निर्धारण किया है:

“कारणात्मक संबंधों का आकलन करने में हमारा विचार है कि राष्ट्रीय प्राधिकारी को यह विश्लेषण करने की जरूरत होती है तथा यह निर्धारण करना होता है कि क्या उद्योग में विकास, जिनपर गंभीर क्षति प्रदर्शन करने के लिए

राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया, संवर्धित आयातों के कारण हुआ है। कार्य कारण संबंधों के आकलन में राष्ट्रीय प्राधिकारी को उन सभी संगत कारकों का उद्देश्यपरक एवं परिकलनीय प्रकृति का मूल्यांकन करना होता है जिनका उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, यदि राष्ट्रीय प्राधिकारी ने संवर्धित आयातों के अलावा कुछ ऐसे कारक अभिज्ञात कर लिए हो जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची हो तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि इन कारकों द्वारा कारित की गई क्षति को संवर्धित आयातों द्वारा कारित की गई क्षति के रूप में नहीं माना गया है।

कारणात्मक संबंध स्थापित करने में कोरिया को यह प्रदर्शित करना पड़ा कि उसके घरेलू उद्योग को क्षति बढ़ते हुए आयातों के कारण हुई है। दूसरे शब्दों में, कोरिया को यह प्रदर्शित करना पड़ा कि एसएमपीपी के आयात, दुग्ध पाउडर तथा कच्चे दूध का उत्पादन करने वाले, घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की स्थिति का विश्लेषण करने के पश्चात कोरियाई प्राधिकारी को अन्य कारकों द्वारा कारित क्षति के लिए संवर्धित आयातों द्वारा कारित क्षति को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया।<sup>6</sup>

96. कार्यकारण संबंध का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ, उद्देश्यपरक एवं परिमाणात्मक प्रकृति के सभी संगत कारकों, जिनका उद्योग की स्थिति से संबंध है, मूल्यांकन किया गया। इस मामले में, इस संबंध में निम्नलिखित कारक संगत हैं:-
  - (i) घरेलू उद्योग द्वारा यह प्रस्तुतिकरण किया गया है कि संवर्धित आयातों और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है।
  - (ii) आयातों का उतराई मूल्य तर्क संगत लागत की तुलना में बहुत कम है।
  - (iii) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत का निर्धारण आयात कीमत द्वारा किया जाता है।
  - (iv) जिसके परिणामस्वरूप, कम कीमत वाले आयातों की लगातार मौजूदगी के कारण उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री, लाभ, निवेश पर अर्जन और नकदी प्रवाह में गिरावट आयी है।
97. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि आयातों में वृद्धि तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध प्रदर्शित नहीं किया गया है और यह कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति अपने कारणों से हुई है तथा उसके लिए आयातों को जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता है।
98. इस संबंध में, कारणात्मक संबंधों का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित प्रेक्षणों पर भरोसा किया गया है:-
  - (i) जांच की अवधि के दौरान आयातों में समग्र रूप से तथा उत्पादन के संबंध में भारी वृद्धि हुई है।
  - (ii) जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है।
  - (iii) घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की कोई चुनौती प्रतीत नहीं होती है।
  - (iv) यद्यपि वर्ष 2012-13 के अनुरूप मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग के पास स्विंग क्षमता है तथापि यह वर्ष 2013-14 में हुई संभावित मांग के लिए कम पड़ जायेगी।
  - (v) आयातित एमएए का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग के एमएए के बिक्री मूल्य से बहुत अधिक है।
  - (vi) कोई कीमत अधोरदन नहीं हुआ है, इसका आशय यह है कि घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद की बिक्री आयातों के साथ उचित प्रतिस्पर्धा करके कर रहा है, यद्यपि आयातों में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत पर वृद्धि हो रही है।
  - (vii) आयातों के बाजार हिस्से में बढ़ोतरी हुई है और इसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आयी है।
  - (viii) यह उत्पाद मौसम के अनुरूप प्राप्त होता है।
  - (ix) जब वर्ष 2011-12 में आयातों में गिरावट आयी और घरेलू उद्योग का निष्पादन बेहतर हुआ तब घरेलू उद्योग सर्वोच्च घाटा, पिछले वर्ष की तुलना में 3.3 गुणा ज्यादा, हुआ। तथापि वर्ष 2012-13 में आयातों में वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग के लगभग सभी पैरामीटर गंभीर क्षति प्रदर्शित करने लगे तो घरेलू उद्योग को भारी घाटा

<sup>6</sup> कोरिया-डेयरी मामले में पैनल रिपोर्ट, पैरा 7.89 से 7.90

हुआ और यह घाटा विगत वर्ष की तुलना में लगभग 32 प्रतिशत अधिक था। पुनः, वर्ष 2013-14 (अप्रैल, 2013 से जुलाई 2013 तक) में जब घरेलू उद्योग की स्थिति में समग्र सुधार हुआ तो यह घाटा पिछले वर्ष 2012-13 में हुए घाटे की तुलना में 2.5 गुणा बढ़ गया। तथापि, घाटे की यह प्रवृत्तियां कारणात्मक विश्लेषण को संपुष्ट करती हुई प्रतीत नहीं होती है। ऐसा संभवतः कीमत कारक के कारण हुआ है जो सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के अंतर्गत रक्षोपाय जांच के अधीन एक विषय नहीं है।

99. अतः उपर्युक्त कारकों की जांच यह दर्शाती है कि जांच की अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि तथा घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई परंतु अद्यतन अवधि अर्थात् (अप्रैल, 2013 से जुलाई, 2013 तक) के लिए यह कारणात्मक संबंध कायम नहीं रहते हैं।

#### XI. समायोजन योजना

100. सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और उसका आकलन) नियमावली, 1997 के नियम-5(2) में “आयात प्रतिस्पर्धा के साथ सकारात्मक समायोजन करने के लिए किये जा रहे प्रयासों अथवा योजना बनाये गये प्रयासों अथवा दोनों के अभिकथन का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है”। रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार में प्रावधान किया गया है कि कोई सदस्य रक्षोपाय साधन का प्रयोग गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका निराकरण करने और समायोजन सुलभ बनाने के लिए जरूरी समझी गई सीमा तक ही कर सकता है।
101. निर्णायक रक्षोपाय शुल्क का उद्देश्य घरेलू उद्योग को सीमित समय की अवधि प्रदान करना है जिससे वह अपने को पुर्नगठित कर सके ताकि वह आयातों के साथ प्रभावकारी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सके। सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख और सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 16(2) प्रावधान करते हैं कि यदि इस तरह के कोई साक्ष्य नहीं है कि घरेलू उद्योग समायोजन कर रहा है तो इस साधन का संभावित सीमा तक कोई प्रयोग नहीं किया जायेगा।
102. इस मामले में घरेलू उत्पादकों ने समायोजन योजना तैयार की है जो मुख्यतः निम्नलिखित सेक्टरों पर कीमत कटौती के लिए प्रकाश डालती है:
- (i) कच्चा माल
  - (ii) विद्युत एवं उपयोगी वस्तुएं
  - (iii) बिक्री एवं माल सूची प्रबंधन
103. आवेदनकर्ता ने प्रस्तुतिकरण किया है कि विनिर्माण सुविधाओं की खरीद एक अन्य मालिक से की गई थी और यह कि उन्होंने इस सुविधा का उन्नयन विश्व स्तर के अनुरूप करने के लिए इसमें भारी धन राशि का निवेश पहले ही कर दिया है। इसके अतिरिक्त, कच्चे माल पर उनका फोकस परिवर्तन मानदंडों और चुनिंदा रूप से किटैन तथा डाईकिटैन में सुधार करके मुख्य कच्चे माल की खपत में कमी लाने और बैच प्रक्रिया से परिवर्तन करके सतत प्रक्रिया में लाने से संबंधित है। उनका इरादा तेल के स्थान पर कोयले का प्रयोग करना भी है जिससे कि ऊर्जा लागत में कमी की जा सके। उन्होंने अपनी बिक्रियों में वृद्धि करने तथा उपरिशीर्ष लागतों में कमी करने के लिए माल सूची प्रबंधन करने की कुशल योजना तैयार की है। यह सभी सकारात्मक समायोजन पिछले 2-3 वर्षों की अवधि में तैयार किये गये हैं।
104. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने अपेक्षित समायोजन योजना प्रदान नहीं करायी है अर्थात् उनकी योजना बिना किसी ठोस विवरण के है और यह कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई समायोजन योजना में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है।
105. इस संबंध में, यह नोटिस किया गया कि घरेलू उद्योग ने एक ऐसी समायोजन योजना प्रदान करायी है जो 2-3 वर्षों की अवधि तक फैली है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिये गये तर्क के अनुसार घरेलू उद्योग ने किसी ठोस समयबद्ध योजना के लिए समायोजन योजना की परिकल्पना नहीं की है जो सक्रिय एवं समायोजन योजना की संपूर्ण अवधि के लिए प्रस्तावित हो। तथापि ऐसा संभवतः इस कारण से हो सकता है कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2010-11 में शुरुआती निवेश पहले ही कर दिया है और वे अपने द्वारा किये गये निवेश के परिणामों की

प्रतिक्षा आज तक कर रहे हैं जिसके आधार पर वे उसमें सुधार करना चाहते हैं। इनकी कारकों के कारण घरेलू उद्योग ने चार वर्षों की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। तथापि, यह तथ्य बना हुआ है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान करायी गई समायोजन योजना केवल प्रस्तावित है और जैसा कि उल्लेख किया गया है कि इसमें परिवर्तन/सकारात्मक समायोजन 2-3 वर्षों की अवधि में किया गया जायेगा, परंतु इस परिवर्तन के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

## **XII. निष्कर्ष एवं सिफारिश**

- (i) आयातों में तत्काल विगत वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में समग्र रूप से भारी वृद्धि हुई है। तथापि, यह वृद्धि जब इसकी तुलना आधार वर्ष से की जाती है तो यह उतनी अधिक नहीं है क्योंकि आधार वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में आयातों में कमी आ गई थी। यद्यपि वृद्धि काफी महत्वपूर्ण है तथापि इस मामले में यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2012-13 में, आधार वर्ष से इसकी तुलना करने पर मांग में वृद्धि अपर्याप्त/मामूली सी ही हुई है। तथापि, यह निष्कर्ष भी नहीं निकाला जा सकता है कि आयातों में संपूर्ण जांच की अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि हुई है तथापि यह नोट किया जाता है कि आयातों में उतनी अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है जिससे गंभीर क्षति कारित हो सके।
  - (ii) अप्रैल से जून, 2013 और 2013-2014 (वार्षिकीकृत की अवधि के लिए विश्लेषण करने पर, पक्षपात रहित निष्कर्ष निकालने के लिए, यह प्रेक्षित किया जाता है कि बाजार हिस्सा, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग जैसे कारकों के आधार पर घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ है। आयातों में गिरावट भी आयी है। उपर्युक्त के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की कोई चुनौती उत्पन्न नहीं है।
  - (iii) घरेलू उद्योग का यह आकलन कि आयात घरेलू उद्योग का एमएए के लिए भारतीय बाजार से विस्थापन कर रहे हैं, गलत प्रतीत होता है जैसा कि संगत पैराग्राफों में स्पष्ट किया गया है। वास्तव में घरेलू उद्योग द्वारा अपनी उपयुक्तता के अनुरूप एमएए के उत्पादन को प्रतिबंधित/विनियमित करना ही है जिसके कारण इस उत्पाद के आयातों पर, खासकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रभाव पड़ा कि घरेलू उद्योग ने प्रश्नाधीन उत्पाद की कुल मांग की तुलना में बेशी क्षमता का दावा किया है।
  - (iv) घरेलू उद्योग यह प्रदर्शित करने में अक्षम रहा है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए बाजार में अनपेक्षित विकास हुआ है। इसके विपरीत, उनके द्वारा प्रदान करायी गई सूचना भी उनके मामले का समर्थन नहीं करती है जैसा कि ऊपर संगत पैराग्राफों में की गई जांच से स्पष्ट होता है। अतः, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग अनपेक्षित परिस्थितियों से संबंधित अपने दावे को ठोस/मूर्त साक्ष्य से बनाये रखने में सक्षम नहीं हो पाया है जिनके कारण विचाराधीन उत्पाद के आयातों में भारी वृद्धि हुई है।
  - (v) घरेलू उद्योग स्पष्ट रूप से यह अभिव्यक्त करने में भी सक्षम नहीं हो पाया है कि इस विचाराधीन उत्पाद पर चार वर्षों के लिए रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण करना पूरी तरह से जनहित में होगा। जब गंभीर क्षति की चुनौती है ही नहीं और यह तथ्य कि आयात प्रतिस्पर्धी कीमतों पर हो रहे हैं, इसलिए इस मामले में सार्वजनिक हित पूरा करने की जरूरत ही नहीं उठती है।
106. इसके परिणामस्वरूप, मिथाइल एसिटोएसिटेट के आयातों पर किसी भी रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश नहीं की जाती है।

[फा. सं. डी 22011/8/2013/पार्ट ए /1562 ]

राम तीर्थ, महानिदेशक

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue )**  
**DIRECTORATE GENERAL (SAFEGUARDS)**  
**Customs and Central Excise**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8<sup>th</sup> October, 2013

**Subject:- Safeguard investigation concerning imports of Methyl Acetoacetate-Final Findings.**

**G. S.R. 676(E).**— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 thereof;

**I. Procedure**

1. An application has been filed before me under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 (hereinafter referred to as Safeguard Rules) by M/s. Laxmi Organic Industries Limited, Mumbai through their consultant M/s ELP Advocates & Solicitors for imposition of Safeguard Duty on imports of Methyl Acetoacetate (hereinafter referred to as MAA) into India to protect the domestic producers of Methyl Acetoacetate against serious injury/threat of serious injury caused by the increased imports of Methyl Acetoacetate into India.
2. In order to satisfy the requirements under Rule 5 of the said Safeguard Rules, the information presented by the applicant was got verified by on-site visit to the plants of the domestic producers to the extent considered necessary. The non-confidential version of verification report is kept in the public file. On being satisfied that the requirements of Rule 5 were satisfied, the Notice of Initiation of Safeguard investigation concerning imports of Methyl Acetoacetate into India was issued under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 on 6<sup>th</sup> June, 2013 and was published in the Gazette of India Extraordinary on the same day.
3. A copy of the Notice of Initiation dated 6<sup>th</sup> June, 2013 along with copy of non-confidential version of the application filed by the Domestic Industry were forwarded to the Central Government, in the Ministry of Commerce and other Ministries concerned, Governments of major exporting countries through their embassies in India, and the Interested Parties listed below, in accordance with Rule 6(2) and 6(3) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997:

**A. Domestic Producers**

- (i) M/s Laxmi Organic Industries Limited, Chandramukhi, 3<sup>rd</sup> floor, Nariman Point, Mumbai-400021.

**B. Importers/Users:-**

- (i) C J Shah, 105, 10<sup>th</sup> floor, Bajaj Bhawan, Nariman Point, Mumbai-400021;
- (ii) Hazel, Embassy Centre, Jamnalal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai-400021;
- (iii) Sarna Chemicals Pvt Ltd, GIDC Vapi, Pardi, Valsad, Gujarat-396185;
- (iv) SM Chemicals, 2-2-1137/5/B, New Nallakunta, Opposite Vijaya Apartments, Hyderabad, AP-500044;
- (v) Arch Pharmalabs Ltd, "H" wing, 4<sup>th</sup> Floor, Tex Centre, Off Saki Vihar Road, Chandivali, Andheri(E), Mumbai-400072;
- (vi) Aurobindo Pharma Ltd, Plot # 2, Maitri Vihar, Ameerpet, Hyderabad -500038, AP;
- (vii) Colourtex Industries Ltd, Survey No 91, Opp. Navin Fluorine Industries, Bhestan-395023, Surat, Gujarat;
- (viii) Kailash Chemicals, 191, Phase I, GIDC Estate, Vatva, GIDC, Ahmedabad-382445;
- (ix) Dia Chemie, 2<sup>nd</sup> floor, 56/58, Garibdas Street, Vadgadi, Mumbai-400003;
- (x) Nutan Die Chem, Plot No 2428, GIDC-Sachin, Distt Surat-394230;
- (xi) Polygon Chemicals, Plot No 337, GIDC Industrial Estate, Odhav, Ahmedabad-382415;
- (xii) Prima Chemicals, Plot No 337, GIDC Industrial Estate, Odhav, Ahmedabad-382415.

**C. Exporters:-**

- (i) Qingdao Double Peach Speciality Chemicals (Group) Co Ltd, 28, Hangzhou Road, Qingdao, China PC. 266031
- (ii) Zhangjiang Hope Chemicals Co Ltd, Nasha Town, Zhangjiagang City, China.
- (iii) Nantong Acetic Acid Chemical Co Ltd, No 968, Jiangshan Road, Economic & Technological Development District, Nantong City, JiangsuProvince, China.
- (iv) Wang Long Group Co Ltd, Wanglong Industrial Zone, Yuyao 315476 Ningbo, China.
- (v) Diacel, 1-1, Shinko-cho, Myoko-shi, Niigata 944-8550, Japan.
- (vi) Mitsuboshi, 1818, Ohaza-Nishinoshima Komaki 485-0077 Japan
- (vii) Lonza CH-3930 Visp, Switzerland
- (viii) Eastman PO Box 431 Kingsport, Tennessee 37662 USA



**D. Exporting Nations:-**

- (i) The Embassy of United States of America, Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi-110021;
- (ii) Trade Representation of the Russian Federation, Block 50-E, Nyay Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021.
- (iii) The Embassy of People's Republic of China, 50-D, Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi-110021.
- (iv) Embassy of Switzerland, Nyay Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021
- (v) The Trade & Economic Section, Delegation of European Union to India, 65, Golf Links, New Delhi-110003

4. Questionnaires were sent to the known exporters, known importers/users in India and other Interested Parties as per the information available with request to make their views known in writing within 30 days of the Notice of Initiation. Responses were received from the following parties:-

- a) M/s Eastman Chemical Company through their Advocates AZB & Partners.
- b) M/s Nantong Acetic Acid Chemical Co Ltd, China PR through M/s WTC & Advocates.
- c) M/s Xinhua Pharmaceuticals (Shouguang) Co Ltd China PR through M/s WTC & Advocates.
- d) M/s Jiangsu Tiancheng Biochemical Products Co Ltd, China PR through M/s WTC & Advocates.
- e) M/s Qingdao Double-Peach Speciality Chemical (Group) Co Ltd through WTC & Advocates.
- f) M/s C J Shah & Co through M/s TPM Consultants
- g) M/s Prima Chemicals through M/s TPM Consultants
- h) M/s Polygon Chemicals through M/s TPM Consultants
- i) M/s Aurobindo Pharma Ltd.

5. (A) Requests to consider them as Interested Parties were received from the following parties:-

- a. Importer: M/s Nutan Dye Chem, Surat (Gujarat)
- b. Importer : M/s Polygon Chemicals, Ahmedabad
- c. Importer: M/s Prima Chemicals, Ahmedabad
- d. Exporting Nation: Trade and Economic Section, Delegation of the European Union to India, 65 Golf Links, New Delhi-110003
- e. Exporting Nation : Trade Representation of the Russian Federation in the Republic of India and Ministry of Economic Development of Russia, New Delhi.

All the requests were accepted

(B) The under mentioned parties sought extension of time for submission of a detailed reply in terms of Rule 6(4) of Safeguard Duty Rules, 1997:-

- a. M/s Polygon and Prima Chemicals
- b. M/s C J Shah & Co
- c. M/s Lonza India Pvt Ltd
- d. M/s Aurobindo Pharma Ltd

Extension of time as sought in each case was allowed.

6. The views expressed by the Interested Parties have been taken into account in making appropriate determination. The non-confidential information received or acquired has been kept in the public file.

**II. Views of the Interested Parties (Post-Initiation)**

7. Responses to the Notice of Initiation were received from importers/exporters/exporting nations, as given below:

1. Letter dated 17<sup>th</sup> June, 2013 from Taipei Economic and Cultural Centre, New Delhi
2. M/S Sojitz India Pvt Ltd, New Delhi
3. M/S Lonza India Pvt Ltd, Hyderabad
4. M/s Nutan Dye Chem, Surat
5. M/s Aurobindo Pharma Ltd, Hyderabad
6. M/S Eastman Chemical Company, Tennessee
7. M/s Polygon Chemicals, Ahmedabad
8. M/S C J Shah & Co, Mumbai
9. M/S Prima Chemicals, Ahmedabad
10. M/S Qingdao Double-Peach Specialty Chemicals(Group) Co.,Ltd, China PR.
11. M/S Nantong Acetic Acid Chemicals Co., Ltd, China PR.
12. M/S Jiangsu Tiancheng Biochemical Products Co., Ltd, China PR
13. M/S Xinhua Pharmaceutical(shouguang) Co.,Ltd, China PR
14. M/S Laxmi Organic Industries Ltd, (Domestic Industry)

The issues raised are not being reproduced for the sake of brevity, but have been discussed at appropriate places in making determinations.

**III. Public Hearing:-**

8. A public hearing was held on 26<sup>th</sup> August, 2013, notice for which was sent on 5<sup>th</sup> August, 2013 to the Interested Parties. In the said Public Hearing, Domestic Industry, i.e., M/s Laxmi Organic Industries Limited as well as the following Interested Parties attended:-

1. Exporters from China PR represented by M/s WTC Consultants & Advocates as below:-

- a. China Petroleum and Chemical Industry Federation.
- b. Qingdao Double Peach Speciality Chemicals (group) Co. Ltd.
- c. Nantong Acetic Acid Chemical Co. Ltd.
- d. Jiangsu Tiancheng Biochemical Products Co. Ltd.
- e. Xinhua Pharmaceutical(Shougang) Co. Ltd.

2. Importers/Users from India represented by M/s TPM Advocates, as below:

- a. C.J. Shah, Mumbai,
- b. Prima Chemicals, Ahmedabad,
- c. Aurbindo Pharma Ltd., Hyderabad
- d. Polygon Chemicals, Ahmedabad

3. Importer/User in India- M/s Nutan Dye Chem, represented by Mr. P. K. Shah.

4 Exporter from the USA- M/s Eastman Chemical & Co., represented by M/s AZB & Partners.

9. All Interested Parties who participate in the public hearing are required to file a written submission of the views presented orally in terms of Sub Rule (6) of Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997. Thereafter, copy of written submissions filed by an Interested Party is made available to all other Interested Parties. Interested Parties are also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other Interested Parties. In the course of the Public Hearing in this matter on 26<sup>th</sup> August, 2013, the Domestic Industry made oral submissions followed by a written submission. All Interested Parties who participated in the public hearing were requested to file a written submission of the views presented orally in terms of sub rule (6) of rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997. Copies of written submissions filed by the interested parties were made available to all other Interested Parties. Interested Parties were also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other Interested Parties. The delay in filing written submissions/updated injury data on the part of M/s WTC Consultants and M/s ELP Advocates, respectively, were condoned after considering the reasons cited by them.

10. Trade & Economic Section, Delegation of European Union to India sent a confirmation for participation in the Public Hearing and making a submission. However, no representative from their side either participated in Public Hearing or made any written submissions.

11. Accordingly, all views expressed by the Interested Parties in the written submissions post-initiation as well as post-hearing were examined and have been taken into account in making appropriate determination.

#### IV. VIEWS OF INTERESTED PARTIES (Post-Hearing)

##### Views of Domestic industry through M/s ELP Advocates & Solicitors

12. The Domestic Industry submitted as follow:-

##### (a) Increased imports of subject goods into India:

(i) That they differ with the views of WTO Appellate Body in Argentina-Footwear case so far as the examination of trend in imports over a five year period is concerned. The use of the present tense of the verb phrase “is being imported” in both Article 2.1 of the Agreement on Safeguards and Article XIX:1(a) of the GATT 1994 indicates that it is necessary to examine recent imports and not simply trends in imports during the past five years.

(ii) Imports have increased in absolute terms as well as in relation to production, sales and demand during the injury period. On end point to end point basis, the imports have increased by 28%, whereas on annual basis the imports have increased by 42% in 2012-13.

(iii) From Q4 2010-11 onwards, there is sudden, sharp and significant increase in imports.

(iv) An analysis of imports from 2009-10 when the domestic industry was not in operation is not correct. The DI submitted that the Domestic Industry commenced its operations starting from May-2010 and is the sole producer of the subject goods in India. Further, the erstwhile domestic producer M/s. Clariant shut down its operations in 2009-10 and as such there was no Domestic Industry in 2009-10. Hence, an analysis of imports from 2009-10 when the Domestic Industry was not operation is not only incorrect and misrepresentative but would lead to a

serious distortion in the analysis of the imports into India. Further, the level of imports in 2012-13 has substantially increased, despite the presence of the Domestic Industry, which clearly establishes that there is a sudden, sharp and significant increase in imports into India.

**(b) Unforeseen Circumstances:**

The DI has submitted the following reasons, which as per their understanding, constitute the unforeseen circumstances in the present case:-

**(i) Unexpected drop in consumption in European Markets:**

The European markets have reported an unexpected drop in demand as a result of the massive capacities of the subject goods in foreign countries and the foreign producers have resorted to increased exports to India.

**(ii) Additional Capacities in China PR:**

There has been a sudden increase in Chinese capacities leading to further diversion of imports to India. In fact, from the non-confidential Exporters Questionnaires filed, it is clearly seen that M/s Xinhua Pharmaceutical (Shougang) Co. Ltd., China PR and M/s Qingdao Double Peach Specialty Chemicals (Group) Co. Ltd. have recently set up plants in 2012-13 and have admitted to having made exports to India. Further, another producer from China, viz., M/s Ningbo Wanglong Tech Co. Ltd., has stated that the company is looking forward to start exporting to India. In fact, according to market intelligence, it appears that the installed capacity of M/s Ningbo Wanglong Tech Co. Ltd. is about eight times the installed capacity of the Domestic Industry. The above admissions clearly indicate that there is bound to be continued incessant imports to India at increasing volumes.

**(iii) Unforeseeably low pricing of imports despite increase in raw material Costs:**

The raw material prices were increasing throughout the course of the Period of Investigation. However, despite the global increase in raw material prices, the import prices increased only marginally. As India is a price attractive market, the low priced imports were well received by the consumers. Hence, the low priced imports led to an increased import into India.

**(c) Serious Injury:**

Despite the global increase in raw material prices, the import prices increased only marginally.

- (i) Production of domestic industry significantly declined in 2012-13.
- (ii) The capacity utilization of the domestic industry significantly declined in 2012-13 to 41%.
- (iii) Domestic sales have declined steeply in 2012-13 to 2017 MT.
- (iv) Productivity of the domestic industry increased upto 2011-12 and thereafter declined drastically.
- (v) The demand of the subject goods has increased over the period of investigation by 24%. However, the sales of the domestic industry have increased only by 16%, whereas the imports have increased by 28%. Increase in imports is at a greater rate than the increase in demand.
- (vi) Market share of the domestic industry has been severely impacted by the increased imports. It has declined in recent period.
- (vii) Domestic Industry has suffered significant losses during the financial years 2011-12 and 2012-13.

13. It can be clearly seen that although the cost of sales has increased by 18% in the period of investigation, in line with the increase in raw material prices, the selling prices of the Domestic Industry has increased only by 8% to compete with the landed price of the imports. In fact, the Domestic Industry is being forced to sell at the prices offered by the imports. Hence, although there is minimal under-cutting, there is significant under-selling and the Domestic Industry is selling even below the cost of sales.

**(d) Threat of Serious Injury:**

14. It is submitted that there is a clear and imminent danger of serious injury to the Domestic Industry on account of the continued imports of the subject goods into India. In fact, the Domestic Industry has received a communication from a foreign producer offering it to shut-down their domestic production to eliminate the competition created by the Domestic Industry and facilitate imports into the country.

15. Further, the market share of the Domestic Industry has been captured by the increased imports of the subject goods. In light of the unabated imports of the subject goods, a further decline in the market share of the Domestic Industry is threatened as well. The resultant serious injury is bound to impact the Domestic Industry severely.

16. It is also pertinent to note that new capacities have been installed in China PR and there is significant idle capacity in EU and US. While present imports continue to cause serious injury to the Domestic Industry, the potential for further production and exports from these countries is bound to lead to continued injury to the Domestic Industry.

17. Hence, there is a clear and imminent danger of serious injury to the domestic industry on account of continued imports of the subject goods into India.

**(e) Causal Link:**

18. There is a direct causal link between the increased imports and the serious injury to the domestic industry. It is submitted that the subject goods are sold in direct competition with the imports. The landed price of imports is significantly lower than reasonable costs and the selling prices of the Domestic Industry are determined by the import prices. Consequently, production, capacity utilization, sales, profits, return on investment and cash flow is declining due to continued presence of low price imports.

19. Given the low prices offered by the foreign producers, the imports are surging further despite low prices offered by the Domestic Industry. The Domestic Industry is forced to reduce its prices at lower than cost of sales. As a result of the increased imports, there is a substantial increase in the market share of imports and reduction in market share of the Domestic Industry. Decline in market share of the Domestic Industry has adversely impacted the production and capacity utilization of the Domestic Industry. It is thus evident that injury to the Domestic Industry has been caused by the increased imports.

**(f) Adjustment Plan:**

20. Domestic Industry has submitted an adjustment plan detailing the efforts planned to be taken to make a positive adjustment to import competition, which the domestic industry plans to implement over a period of 2-3 years.

**(g) Public Interest:**

21. In the factual matrix of the case at hand, the Domestic Industry has made significant investments and set-up the new production facility in Mahad, Maharashtra to domestically cater to the growing Indian demand and has generated employment in India. The Domestic Industry is at a nascent stage and requires immediate relief to prevent deterioration due to aggressive marketing and low priced imports by foreign producers as India is a price attractive market.

22. Hence, it is in larger public interest to impose safeguard duty on the imports of the subject goods into India and afford immediate protection to the nascent Domestic Industry and protect the growth and direct and indirect employment opportunities created by the Domestic Industry.

**Views of Exporting Nations:**

23. A confirmation from Trade & Economic Section, Delegation of European Union to India for participation in the Public Hearing and making a submission was received. However, no representative from their side either participated in Public Hearing or made any written submissions.

**Views of Exporters:**

**M/s Eastman Chemical Company filed through M/s AZB & Partners**

24. M/s AZB & Partners vide their letter dated 3<sup>rd</sup> Sep, 2013 requested that their submissions vide letter dated 12<sup>th</sup> July, 2013 may be taken on record as their post-public hearing submissions also and, accordingly, the brief of the submissions is as under-

- (a) The domestic industry has performed remarkably well within only three years of entering Indian MAA market and intends to gain a competitive advantage from Safeguards.
- (b) There are no unforeseen circumstances responsible for the increase of imports.
- (c) Increased imports must be a result of unforeseen developments as per decisions of WTO Appellate Body in US-Lamb case.
- (d) The Petition and the initiation notice are completely silent on the matter of any 'unforeseen circumstances' that may have led to the alleged increase in imports of MAA into India.
- (e) That the foreign producers are export oriented can hardly be termed as unforeseen circumstances.
- (f) In accordance with the ruling of WTO Appellate Body in Argentina-Footwear case, the increase in imports is not recent, sudden, sharp and significant enough both quantitatively and qualitatively to cause or threaten to cause "serious injury".
- (g) Increase in imports must be evident both in end-point-to-end-point comparison and in an analysis of intervening trends over the period.
- (h) Imports have decreased by 40% within a short span of six months, i.e., between second and fourth quarter of 2012-13.
- (i) The petitioner is suffering neither serious injury nor any threat of serious injury. The petitioner fared well all through 2010-11 and 2011-12.
- (j) Since imports of MAA into India are showing a perceptible declining trend beginning the last quarter of the POI and the DI market share is improving, the claim that the DI is suffering injury is entirely misplaced.
- (k) Petitioner have made significant profits during the year 2010-11 and 2011-12.

- (l) Petitioner's claim on reduced profitability may be on account of its losses in the production of other Diketene derivatives or products.
- (m) Petitioner's capacity utilization is consistent with its having been a recent market entrant. Capturing 25% of the market in just three years is a remarkable achievement.
- (n) Petitioner's production has improved in the most recent quarter of 2012-13 i.e. quarter 4.
- (o) A genuine and substantial causal relationship between the imports and the alleged injury suffered by the petitioner is lacking.
- (p) Injury to DI, if any, may be on account of several factors distinct from increase in imports, none of which may be attributed to injury due to increased imports.
- (q) The injury to the DI is on its own account and cannot be attributed to imports.
- (r) The safeguard case is not in public interest as the Petitioner is the sole producer and imposition of safeguard duty would place them in a monopoly position, with the potential for extracting monopoly profits from the Indian customers that use MAA for the production of downstream products.

**25. Views of China Petroleum and Chemical Industry Federation, Jiangsu Tiancheng Biochemical Products Co. Ltd, Nantong Acetic Acid Chemical Co. Ltd, Qingdao Double-Peach Speciality Chemicals (Group) Co. Ltd, Xinhua Pharmaceutical (Shouguang) Co. Ltd, all from China PR filed through World Trade Consultants & Advocates**

- (a) There is no examination of the sufficiency of evidence as prescribed under Rule 5(3) of Safeguard Duty Rules, 1997.
- (b) Domestic Industry has not filed the Questionnaire for Domestic Producers and hence failed to cooperate with the Investigating Authority.
- (c) The application does not contain any evidence on unforeseen developments.
- (d) No viable adjustment plan has been provided by the applicant. No technical details regarding adjustment plan have been provided.
- (e) DGCIS data, which is considered to be the most authentic source of import statistics has not been relied upon in this case.
- (f) There is no surge in imports in the recent past either in absolute or relative terms.
- (g) Claim of the domestic industry that the prices of imports of the subject goods have decreased is totally incorrect and erroneous.
- (h) There is no accumulation of inventories.
- (i) Attributing losses to the domestic industry to imports is totally incorrect. In fact, losses have accrued due to other factors like purchase of an obsolete plant from another company.
- (j) There is absence of causal link between surge in imports and serious injury to the domestic industry.
- (k) The applicant is in expansion mode and wants to monopolise the market by eliminating imports into India.
- (l) The petition did not clarify whether the safeguard measures to the product under consideration would be in the public interest.
- (m) There is absolutely no reason for considering provisional safeguard measures as no critical circumstances exist in this case.

**Views of Importers/User Industry**

**26. M/s Aurobindo Pharma, M/s C J Shah & Co, M/s Nutan Dychem, M/s Prima Chemicals and M/s Polygon Chemicals through M/s TPM Consultants**

- (a) M/s Laxmi Organics ventured into the product knowing very well that Clariant was not performing well in the product.
- (b) There should be evidence in support of unforeseen development claimed by the petitioner. In the instant case, the domestic industry has given no evidence at all in support of unforeseen development claimed by them.
- (c) There is no price undercutting as the petitioner is selling at prices matching the import prices.
- (d) Director General, Safeguards has invariably considered at least three complete years' data in past investigations.
- (e) There is no evidence of increased imports. The domestic industry has not established serious injury. Period of data collection suffers from lot of infirmities.
- (f) The petitioner has discarded most authentic Govt of India data and adopted secondary source data. DGCIS data should have been taken as the same is readily available. Further, even where the importers have used a classification other than the classification dedicated for the product in question, DGCIS reports the correct classification/dedicated classification.
- (g) There is a clear seasonality in the product. Import volumes are higher in Q 1 and Q 2 and lower in Q3 and Q4. In the first two quarters, imports are higher because of lower production of MAA by DI and imports are lower in subsequent two quarters because of higher production by DI.
- (h) Detailed information regarding capacity of Diketene, its consumption pattern and market price etc. should be sought from the petitioner.

- (i) The petitioner is not in a position to meet demand of the product in the country.
- (j) Production, sales, capacity utilization and market share of the company have improved in Q4, 2012-13. Inventory has shown a declining trend in the most recent period. Therefore, there is no serious injury to the domestic industry.
- (k) Imposition of safeguard duty on the product under consideration is not in public interest. Pyrazolone industry which uses MAA as raw material is already undergoing serious injury and anti dumping duty has been imposed on the imports of Pyrazolone. By imposition of safeguard duty on MAA, the Pyrazolone industry would suffer further injury which shall not be in the public/consumer interest.
- (l) Petitioner has claimed excessive confidentiality on the adjustment plan in their application.
- (m) The steps listed by the petitioner do not constitute viable adjustment plan.

#### **V. Rejoinder by Domestic industry**

##### **27. Rejoinder submission by M/s ELP Advocates & Solicitors on behalf of Domestic Industry**

- (a) The claim of Interested Parties regarding insufficiency of evidence is without factual basis as Director General (Safeguards) conducted a complete verification of data with the excise records and other relevant records through on-site visit prior to the initiation notice.
- (b) The contention of Interested Parties that there is no actual increase in price of raw materials without requisite increase in import price is wrong as in this case it is not so and in fact import prices have not increased in proportion to the increased raw material prices.
- (c) While there is a substantial increase in the market share of the imports, the market share of the domestic industry has come down to merely 28% in the last year. Despite lowering prices, the domestic industry has been unable to compete with the abysmally low prices of the imports whereby production has come down.
- (d) As regards the contention of the Interested Parties that the investment of the domestic industry cannot be considered an unforeseen development and that Laxmi Organics ventured into a product knowing very well that the previous producer was not performing well, it is stated that the investment has to be considered in conjunction with various other unforeseen developments like low import prices, a downturn in overseas markets and additional capacities in China as all these factors are intrinsically linked.
- (e) The contention of Interested Parties that there is no noticeable accumulation of inventories of DI is wrong. Inventories of the subject goods have steadily increased and the apparently lower inventories are attributable to the increased frequency and duration of forced shut-downs faced by the DI leading to lower production.
- (f) The contention of Interested Parties that with increased sales the losses of the DI have also increased indicates that there are several other factors that are affecting the profitability, is without basis as the DI is being forced to sell at loss making prices. Therefore, it is obvious that the losses of the DI have increased despite the increase in the sales in 2011-12.
- (g) The Interested Parties have tried to differentiate between the final findings of DOP and PAN and the present investigation by claiming that there was sufficient evidence provided in the two final findings whereas there has been no evidence provided in the present investigation to substantiate the claim of the DI. This is totally wrong. The DI has relied upon ICIS reports as well as Chemistry World reports regarding unexpected drop in EU market consumption. The DI has relied upon the Exporters Questionnaire responses while specifying precisely as to which producers have installed additional capacities of the product in China PR. Further, DI has relied upon a comparison between raw material prices and the prices of PUC imports into India for proving low prices of imports as unforeseen development.
- (h) Some Interested Parties have averred that the low prices of imports could not be classified as an unforeseen development because low import prices while costs increase is a situation of price suppression/depression which are injury parameters and not unforeseen developments. It is baseless. Merely because a parameter is relevant for injury analysis does not mean it cannot be an unforeseen development. Price depression/suppression as economic criteria are relevant for this very reason. They are indicative of possible reasons for a sudden surge in import quantity. It is widely known economic principle that consumers demand will increase in inverse proportion to price. Further, it is not for the DI to predict the pricing policies of the exporters that might have led to such low priced imports, which continue to remain an unforeseen development.
- (i) Interested Parties have contended that fluctuation in raw material prices have caused injury to the DI and the DI is able to sell at prices that match the import prices whereby there is no undercutting or injury. Both these contentions are refuted. The estimation provided by the Interested Parties on the proportion of raw material prices in the cost of the DI is unsubstantiated. Further, DI was forced to reduce its prices in order to match the import prices. Hence, although there is minimal undercutting, there is significant underselling and the DI is selling even below the cost of sales.
- (j) Interested Parties have submitted that the minimum period of investigation, as per past cases in safeguards, ought to be 36 months which is not the case here. It is submitted that the injury demonstrated by the DI's

figures was sufficient to initiate the case and the DI has now filed data for the latest period, thus covering a period of more than three years.

- (k) The Interested Parties have made averments with regard to the unreliability of the import data filed by the DI and have recommended using the DGCIS import data. However, the Interested Parties have conveniently overlooked the fact that the PUC is a complex chemical product that is imported under multiple HS classifications whereby it was considered appropriate to obtain transaction wise data sourced from IBIS. Director General (Safeguards) can call for transaction wise data from the DGCIS and take the same into consideration provided that there are no undue exclusions of the PUC related data from this data.
- (l) The Interested Parties have claimed that surge in imports is not sudden, sharp and significant enough and imports should be analysed for a longer time period, from prior to the operations of the present DI. It is contended that the DI has already placed on record sufficient data and analysis to establish that the increase in imports has been sudden, sharp and significant enough. Imports have increased in absolute terms as well as in relation to the production, sales and demand during the injury period. Further, an analysis of imports from 2009-10 when domestic industry was not in operation is not only incorrect and misrepresentative but also contrary to the requirement of law.
- (m) Interested Parties have contended that a quarterly examination of data reflects a fall in import quantities. It is submitted that with the commencement of operations by the DI in 2010-11, the imports indicate a declining trend upto Q4 2010-11, with customers relying on the DI instead of imports. However, from Q4 2010-11 onwards, there is a sudden, sharp and significant enough increase in imports and the imports increased by 66% in Q1 2011-12 and by 127% in Q2 2012-13 as compared to Q4 2010-11 and continue to increase up to Q4 2012-13. Whether examined on an annual or quarterly basis, there is a sharp, sudden and substantial increase in imports.
- (n) The DI has received a communication from a foreign producer offering it to shut down their domestic operations to eliminate the competition created by the DI and facilitate imports into the country.
- (o) Interested Parties have contended that the operations of the DI are planned in order to maximize overall profitability by allocating resources to those products which have higher profits. It is submitted that these allegations are contradictory to the import data placed on record. Over the last three years the highest surge in imports has been taking place consistently approaching the second quarter of the Financial Year. On the other hand, the lowest imports take place in the fourth quarter of every financial year. Clearly, the DI has been forced to resort to selling below reasonable cost to liquidate the stock on account of the increased low priced imports.
- (p) The Interested Parties have contended that the demand in India is higher than the capacity of the DI whereby there is bound to be a demand-supply gap leading to certain inevitable imports. It is submitted that the DI is presently at 40% capacity utilization and the argument of the Interested Parties would be tenable if the DI was at 100% capacity utilization and there were still large quantities of imports being made due to unfulfilled demand. Further, the DI's plant is a swing plant and the DI is fully capable of meeting the complete demand in the country by allocating further swing capacity towards production of the PUC, provided that the safeguard duty protection is granted to ensure fair priced imports.
- (q) The Interested Parties have contended that levying safeguard duty on the product will be contrary to public interest. As regards fate of downstream producers, particularly in the pharmaceutical sector, it is submitted, that if the DI is forced to closure, there is no substantial competition to the overseas producers and they are bound to start increasing prices to exploit their market share and lack of competition. Therefore, the existence of a robust and self sufficient DI is in the public interest of downstream producers as well and will prevent overseas producers from exploiting the lack of competition in the Indian market. Further, several of downstream pharmaceutical producers are EOUs exclusively set up for exports and do not cater to the Indian domestic demand. As regards potential injury to the producers of Pyrazolone in India, as averred by some Interested Parties, it is submitted that injury suffered by downstream producers on account of dumping of the downstream product cannot be attributed to safeguard duties being levied on the product under consideration. More importantly, the fact that the Pyrazolone producers are already suffering grave injury despite no safeguard duty on MAAE clearly implies that the cause of concern for such producers is insufficient anti dumping duty and not duties being levied on the PUC.
- (r) The Interested Parties have contended that the DI has not provided a requisite adjustment plan and the adjustment plan submitted by the DI has been claimed to be excessively confidential. It is submitted that an adjustment plan detailing the efforts planned to be taken to make a positive adjustment to import competition, which the DI plans to effectuate over a period of 2-3 years, has been provided. Specific steps regarding particular cost-reduction measures have been provided and DI has made significant investment to upgrade and enhance the machinery purchased and upgrade it to international standards. Further, the DI has requested confidentiality in complete conformity with the requirements of the Safeguard Duty Rules.
- (s) Some Interested Parties have claimed that there is no demonstration on causation between the surge in imports and injury to the DI. It is submitted that there is a direct causal nexus between the increased imports and the

serious injury to the DI. The subject goods are sold in direct competition with the imports. The landed price of imports is significantly lower than reasonable costs and the selling price of the DI are determined by the import prices. Consequently, production, capacity utilization, sales, profits, return on investment and cash flow is declining due to continued presence of low price imports.

## **VI. Rejoinder by EXPORTERS**

### **28. Rejoinder submissions by M/s AZB & Partners on behalf of M/s Eastman Chemical Company**

- (a) These rejoinder submissions may be read in conjunction with the written submissions dated 12<sup>th</sup> July, 2013.
- (b) DI has merely reiterated most of its averments contained in the petition and failed to adduce additional evidence. DI has cited unexpected drop in consumption in European markets as result of recession, additional capacities in China PR and unforeseeably low prices of imports despite increase in raw material prices, as the three unforeseen events. However, none of three events are correct or can be considered as unforeseen.
- (c) DI has selectively referred to an online report which at best talks about dip in demand for chemical products in general in the EU due to recessionary effects arising from 2008 financial crisis. Even if it is assumed that the demand for chemicals in EU has decreased, such decrease would have been known and very well foreseeable by the DI which entered the market in 2010, more than 2 years after the onset of the 2008 financial crisis. Further the report relied upon by the DI neither specifies that the economic slowdown has resulted in decreased demand for MAA in the EU, nor does the report indicate that the slowdown has led to increased exports of MAA to South Asian countries, including India. On the contrary, the report indicates that as a result of low demand for chemical products, most producers have sharply curtailed production. This contradicts DI's contention.
- (d) DI states that capacity addition by Xinhua Pharmaceuticals (Shougang) Co Ltd and Qingdao Double Peach Speciality Chemicals (Group) Co Ltd during 2012-13 were unforeseen and bound to result in increased exports to India. However, it is incorrect to assert that these were unforeseen and necessarily translate into sudden, sharp and significant imports of MAA into India. On the contrary, as a new entrant into the market in 2010, the DI would have known who its likely competitors would be.
- (e) As regards DI's claim regarding low price of imports despite increase in raw material prices, such an assertion is incorrect because while input costs may affect the prices of the end product, the exact proportion in which end product prices may change would depend upon the conversion ratio. It is not correct to assume that the end product prices would increase to the same extent that the raw material prices may increase.
- (f) The additional data submitted by the DI for Apr-July 2013 shows that imports have fallen and capacity utilization has improved during this period.
- (g) DI's production as compared to the trends in imports has for the most part during the POI remained above the trends in imports and has stayed consistently above imports in the most recent period.
- (h) DI has based its claim on injury and also on causal link to relatively lower prices of imports. However, as per data submitted by the DI, import prices have for most part of the POI remained above the DI's prices.
- (i) DI asserts that the increase in imports have led to reduction in DI's market shares, and hence production and capacity utilization. However, the DI's market share has seen a substantial increase over the POI, despite it being a relatively new entrant in the market. A mere assertion that the alleged increase in imports have led to injury to the DI, without establishing the causal link by way of irrefutable facts and evidence, is incorrect and in the absence of any positive evidence, the former can not be said to be cause for the later.
- (j) A cyclical trend in imports is discernible. Import volumes are higher in Q1 and Q2 and lower in Q3 and Q4. More significantly, when imports are lower in Q3 and Q4, domestic sales witness a sudden spurt. This is because during the first two quarters, DI chooses to use its limited capacity to manufacture Monomethyl Acetoacetate (MMAA) which yields higher profitability than sales of MAA. Since MMAA has a seasonal demand lasting first two quarters. Thereafter, DI starts to employ its production facility for the production of MAA. Therefore, DI's assertion that imports are displacing DI in the Indian market for MAA is incorrect. Rather, the injury, if any to the DI may be attributed to its own selective utilization of its installed capacity, which may be employed interchangeably for making both MAA and MMAA.
- (k) Despite the statutory requirement, the DI has failed to provide its response to the Domestic Industry questionnaire.

## **VII. Rejoinder by IMPORTERS/USER INDUSTRY**

### **29. Rejoinder submissions by M/s TPM Consultants on behalf of M/s Aurobindo Pharma, CJ Shah & Co, Nutan Dychem, Prima Chemicals & Polygon Chemicals**

- a. A long period is required to be considered for the reason that the domestic industry does not have full existence in 2010-11.



- b. Despite specific instructions by the Director General (Safeguards) at the time of hearing, petitioner has preferred not to provide relevant information for the period April-June 2013 period to the Interested Parties. However, it is noted that the petitioner submitted the updated information only to the Director General on 5<sup>th</sup> September, 2013 and failed to provide the same to the Interested Parties in absolute contravention to the confidentiality provisions under the Rules, especially given the fact that the Interested Parties specifically argued that the data for longer period needs to be provided. The Interested Parties received the data on 10<sup>th</sup> September, a day before filing rejoinder, upon the direction of the Director General. Since not much time is available with the Interested Parties, adequate submission on the data so received shall be made subsequently. However, brief comments are being included separately hereinbelow.
- c. The written submissions of the petitioner do not contain relevant information for the period April-June, 2013. It is thus a clear situation where the petitioner has provided selective information and has clearly ignored the instructions given by the Director General (Safeguards) at the time of hearing.
- d. Petition did not contain quarter wise data for the three quarters of 2010-11, even when petitioner has claimed that it has commenced commercial production in May, 2010. Nor the petitioner has rectified this gap even when it was pointed out at the time of oral hearing. This is clearly malafide.
- e. No reasons have been given by the petitioner in the petition for discarding DGCI&S data and adopting IBIS data. The petition is totally silent on this issue. Use of IBIS information is not appropriate in the present case for the reasons that (i) IBIS has reported several transactions which are duplicate, (ii) since DGCI&S information is available, the same should have preference.
- f. The import pattern clearly reflects the behavior of MAA production by the petitioner.
- g. Petitioner is utilizing the same intermediate diketene for manufacturing of a number of products and therefore the production of MAA suffers when product of MMAA is at peak.
- h. Petitioner has suppressed from the Director General (Safeguards) that the product has significant seasonality because of seasonality in production of MMAA. MMAA has high seasonal demand at the time of Jan.-June, because of which the production of MAA in this period is low. Further, when demand for MMAA is low in July-Dec., the petitioner increases its production of MAA. Consequently, imports of MAA are high in first six months of a year and low in subsequent six months.
- i. The petitioner has a capacity of 4950 MT the same is grossly insufficient to meet the demand for the product in the country. Given the growth in demand in the past, it is estimated that demand in the current year shall be in the region of 7000 MT and same in the next year when proposed safeguard duty is operative in 2014-15, demand shall be 8500 MT. Thus, demand for the product shall be in the region of 8500 MT i.e. 170% of installed capacity and 215% of achievable production by the petitioner when the proposed safeguard duty shall be operative.
- j. Petitioner's production suffered in Q3, 2012-13 because the petitioner undertook some capital expenditure in this period, leading to production disruption in this quarter. Since the production of MAA by the petitioner was low, the consumers had to import the product to meet their requirement for the product.
- k. Petitioner's sales, production, capacity utilization, etc. shows an improvement in Q4 of 2012-13. Petitioner has provided no information on injury for April-June, 2013. Market share has improved in Q4, 2012-13. Inventories have declined. Losses suffered by the petitioner has also declined in 2012-13.
- l. Imposition of safeguard duty is against the interests of the user industry, i.e., Pyrazolone and Pharma Industry. Pyrazolone industry is as it is suffering financial losses, industry will not be able to further pass on the increase in its raw material costs to the consumers. Industry is already suffering from significant imports and dumping of Pyrazolone from China.
- m. Imposition of safeguard duty on MAA would lead to change in manufacturing process of pharma industry by shifting to imports of PHPG Dane Salt instead of production of PHPG Dane Salt from MAA.

### 30. **Increased imports of subject goods into India:**

The safeguard duty can only be imposed if the information has established that the product under consideration has been imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to domestic industry. In the instant case, however, these conditions precedence have not been met and therefore the safeguard duty should not be imposed.

The following cases have been referred to for the applicability of the above

- i. The WTO Appellate Body in Argentina – Footwear (WT/DS121/AB/R dated 14th Dec, 1999).
- ii. The WTO Panel in US – Line Pipe (WT/DS202/R dated 29th Oct, 2001).

31. The conditions listed in the case cited have not been met in the present case and therefore safeguard duty should not be imposed.

- i. The petitioner has not provided data for the period April-June 2013 despite specific instructions from the Director General (Safeguards). We have established that the imports have declined significantly in this period.
- ii. Petitioner has not included import data for the period 2009-10 for the reason that it would have clearly shown that imports have declined.
- iii. Admittedly, petitioner commenced commercial production in 2010-11 which resulted in decline in imports in that year. Some increase in imports in 2012-13, is a reaction of loss volumes by the foreign producers in previous years and suspension of production by the petitioner in Q3 of 2012-13. Because petitioner had suspended production the demand had to be met by imports.

32. The import trend does not show a trend of sudden, sharp and recent increase in imports. It only shows correction of situation due to market earlier lost and imports being made to meet the demand left by the domestic industry. Assuming that there was no domestic industry in 2009-10 and therefore imports were higher in this period; then it shows that imports were lower in 2010-11 because the petitioner had commenced commercial production and had displaced imports to a significant extent in this period. Further, the petitioner had suspended production in 2012-13 and therefore the demand had to be met by imports.

#### **Unforeseen Developments-**

33. The Director General has examined unforeseen development in all these cases. Further, the Director General has clearly established unforeseen developments in these cases on the basis of positive evidences. In the present case, no evidence whatsoever has been given by the petitioner to establish unforeseen developments. It is a mere statement. The fact that foreign producers have not increased their prices in proportion to the increase in cost does not constitute an unforeseen development.

#### **Serious Injury and threat of serious injury:-**

34. The decline in production in 2012-13 is because of suspension of production by petitioner on account of some capital expenditure undertaken.

35. The decline in capacity utilization in 2012-13 is because of suspension of production by petitioner because of some capital expenditure undertaken.

1. The decline in domestic sales in 2012-13 is because of suspension of production by petitioner because of some capital expenditure undertaken.
2. Increase in employment does not establish any injury. Further, decline in productivity is due to production suspension because of capital expenditure undertaken.
3. The increase in sales of the domestic industry less than increase in demand is because of suspension of production by the petitioner on account of capital expenditure undertaken. Further the demand for the product is higher than the capacities with the domestic industry and therefore the demand had to be met by imports.
4. The loss of market share in 2012-13 is because of production suspension by the petitioner in Q3, 2012-13. Since the petitioner was not in a position to meet the demand of the consumers, the same had to be met by imports.

36. On the contrary, when the alleged surge has happened in 2012-13, the losses suffered by the domestic industry have reduced. Further, when imports did not surge in 2011-12 and domestic industry had highest production, sales, best capacity utilization, ironically, the losses suffered by the domestic industry were also highest. A suggestion by foreign producers to the petitioner to shut down the business does not mean a threat of serious injury within the meaning of the Rules. It is a simple business proposal. The petitioner suffered financial losses in 2010-11 with lowest volume of imports. Further, the loss increased significantly in 2011-12 when imports remained in similar region whereas the petitioner had significantly increased its production and sales. Thus, the petitioner was suffering financial losses even when imports were at low levels. This clearly shows existence of certain other issues with the petitioner because of which petitioner might have been contemplating selling of business and shutting down the production.

37. So far as submission of the DI that several plants have been installed in China PR as well as significant capacity of the US and UK will lead to continued injury is concerned, it is mere statement and not supported with any evidence.

#### **Causal Link –**

38. There is no causal link between increased imports and serious injury to the domestic industry. The imports have been made only because the domestic industry decided to divert its intermediate capacity to other product. Since the petitioner did not have significant intermediate available, it follows that the petitioner could not have produced more of the product under consideration.

**Adjustment Plan –**

39. Petitioner has not provided any concrete information in this regard and therefore no further rejoinder is required.

**Public Interest –**

40. Written submissions are relied upon.

**Post-POI data:**

41. On the updated data provided by the DI on the directions of the DG(S) for the period April'13-July'13 for the PUC, it appears that

1. There is decline in imports of the product under consideration in the recent period Q1 of 2013-14 and July 2013 alongwith a decline in market share of imports.
2. Petitioner's production, sale, market share, employment, productivity and capacity utilization has significantly increased in Q1 2013-14 and thereafter in July 2013. The inventory has declined in the same period. The demand for the product has significantly increased.
3. As per petitioner's claim, demand in Q1 2013-14 was in the region of 7700 MT which increased beyond 9100 MT in July 2013. As against this, the petitioner holds a capacity of only 4950 MT. Thus, capacity with the petitioner is much lower than the demand of the product in the country. Given significant and rising gap between demand and supply, it is evident that the petitioner cannot, in any case, meet the demand for the product in the country and imposition of safeguard duty shall not be in public interest.

42. The product has significant seasonality because of seasonality in production of MMAA. As submitted in the written submissions, petitioner is utilizing the same intermediate diketene for manufacturing of a number of products and therefore the production of MAA suffers when product of MMAA is at peak. Imposition of safeguard duty would have significant adverse impact on the consumers. In any case, petitioner cannot meet the demand for the product under consideration in the Country, imports are inevitable and imposition of safeguard duty is not in public interest on this account.

43. **Rejoinder by M/s WTC Consultants on behalf of Exporters from China PR:-**

M/s WTC Consultants appearing on behalf of exporters from China PR has filed only written submissions post public hearing, but has not filed any rejoinder.

## VIII. Examination & Findings:

44. I have carefully gone through the case records, the replies filed by the domestic producers, user/importers, exporters and exporting nations. Submissions made by the various parties and the issues arising therefrom are dealt with at appropriate places in the findings hereinafter.

45. Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 deals with imposition of Safeguard Duty on imports. Section 8B(1) provides for imposition of Safeguard Duty by the Central Govt on an article if the article is being imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry.

46. The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provides the manner and principles governing investigation.

47. The investigation has been conducted in accordance with the said rules and the final findings are recorded through this notification.

**(A) The product under investigation:**

48. The product under consideration in the present case is Methyl Acetoacetate (also known as MAA/MAAE/AAME) which is a diketene based ester or aceto-acetate. Esters are chemical compounds derived by reacting an oxoacid with a hydroxyl compound such as an alcohol or phenol. The chemical formula in respect of this product is  $C_5H_8O_3$ . This product is also known by the names of Methyl-3-ketobutyrate, Methyl acetylacetate, Methyl-3-oxobutanoate, Methyl acetone carboxylate, Methyl-3-oxobutyrate, Acetoacetic methyl ester, MAAE.

49. Methyl Acetoacetate is classifiable under Customs Tariff Heading 29183040 of Chapter 29 falling under First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations. No interested party raised any issue with regard to the product under investigation. Therefore, it is confirmed that the product under investigation is "Methyl Acetoacetate" falling under Customs Tariff Heading 29183040 of Chapter 29 falling under First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. Further, no differences in the production process, characteristics or end-uses between imported Methyl Acetoacetate

and domestically produced Methyl Acetoacetate were raised by any of the Interested Parties during the course of this investigation. Therefore, it is also held that domestically produced Methyl Acetoacetate falls under the ambit of like or directly competitive in all respects to the imported product under investigation and that the domestically produced Methyl Acetoacetate is a like article to the imported Methyl Acetoacetate within the meaning of Rule 2(e) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997.

**(B) Domestic Industry:**

50. Section 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act 1975 defines Domestic Industry as follows:

(b) "Domestic Industry" means the producers –

(i) as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or

(ii) whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India;"

51. M/s Laxmi Organic Industries Ltd, Mumbai is the only applicant constituting domestic industry in this case. M/s Laxmi Organic Industries Ltd, claimed that their production accounts for 100% of the total production of Methyl Acetoacetate in the country. Thus, the collective output of the applicant producer constituted a major share of the total production of Methyl Acetoacetate in India. Further, no claim has been made by the Interested Parties against the applicant being the domestic industry. Therefore, it is held that the applicant domestic producer constitutes and represents the domestic industry (DI) within the meaning required and defined under Sec 8B(6)(b)(i) of the Customs Tariff Act 1975.

**(C) Source of information:**

52. The import data for the product under consideration for the period from Q1 of 2010-11 to July 2013-14 has been taken from IBIS (transaction-wise) as provided by the applicant as they have claimed that the subject goods are being imported under various other classifications as well. In such a situation, transaction-wise data had to be considered which is available in the IBIS data, which has been considered by this directorate earlier also. Hence, IBIS import data has been taken in this matter as well. Further, the data pertaining to other safeguard economic parameters for the period from 2010-11 till 2012-13 has been verified on the basis of central excise records of the petitioner to the extent necessary, through on-site verification of the unit of the applicant and such verified data for the POI has been taken into consideration for injury analysis. The data for the first quarter of 2013-14 and till July'13 has been taken as furnished by the applicant, post-public hearing. The data for three years or longer has been provided by the DI in the form and manner decided by DG (Safeguards) under Rule 5(2) of Safeguard Duty Rules 1997 vide Trade Notice No SG/TN/1/97 dated 06/09/1997. The non-confidential version of the verification report has been placed in the public file for all concerned. The cost data and calculations of injury margin have been provided by the petitioner duly certified by an independent Cost Accountant.

**(D) Period of Investigation (POI):**

53. Neither the Customs Tariff Act, 1975, nor the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, specifically define 'period of investigation' or the minimum period to be considered for a Safeguard investigation. The WTO Agreement on Safeguards does not contain any general or specific provision or guidelines for choosing the investigation period. However the issue of period of investigation has been dealt with in detail in Panel findings in US-Line Pipe Case against Korea. The Panel in this case ruled that it is up to the discretion of the investigating authority of the importing Member to decide the "length of the period of investigation" and its "breakdown":

*"We note that the Agreement contains no requirements as to how long the period of investigation in a safeguards investigation should be, nor how the period should be broken down for purposes of analysis. Thus, the period of investigation and its breakdown is left to the discretion of the investigating authorities. In the case before us the period selected by the ITC was five years and six months, which is a period similar in length to the one used by the Argentine investigating authority in Argentina — Footwear Safeguard. However, we note that the Appellate Body, in the findings relied upon by Korea to argue the question of the length of the period of investigation, emphasized not the length of the period per se, but that there should be a focus on recent imports and not simply trends over the period examined. In the case of the line pipe investigation the ITC did not merely compare end points, or look at the overall trend over the period of investigation (as Argentina had done in the investigation at issue in Argentina — Footwear Safeguard). It analyzed the data regarding imports on a year-to-year basis for the 5 complete years, and also considered whether there was an increase in interim 1999 as compared with interim 1998. We are of the view that by choosing a period of investigation that extends over 5 years and six months, the ITC did not act inconsistently with Article 2.1 and Article XIX. This conclusion is based on the following considerations: first, the Agreement contains no specific rules as to the length of the period of investigation; second, the period selected by the ITC allows it to focus on the recent imports; and third, the period selected by the ITC is sufficiently long to allow conclusions to be drawn regarding the existence of increased imports." (paras. 7.196, 7.199 and 7.201)<sup>7</sup>*

<sup>7</sup> WT/DS202/R DT, 29.10.2001 Panel report in US-Line Pipe case

The Panel in the same US-Line pipe case ruled that:

*“In a safeguard investigation, the period of investigation for examination of the increased imports tends to be the same as that for the examination of the serious injury to the Domestic Industry. This contrasts with the situation in an anti-dumping or countervailing duty investigation where the period for evaluating the existence of dumping or subsidization is usually shorter than the period of investigation for a finding of material injury. We are of the view that one of the reasons behind this difference is that, as found by the Appellate Body in Argentina – Footwear Safeguard, “the determination of whether the requirement of imports “in such increased quantities” is met is not a merely mathematical or technical determination.” The Appellate Body noted that when it comes to a determination of increased imports “the competent authorities are required to consider the trends in imports over the period of investigation”. The evaluation of trends in imports, as with the evaluation of trends in the factors relevant for determination of serious injury to the Domestic Industry, can only be carried out over a period of time. Therefore, we conclude that the considerations that the Appellate Body has expressed with respect to the period relevant to an injury determination also apply to an increased imports determination.” (Para 7.209)<sup>8</sup>.*

54. From the above, it is clear that neither the domestic laws on Safeguard nor Agreement on Safeguard and Article XIX of GATT provide specific guidelines on the period of investigation. However, in the spirit of the references cited above, it appears that the relevant investigation period should be sufficiently long to allow conclusion to be drawn on increased import and serious injury and it should not only end in the very recent past but the investigation period should be the recent past.

55. In the Notice of Initiation, period of investigation had been taken from 2010-11 to 2012-13 as the domestic industry started commercial production in May 2010 only and accordingly, this period of investigation had been considered. One of the issues raised by opposing Interested Parties in this case, during the Public Hearing, was pertaining to the quarterly injury analysis done by the domestic industry from Q4 2010-11 onwards, in their presentation. The parties objected that the period of investigation falls below three years which is not in conformity with the prevalent norm/past precedence of the Directorate, though this is not factually correct in view of the fact that in the Notice of Initiation, the POI is clearly mentioned to be from 2010-11 to 2012-13 and the injury analysis is also done on annual basis for the same period. Further, during onsite verification also, data has been verified from Q1 2010-11 till 2012-13. It was a different matter that the DI chose to explain injury analysis from Q4 of 2010-11 and not for the full year, despite having the data.

56. It was argued by some of the Interested Parties that imports have decreased by 40% within a short span of six months i.e. between second and fourth quarter of 2012-13 and since imports of MAA into India are showing a perceptible declining trend beginning the last quarter of the POI and the DI market share is improving, the claim that the DI is suffering injury is entirely misplaced. Accordingly, the domestic industry was asked in the Public Hearing to file updated injury data for the subsequent period. The domestic Industry have filed the same vide their letter dated 5<sup>th</sup> Sep, 2013 updating it for the period upto July, 2013. This additional data has also been considered in making the final analysis of the serious injury/threat of serious injury.

57. Considering that the period selected should be sufficiently long to allow conclusions to be drawn regarding existence of increased imports, to neutralize the effect of seasonal variation in this case, the POI has been considered as 2010-11 to 2012-13. However, as stated above, additional data provided by the DI has also been considered in making the final analysis of the threat of serious injury.

**(E) Confidentiality of information submitted:**

- i) Rule 7 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 and Article. 3.2 of WTO Agreement on Safeguards provides for confidentiality treatment to certain information. The rules provide that an interested party is not required to disclose such information on actual basis which is confidential information of the company and disclosure of which can cause serious prejudice to the business interests of such party, which is not in public domain and which the petitioner has not disclosed before public at large in the past.
- ii) The domestic industry has provided some information on confidential basis and sought confidentiality on the information /data submitted. The domestic industry provided non confidential version of the application for safeguard measure as per the provisions of Safeguard Rules 1997 and Trade Notice No. SG/TN/1/97 dated 06.09.1997. Further, the domestic industry has submitted reasons for seeking confidentiality at the time of filing the application.
- iii) Further, the Domestic Industry and the Interested Parties have submitted reasons for seeking confidentiality at the time of filing the application and at the time of filing written submissions/rejoinders, which appears to be reasonable and, therefore, have been accepted, whenever claimed.

**(F) Increased Imports:**

<sup>8</sup> WT/DS202/R DT, 29.10.2001 Panel report in US-Line Pipe case

Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 deals with the power of the Central Government to impose safeguard duty and provides as follows:

*“(1) If the Central Government, after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to Domestic Industry, then, it may, by notification in the Official Gazette, impose a safeguard duty on that article :”*

58. The Rules mandate increase in imports as a basic prerequisite for the application of a safeguard measure. Thus, to determine whether imports of the product under consideration have “increased in such quantities” for purposes of applying a safeguard measure, the rules require an analysis of the increase in imports, in absolute terms or in relation to domestic production.

59. Rule 2 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 defines ‘increased quantity’ as follows:

*“increased quantity” includes increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production.”*

60. With regard to the nature of the increase in imports, the Appellate Body in Argentina-Footwear (EC)<sup>9</sup>, in contrast to the Panel, held that the increase in imports must have been recent, sudden, sharp and significant enough to cause or threaten to cause serious injury. Relevant extract therefrom is as follows:

*“131. [T]he determination of whether the requirement of imports ‘in such increased quantities’ is met is not a merely mathematical or technical determination. In other words, it is not enough for an investigation to show simply that imports of the product this year were more than last year — or five years ago. Again, and it bears repeating, not just any increased quantities of imports will suffice. There must be ‘such increased quantities’ as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry in order to fulfill this requirement for applying a Safeguard measure. And this language in both Article 2.1 of the Agreement on Safeguards and Article XIX:1(a) of the GATT 1994, we believe, requires that the increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough, and significant enough, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause ‘serious injury’.”*

The Panel on US-Wheat Gluten<sup>10</sup>, interpreted the phrase “in such increased quantities” as follows:

*“8.31 [A]rticle XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 [of the Agreement on Safeguards (“SA”)] do not speak only of an ‘increase’ in imports. Rather, they contain specific requirements with respect to the quantitative and qualitative nature of the ‘increase’ in imports of the product concerned. Both Article XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 SA require that a product is being imported into the territory of the Member concerned in such increased quantities (absolute or relative to domestic production) as to cause or threaten serious injury. Thus, not just any increase in imports will suffice. Rather, we agree with the Appellate Body’s finding in Argentina — Footwear Safeguard that the increase must be sufficiently recent, sudden, sharp and significant, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause serious injury.”*

#### **(G) Increased Import in absolute terms:**

61. The analysis of the trend in imports of Methyl Acetoacetate in the light of the above stated provisions has been done. Methyl Acetoacetate is imported into India from a number of countries, but primarily from China PR, the USA and Switzerland. The imports and production of Methyl Acetoacetate during financial year 2010-11 to 2012-13 were as under:

Financial Year	Total Imports (MT)	All India Production (MT)
2010-11	3985	1980
2011-12	3584	2604
2012-13	5084	2045

<sup>9</sup> Appellate Body Reports on Argentina-Footwear (EC) WT/DS121/AB/R dated 14 December 1999

<sup>10</sup> Panel Report on US-Wheat Gluten WT/DS166/R 31 July 2000

62. There appears to be an increased import in 2012-13 in absolute terms. The imports have increased from the base year and also increased from 3584 MT in 2011-12 to 5084 MT in 2012-13 which shows an increase of 41.85 %. It is, therefore held that imports of Methyl Acetoacetate have surged over the POI in absolute terms.

**(i) Imports in relation to production:**

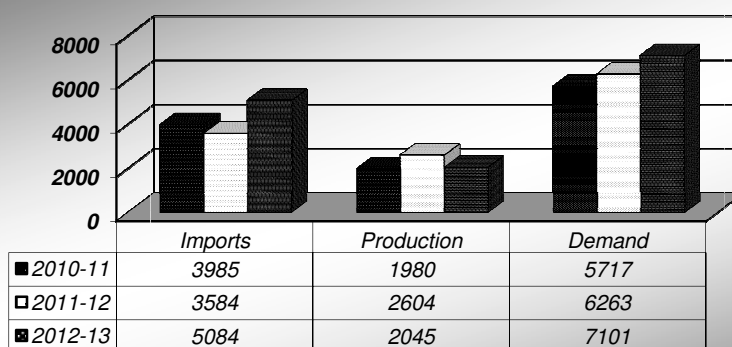
63. The imports of product under consideration in India during the POI have also increased in relation to production of the Domestic Industry when compared with the base year as well as preceding year. The import with respect to total production increased from 201% in 2010-11 to 249 % in 2012-13 i.e. by 48 %, which is a significant increase. However, there was a dip in 2011-12 due to increase in production by the DI, but the rise in 2012-13 from 2011-12 is very significant.

Financial Year	Total Imports (MT)	All India Production (MT)	% of Import with respect to production
2010-11	3985	1980	201
2011-12	3584	2604	138
2012-13	5084	2045	249

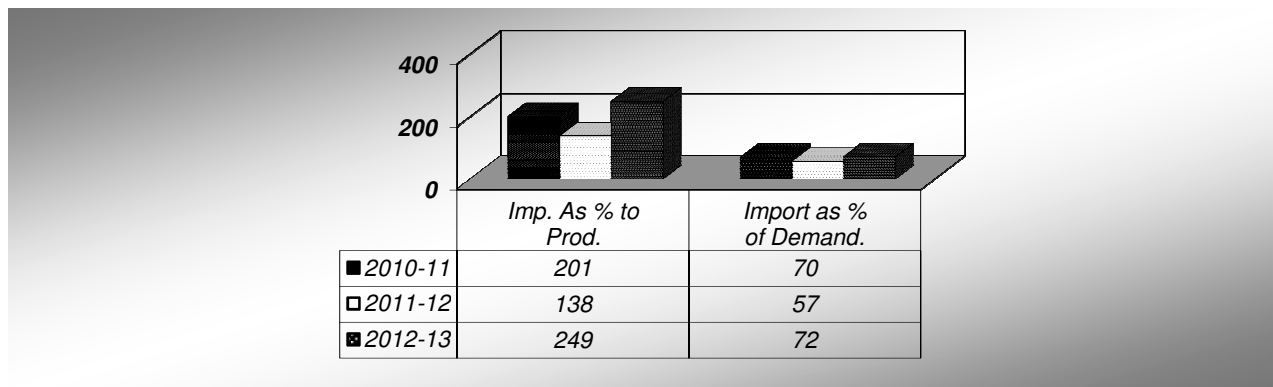
**(ii) Imports in relation to Demand:**

64. For the purpose of the present investigations, the consumption or demand for the product under consideration is determined as the imports of product into India from different countries, domestic sales of the DI and domestic sales of other domestic producers. Changes in demand/consumption so determined over the period have been compared with the changes in the imports from various sources and supplies by the Domestic Industry in order to determine whether imports of product under consideration in India have increased/decreased in relation to consumption or demand for the product in the country. It is noticed, however, that the rise in import with respect to demand has been marginal, i.e., from 70% in 2010-11 to 72% in 2012-13. However, imports increased significantly with respect to demand when compared from the preceding year, i.e., from 57 % in 2011-12 to 72 % in 2012-13.

Financial Year	Total Imports (MT)	Total Demand(MT)	% of Import with respect to demand
2010-11	3985	5717	70
2011-12	3584	6263	57
2012-13	5084	7101	72



**Table showing import as % of Production and Demand:**



65. Some of the Interested Parties have claimed that surge in imports is not sudden, sharp and significant enough and imports should be analysed for a longer time period, from prior to the operations of the present DI. It is contended that the DI has already placed on record sufficient data and analysis to establish that the increase in imports has been sudden, sharp and significant enough, imports have increased in absolute terms as well as in relation to the production. Further, an analysis of imports prior to 2010-11, when domestic industry was not in operation is, therefore, not only incorrect and misrepresentative but also contrary to the requirement of law. Similarly, it is added by the said Interested parties, quarter-wise analysis over the POI has not been considered because the seasonality of the Product under consideration has been a clearly accepted fact by both the Domestic Industry and the Interested Parties.

66. It is apparent from the above that there is an increased import during the Period of Investigation, as compared from the base year and has surged significantly in the most recent period of 2012-13 from the preceding year. As such, overall increase in imports from the base year seems to be significant enough, to constitute “increased imports” within the meaning of Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975.

**(iii) Reasons for increase in imports/Unforeseen developments:**

67. It is noted that there is no express obligation/requirement on the Director General (Safeguards) to analyze unforeseen circumstances as there is no specific requirement either in Indian Rules, on the methodology that should be followed for analyzing unforeseen developments, or the WTO Agreement on Safeguards, which also does not make any prescription with regard to the methodology that should be followed or the parameters that must be met in deciding unforeseen developments. The Agreement on Safeguards read with Article XIX of GATT, however, obligates the national authorities to examine the “unforeseen developments” which led to the serious injury to the Domestic Industry. It is understood that this Directorate has consistently been examining the issue of “unforeseen developments” in its investigations. It is, therefore, considered important to examine the unforeseen developments or circumstances which have led to increased imports.

68. The Appellate Body in Argentina-Footwear (EC case) held that the phrase “Unforeseen Developments” means the developments which were unexpected. ‘Unforeseen developments’ requires that the developments which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been ‘unexpected’. The Appellate Body in Korea-Dairy case held that unforeseen developments are developments not foreseen or expected when member incurred that obligation.

69. The Appellate Body, in Argentina-Footwear (EC), then held that the requirement of “unforeseen developments” did not establish a separate “condition” for the imposition of safeguard measures, but described a certain set of “circumstances”.

70. The Domestic Industry has pointed out that the following factors have led to the increased imports of the product from different countries as unforeseen circumstances in the present case:-

**(a) Unexpected drop in consumption in European Markets**

71. The European markets have reported an unexpected drop in demand as a result of the massive capacities of the subject goods in foreign countries and the foreign producers have resorted to increased exports to India.

**(b) Additional Capacities in China PR**

72. The Producers in China PR like M/s Xinhua Pharmaceutical (Shougang) Co. Ltd., M/s Qingdao Double Peach Specialty Chemicals (Group) Co. Ltd. and M/s Ningbo Wanglong Tech Co., Ltd have set up huge capacities and are looking forward to start exporting to India. This development, as claimed by the Domestic Industry, clearly indicate that there is bound to be continued incessant imports to India at increasing volumes.

**(c) Unforeseeably low pricing of imports despite increase in raw material Costs**



73. Despite the global increase in raw material prices, the import prices increased only marginally. As India is a price attractive market, the low priced imports were well received by the consumers. Hence, the low priced imports led to an increased import into India.

74. It has been submitted by some Interested Parties that DI has merely reiterated most of its averments contained in the petition and failed to adduce additional evidence. DI has cited unexpected drop in consumption in European markets as result of recession, additional capacities in China PR and unforeseeably low prices of imports despite increase in raw material prices, as the three unforeseen events but none of three events are correct or can be considered as unforeseen. Some have argued that the claim by the applicant that unforeseen development is not a separate requirement or condition for imposition of safeguard measures is clearly violative of Article XIX of GATT 1994, which clearly provides that unforeseen development is required to be seen by the Director General (Safeguards).

75. As against the above mentioned arguments, it appears that DI has referred to a report which at best talks about dip in demand for chemical products in general in the EU due to recessionary effects in economy arising from the 2008 financial crisis. Even if it is assumed that the demand for chemicals in EU has decreased, the DI has not been able to demonstrate as to how such decrease, more than 2 years after the onset of the 2008 financial crisis has resulted in increased exports of MAA to South Asian countries, including India. On the contrary, the report indicates that as a result of low demand for chemical products, most producers have sharply curtailed production. This contradicts DI's contention. Further, DI states that capacity addition by Xinhua Pharmaceuticals (Shougang) Co Ltd and Qingdao Double Peach Speciality Chemicals (Group) Co Ltd during 2012-13 were unforeseen and bound to result in increased exports to India, but has not been able to demonstrate the shift in exports from China PR to India during the POI which necessarily translate into any sudden, sharp and significant imports of MAA into India.

76. Therefore, the Domestic Industry has not been able to support its claim for unforeseen developments by any concrete documentary evidence due to which these cannot be taken as unforeseen developments.

#### **Serious Injury:**

(H). Section 8B subsection 6(c) of Customs Tariff Act, 1975 provides as follows:

*"Serious injury" means an injury causing overall impairment in the position of a domestic industry.*

(i) The Article 4.2(a) of the Agreement on Safeguard and Annexure to Rule 8 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997 technically requires that certain listed factors as well as other relevant factors must be evaluated to determine serious injury or threat of serious injury. However, these provisions do not specify what such an evaluation must demonstrate. Any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is "declining". In one case, for example, there may be significant decline in sales, employment and productivity which will show "significant overall impairment" in the position of the industry, and therefore will justify a finding of serious injury. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate "significant overall impairment" of the industry. Thus, in addition to a technical examination of all the listed factors and any other relevant factors, it is essential that the overall *position* of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.<sup>11</sup>

ii) Accordingly, in analyzing serious injury or threat of serious injury, all factors, which are mentioned in the rules as well as other factors which are relevant for determination of serious injury or threat of serious injury, have been considered. No single factor has been considered as dispositive. All relevant factors within the context of the relevant business cycle and conditions of competition which are relevant to the affected industry have been considered. The determination of serious injury or threat of serious injury is based on evaluation of the overall position of the domestic industry, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.

(I). Section 8B subsection 6(d) of Customs Tariff Act provides as follows:

*"threat of serious injury" means a clear and imminent danger of serious injury.*

The Annex (1) to the Customs Tariff(Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997 provides as follows:

*"In the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to a demonstrate industry, the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market*

<sup>11</sup> Based on Para 139 of Argentina footwear Case Appellate Body Report Of WTO

*taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment.”*

**(J) Serious Injury:** In view of the facts on records, the serious injury caused or threatened to be cause to the Domestic Industry due to increased import of Methyl Acetoacetate is reflected from the analysis of the following economic parameters:

(i) **Production:** The production of the domestic industry increased from 1980 MT in 2010-11 to 2045 MT in 2012-13. However, the production in 2012-13 decreased as compared to immediate preceding year 2011-12.

Year	Production of MAA (MT)
2010-11	1980
2011-12	2604
2012-13	2045

(ii) **Capacity Utilisation:** Capacity utilization of the domestic industry has decreased significantly in the most recent period, from 53% in 2011-12 to 41% in 2012-13.

Year	Installed Capacity (MT)	Capacity utilized(%)
2010-11	4950	40
2011-12	4950	53
2012-13	4950	41

(iii) **Share of domestic producers in domestic demand:** Market share of domestic producer has decreased significantly. Applicant had a market share of 30% in 2010-11 which has risen to 43% during 2011-12, but has declined to 28% in 2012-13.

Financial Year	Total Import(MT)	Sales of DI (MT)	Total Demand (MT)	Market Share(%)		Inventory (MT)
				DI	Import	
2010-11	3985	1732	5717	30	70	196
2011-12	3584	2679	6263	43	57	84
2012- 13	5084	2017	7101	28	72	79

iv) **Changes in the level of Sales :-** As seen in the table above, the sales of the domestic industry increased from 1732 MT in 2010-11 to 2679 MT in 2011-12, but declined significantly thereafter to 2017 MT in 2012-13.

v) **Employment:** Average employment has increased from 183 in 2010-11 to 247 in 2012-13.

(vi) **Profit & Loss:** The profitability of the domestic industry has been as under:

Financial Year	Profitability (Rs. /MT) (Indexed)
2010-11	-100
2011-12	-330
2012-13	-225

It appears that the DI is in loss, but showing signs of recovery in the most recent period of 2012-13 as compared to the preceding year.

77. Based on above, it is concluded that the DI has suffered adversity on almost all the major safeguard parameters viz production, sales, market share and capacity utilization during the year 2012-13 as compared to the immediately preceding year 2011-12. However, this adversity is not as sharp when the comparison is made with the

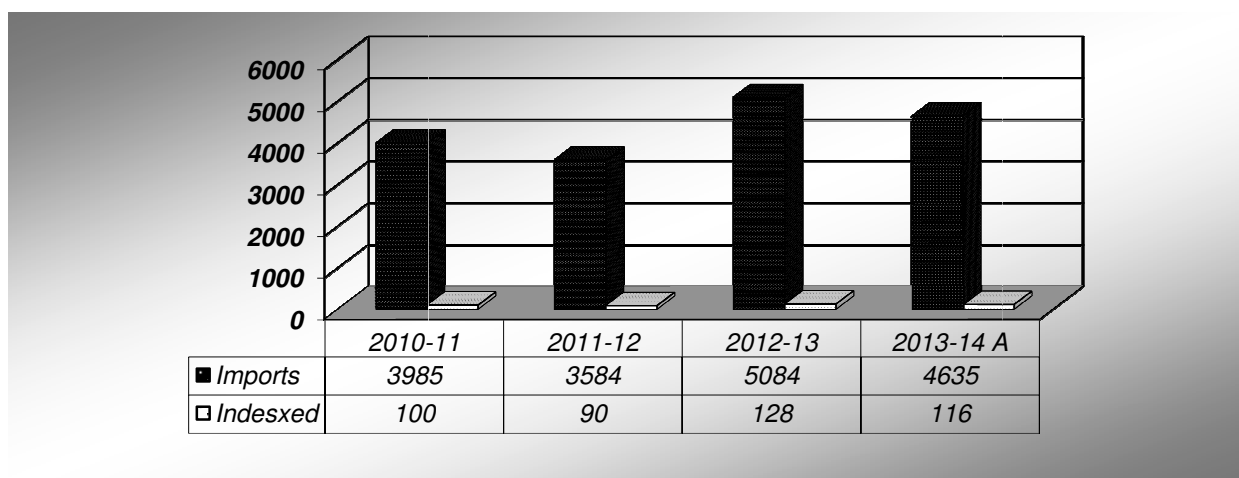
base year, because of the reason that these parameters have shown a healthy trend in 2011-12 vis a vis the base year. Even then, though, it cannot be concluded that there is a continuous surge in imports over the entire POI leading to a serious injury to the DI, it is noted that there has been significant increase in imports during 2012-13 as compared to 2011-12, so as to cause serious injury to the domestic industry.

**(K) Threat of Serious Injury:**

Post-POI data till July, 2013 was sought during the Public Hearing in view of the submissions of some Interested Parties, who argued that since imports of MAA into India are showing a perceptible declining trend beginning the last quarter of the POI, and the DI market share is improving, the claim that the DI is suffering injury is entirely misplaced. They further submitted that imports have decreased by 40% within a short span of six months i.e. between second and fourth quarter of 2012-13 and that the petitioner's production has improved in the most recent quarter of 2012-13, i.e., quarter 4, submitted by the DI. In the given circumstances, an attempt was made to analyse the trend in the period after the POI i.e. 2013-14 (from April, 13 to July, 13) to draw a clear inference about the possibility of accentuation or diminishing of the injury to the domestic industry and to assess the threat perception of the DI. On examination of this data, the following is observed:

**(a) Import data –**

Description with source	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 Q1 (Apr to Jul)	2013-14 (Annualized)
As furnished at annexure 6(updated up to July 13) post Hearing, sourced from IBIS (in MT)	3985	3584	5084	1545	4635
Indexed (%)	100	90	128		116



**(b) Analysis of various economic/safeguard parameters pertaining to Methyl Acetoacetate**

Financial Year	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (Apr. to July)	2013-14 (Annualized)
Imports as per IBIS (MT)	3985	3584	5084	1545	4635
Production of DI (MT)	1980	2604	2045	1094	3282
Domestic sale of DI (MT)	1732	2679	2017	1141	3423
Total consumption/demand(MT)	5717	6263	7101	2686	8058
Export (MT)	51	38	33	Nil	
Market share of DI (%)	30	43	28	42	42
Market share of Imports (%)	70	57	72	58	58
Installed capacity (MT)	4950	4950	4950	1650	4950

Capacity utilization (%)	40	53	41	66	66
Average Employment (No)	183	217	247		267
Inventory (MT)	196	84	79	79	79

(i) **Imports**— Imports have declined in 2013-14 (Annualized) when compared to 2012-13, but are more than the base year.

(ii) **Production**—Production has sharply increased in 2013-14 (Annualized) when compared to 2012-13 by almost 60.48%. It is also significantly higher than the base year's production, i.e., by 66%.

(iii) **Domestic Sales**- Domestic sales have increased in 2013-14(Annualized) when compared to 2012-13 by a whopping 70%, almost double the base year figure. Compared to the base year 2010-11, the increase is 98%.

(iv) **Total consumption/demand**—This has shown a rising trend throughout from 2010-11 to 2013-14(Annualized). Further, demand of the product in question is also much above the total installed capacity of the product resulting in demand/supply gap. However, the DI have stated that their plant is a swing plant and fully capable of meeting the complete demand in the country by allocating additional capacity towards production of the product under consideration. But, the surge in low priced imports has restricted the applicant from utilizing the swing capacity for the subject goods. Further, despite the cost of sales being higher, the domestic industry is compelled to keep prices low in order to compete with the imports into India, making it unviable for them to increase the capacity utilization and achieve higher production. It has further been submitted that presently other reactors of the applicant DI's plant are utilized to make other diketene derivatives, which in case the applicant was able to sell the subject goods at fair selling price, can be utilized for manufacture of the subject goods. However, the surge in the low priced imports has restricted the applicant from utilizing the swing capacity for the subject goods. In fact, as per the letter, the applicant can allocate the capacity of other reactors to enhance its production capacity of subject goods to 7260 MT to cater to the market demand which stands at 7101 MT for 2012-13.

(v) **Exports** – Exports have shown a declining trend throughout the period in question.

(vi) **Market share of DI/Import** – Market share of DI has increased in 2013-14 (Annualized), whereas the market share of imports has decreased as compared to 2012-13. This shows the improvement in the position of the DI vis-à-vis imports, emphasizing no causal link between surge in imports and serious injury or threat of serious injury to the DI.

(vii) **Capacity utilization** – Capacity utilization has increased in 2013-14(Annualized) as compared to the previous year by 25%.

(viii) **Average employment** – This has shown a rising trend throughout the period in question.

(ix) **Inventory** – Inventory has decreased throughout the period in question. The reason, as contended by the DI is that the production was deliberately reduced to cope up with the absence of orders and surge of low priced imports into India.

(x) **Profitability** - Profit/Loss position of the party is reflected in the table below –

Financial Year	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (A.)
Indexed	-100	-330	-225	-473

Losses have accentuated further in 2013-14(annualized) as compared to the preceding year 2012-13, after showing signs of improvement in the previous year. In a situation (2013-14 July'13) where the economic parameters are showing marked improvement and imports have declined, increase in losses signify presence of factors other than surge in imports for serious injury or threat of serious injury.

78. On scrutiny of the said data it is noted that during the post POI period, there is a decline in the overall imports so much so that the market share of imports has declined by about 14% as against the corresponding rise of the market share of the domestic industry by 14%. There is a significant improvement in the production, inventory position, productivity, employment with a very sharp increase in domestic sales. Even though there appears to be a fall in profitability for the domestic industry, in all fairness, in view of the above, it cannot at least be attributed to the surge in the imports. The DI has shown marked improvement in the period 2013-14 (Annualised) as compared to the immediately preceding year i.e. 2012-13. Even the loss suffered improved (in 2012-13) when the DI suffered the serious injury in relation to almost all economic parameters, but again aggravated post POI (till July'13 i.e., 2013-14 A) when the economic parameters are showing marked improvement. Thus, even though the DI seems to have suffered serious injury till 2012-13 due to surge in imports, the same cannot be said to be true for post-POI in this case. This leads to the conclusion that the threat perception expressed by the Domestic Industry is largely unsubstantiated.

(L) **Price Undercutting-**

79. The DI has submitted the cost data duly certified by the independent cost accountant regarding price undercutting and injury margin, as below:

Particulars	2010-11 (Indexed)	2011-12 (Indexed)	2012-13 (Indexed)
Import Price (Rs./MT)	100	107	108
Selling Price of DI(RS./MT)	106	113	114
Cost of Sales(Rs./MT)	120	143	141
Landed Value (Rs./MT)	109	115	117
Price Undercutting (RS./MT)	-3	-2	-3
% of price undercutting	-3	-2	-3

80. As against the contention of the Interested Parties that fluctuation in raw material prices have caused injury to the DI and the DI is able to sell at prices that match the import prices whereby there is no undercutting or injury, it is noticed that there is negative price undercutting between the selling price of the DI and the landed value of the imported product, as shown in the table above. It is seen that the selling price of the DI is lower than the landed value of the imported product. This further shows that the PUC is available domestically as well as imported, at a very competitive price. This further strengthens the belief that though there has been a surge in imports in the year 2012-13 over 2011-12, this is more to cater to the rising demand of the PUC at a competitive price. Besides, as per the submissions of the Interested Parties, the limitations of installed capacity vis-a-vis logic of self-controlled production and the seasonality of the PUC among the product basket also appears to have contributed at one time or the other.

**M) Public Interest:** Article 3 of the Agreement on Safeguards states as follows:

*“A Member may apply a safeguard measure only following an investigation by the competent authorities of that Member pursuant to procedures previously established and made public in consonance with Article X of GATT 1994. This investigation shall include reasonable public notice to all Interested Parties and public hearings or other appropriate means in which importers, exporters and other Interested Parties could present evidence and their views, including the opportunity to respond to the presentations of other parties and to submit their views, inter alia, as to whether or not the application of a safeguard measure would be in the public interest. The competent authorities shall publish a report setting forth their findings and reasoned conclusions reached on all pertinent issues of fact and law.”*

81. In an economy there are varying and sometimes competing interests of different economic players. The imposition of safeguard duty can affect different players differently and the impacts may not always be most suitable for all the different economic players when they have competing interests. Therefore, the possible impact on interests of various economic player groups have been analyzed based on the available information.

82. In their written submissions regarding the question of public interest, the domestic industry have stated that they have made significant investment and set up the new production facility in Mahad, Maharashtra to cater to the growing Indian demand and generate employment in India and therefore it is in larger public interest to impose safeguard duty on the imports of the subject goods into India and afford immediate protection to the nascent domestic industry. However, they have not adduced any evidence in the form of statistical data regarding the minimal impact of the imposition of the safeguard duty, if any, on the downstream industry using their product as raw material and consequential impact on the public at large using the end product manufactured by the downstream industry.

83. On the other hand, other Interested Parties have submitted that two consumer segments, viz., Pyrazolone industry and pharma industry, command majority of the consumption of MAA in India. They have further submitted that Pyrazolone producers are not large scale organizations and are small business enterprises who do not have strength to bear financial losses in the product for quite some time. Any imposition of safeguard duty would force these manufacturers to quit manufacturing of Pyrazolone and consequently eliminating the existing demand for MAA. The parties have further submitted that pharma industry consumes MAA in the production of Amoxy Formulations, which are covered under DPCO. Since the end product of the Industry is under DPCO, the Industry cannot increase the price of its product in the market. However, any imposition of safeguard duty on its raw material i.e. MAA will increase its cost and render the production of Amoxy Formulations unviable forcing the industry to close down or look for some other alternative. These factors shall not be in the consumer/public interest.

84. The domestic industry, in their rejoinder submissions, have refuted the above submissions by stating that the downstream pharmaceuticals producers are export oriented units exclusively set up for exports and do not cater to the Indian domestic demand. However, they have not put forth any documentary evidence in support of their claim.

85. As regards potential injury to the producers of Pyrazolone in India, as averred by some interested parties, it has been submitted by the DI that injury suffered by downstream producers on account of dumping of the downstream product cannot be attributed to safeguard duties being levied on the product under consideration, more importantly, the fact that the Pyrazolone producers are already suffering grave injury despite no safeguard duty on MAAE clearly implies that the cause of concern for such producers is insufficient anti dumping duty and not duties being levied on the PUC.

86. The issue has been examined. It is noticed that the DI is the only producer of the PUC in India and has 100% market share. Though some Interested Parties have contended that, if safeguard measures are imposed, the DI will gain and it may lead to a monopolistic hegemony of the DI. However, none of the Interested Parties have provided any documentary evidence in support of their claim. The DI has also not provided any tangible evidence in support of their contention that imposition of safeguard duty shall be in the Public Interest at large. They have only made averments. It has also been seen that the PUC has seasonality attached to it. The DI is producing the PUC as well as several other products, which, as has been discussed earlier, are produced in a combination of other products in the same factory. The capacity to produce the PUC is limited to 4950 MT; but they can produce up to 7260 MT, utilizing the product-swing route.

87. It has been contended by a Interested Party that a cyclical trend in imports is discernible. It is stated by them that import volumes are higher in Q1 and Q2 and lower in Q3 and Q4. More significantly, when imports are lower in Q3 and Q4, domestic sales witness a sudden spurt. This is because during the first two quarters, DI chooses to use its limited capacity to manufacture Monomethyl Acetoacetate (MMAA) which yields higher profitability than sales of MAA, since MMAA has a seasonal demand lasting first two quarters. Thereafter, DI starts to employ its production facility for the production of MAA. Therefore, DI's assertion that imports are displacing DI in the Indian market for MAA is incorrect. As per the data available, it is seen that in the first 2 quarters of the Financial Year, the ratio of production of MMAA is much higher than the MAA, as below:

<b>Data Indexed</b>				
	<b>MAA</b>		<b>MMAA</b>	
	<b>Production</b>	<b>Sale</b>	<b>Production</b>	<b>Sale</b>
2010-11(Q1)	100	60	1041	1006
2010-11(Q2)	342	232	1362	1340
2011-12(Q1)	305	453	1834	1858
2011-12(Q2)	547	520	1521	1507
2012-13(Q1)	514	542	1845	1880
2012-13(Q2)	382	336	616	582

88. Going by the actual capacity utilization in this case, there appears to be a huge gap in demand and supply of the PUC. Rather, the injury, if any, to the DI may be attributed to its own selective utilization of its installed capacity, which may be employed interchangeably for making both MAA and MMAA. The Post POI data clearly shows that the share of production is increasing at the cost of imports in relative terms and all the economic parameters like production, sale, inventory, productivity, employment and profitability are showing significant improvement on actual basis. The imports are declining and the demand is rising which means that the domestic supply of the PUC has improved. Moreover, it is already on record that the PUC is used by a large no. of sectors in India like Pharma, industry, Dyes, Paints, etc., and in one of such products, viz., Pyrazolon, anti dumping duty is already imposed. The pertinent point is that the DI has not been able to give evidence as to how imposition of safeguard duty on the PUC will not affect these consumers, a few of whom are in sensitive pharma sector, and that the impact would be minimal so as to be in Public Interest. Moreover, as per the claim of the DI - that they are capable for meeting the demand by product swing route, the possible impact of this change that will take place on the end users of the other product and the fact that it will hamper/restrict/modify/nullify the product already being manufactured at the cost of MAA has not at all been provided during the investigation. In complete absence of any data quantifying such impact on the end users of different product signifies no public interest assessment at all by the DI.

89. Moreover, negative price undercutting means that the user/public at large have a viable choice of procurement. In this scenario, if the DI gets a protection in the form of safeguard duty on the PUC, it will render the imported goods costlier than the domestic goods, thereby creating an unfair market condition for the users of this product and the price escalation would hamper availability of cheap downstream products, including medicines. In this regard, the contention

of the DI that import prices have not increased in proportion to the increased raw material prices abroad does not hold relevance in the present investigation.

90. Therefore, the fact remains that the product under consideration is being imported at a very competitive price and the performance of the DI in the period April'13-July'13 (post-POI) indicates no threat of any serious injury or any sustainable cause of concern to the DI.

91. In view thereof, considering the points put forth by the DI as well as all the Interested Parties, it is concluded that the imposition of safeguard duty on Methyl Acetoacetate may not be in the Public Interest at large.

#### IX. Other factors causing serious injury or threat thereof:

92. Para (2) of Annex to the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 lays down that the determination referred to in subparagraph (1) shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the article concerned and serious injury or threat thereof and when factors other than increased import are causing "serious injury" to the Domestic Industry at the same time, such "serious injury" shall not be attributed to increased imports.

93. As such, the possible other factors that may be attributed to the serious injury to Domestic Industry have been examined. Followings are relevant in this regard-

a) **Demand of the product:** When overall demand increases, it is expected that, in tandem therewith, sales of the domestic industry will show rising trend; may be imports too show such a trend. However, in this case, market share of the DI has shown a decline whereas the market share of imports has risen. It is, thus, clearly seen that the increased imports have taken away the major share of the demand. However, it is also a fact that the total capacity of the DI is less than the demand of the product in the post POI (2013-14 Q1), which points to minimized or no threat to the DI, as well as no causality due to increased imports.

b) **Changes in the patterns of consumption:** It is claimed by the Domestic Industry that there is no evidence on record that the pattern of consumption with regard to the product under consideration has undergone any material change as far as the Indian market is concerned. Also, none of the Interested Parties has brought out any evidence to dispute this claim of the Domestic Industry, and is, as such, accepted.

c) **Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers:** There is no evidence on record that trade restrictive practices or competition between the foreign and domestic producers could have contributed to the injury to the Domestic Industry. However, it is a fact that the DI is having 100% market share and the imports are coming in at very competitive prices, so much so that there is no price under-cutting for analyzing injury margin.

d) **Export performance:** Applicants have exported small volumes of the product under consideration. However, the claimed injury to the Domestic Industry is on account of domestic operations.

e) **Developments in technology:** The applicant has claimed that the technology for production of the product has not undergone any change. This has not been refuted by any Interested Party. Developments in technology are therefore, not a factor of injury in this case.

94. It is thus noted that possible other factors have not decisively caused injury to the Domestic Industry.

#### X. Causal Link between Surge in Imports and Serious Injury & Threat of Serious Injury caused:

95. The Panel on Korea-Dairy set forth the basic approach for determining "causation":

*"In performing its causal link assessment, it is our view that the national authority needs to analyse and determine whether developments in the industry, considered by the national authority to demonstrate serious injury, have been caused by the increased imports. In its causation assessment, the national authority is obliged to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry. In addition, if the national authority has identified factors other than increased imports which have caused injury to the Domestic Industry, it shall ensure that any injury caused by such factors is not considered to have been caused by the increased imports.*

*To establish a causal link, Korea has to demonstrate that the injury to its Domestic Industry results from increased imports. In other words, Korea has to demonstrate that the imports of SMPP cause injury to the Domestic Industry producing milk powder and raw milk. In addition, having analyzed the situation of the Domestic Industry, the Korean authority has the obligation not to attribute to the increased imports any injury caused by other factors."*<sup>12</sup>

<sup>12</sup> [Panel Report on Korea – Dairy](#), paras. 7.89-7.90

96. For the purpose of determining causation, all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of the industry have been evaluated. In the instant case, the following are relevant in this regard—

- I. It has been submitted by the DI that there is a direct causal link between the increased imports and the serious injury to the domestic industry.
- II. The landed price of imports is significantly lower than reasonable costs.
- III. Selling prices of the domestic industry are determined by the import prices.
- IV. Consequently, production, capacity utilization, sales, profits, return on investment and cash flow is declining due to continued presence of low price imports.

97. Some interested parties have claimed that there is no demonstration on causation between the surge in imports and injury to the DI and that the injury to the DI is on its own account and cannot be attributed to imports.

98. In this regard, the following observations have been relied upon for determination of the causality:

- I. There has been a surge in imports over the POI both in absolute terms and in relation to the production.
- II. There is serious injury to the domestic industry over the POI.
- III. There appears to be no threat of serious injury to the DI.
- IV. Even though the DI has swing capacity to cater to the demand as of 2012-13, it falls short to possible demand in 2013-14.
- V. The landed value of the imported MAA is higher than the selling price of MAA of the DI.
- VI. There is no price undercutting which means the Domestic Industry is selling the PUC in fair competition to imports, even then the imports are surging at the cost of DI's sale.
- VII. Market share of imports increased and, consequently, market share of the Domestic Industry declined.
- VIII. There is a marked seasonality involved for this product.
- IX. When there is a decline in imports in 2011-12 and the DI has a better performance, the DI suffered its highest loss, about 3.3 times higher than the previous year. However, when import has surged in 2012-13 and almost all parameters of the DI show serious injury, the losses have eased significantly, by about 32% from the preceding year. Again, when the DI shows overall improvement in 2013-14 (April'13-July'13), the losses jumped by 2.5 times over the corresponding period during the previous year. However, the trends in losses do not appear to conform to the causal analysis, probably due to the price factor, which is not the subject under safeguard investigations under Section 8B of the Customs Tariff Act'75.

99. The examination of the above factors, therefore, shows that there appears to be a causal link between surge in imports and the serious injury caused to the DI over the POI, but the same causality is not sustained for the latest period i.e., April'13-July'13.

#### **XI. Adjustment Plan:**

100. Rule 5(2) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997 requires submission of a statement on "efforts being taken or planned to be taken or both to make positive adjustment to import competition". The WTO Agreement on Safeguard provides that a member shall apply safeguard measure only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and facilitate adjustment.

101. The purpose of definitive safeguard measure is to provide the domestic producers with a limited period of time in which to restructure so as to more effectively compete with the imports. Section 8B (4) of Customs Tariff Act 1975 and Rule 16(2) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997 prohibits any possible extension of measure if there is no evidence that the domestic producers are adjusting.

102. The domestic producers in this case has laid down adjustment plan which mainly focuses on cost reduction in the following sectors:

- i) Raw Material.
- ii) Power & Utilities
- iii) Sales and Inventory management.

103. The Applicant has submitted that the manufacturing facility was purchased from another owner and that they have already invested a large sum of money in upgrading the facilities to world standard. Moreover, their focus on raw material pertains to reduction in consumption of main raw materials by improving conversion norms and selectivity to ketene and diketene and change from batch process to continuous process. They also intend to replace oil with that of coal to reduce energy cost. They have planned efficiency boost up in their sales and inventory management for minimizing overhead costs. All these positive adjustments are planned for over a period of 2-3 years.



104. Some of the interested parties have contended that the DI has not provided the requisite adjustment plan, i.e., without any concrete details and that the adjustment plan submitted by the DI has been claimed to be excessively confidential.

105. In this regard, it has been noticed that the DI has provided an adjustment plan spread over a period of 2-3 years. As contended by the Interested Parties, no concrete time-bound plan for positive adjustments has been envisaged by the DI that is active and almost the entirety of the adjustment plan is proposed. However, this may be probably due to the reason that the DI has already made initial investments in 2010-11 and they are still waiting to gauge the results of their investments done till date based on which they intend to improve upon. It is because of these factors that the DI has requested safeguard duty for a period of 4 years. The fact, however, remains that adjustment plan given by the DI is only proposed and, as averred, changes/positive adjustments are to be undertaken over 2-3 years. But, no actual time frame has been fixed for such changes.

**XII. Conclusion and recommendation:**

- (i) There has been a significant increase in imports in absolute terms in the year 2012-13 as compared to the immediately preceding year 2011-12. However, this increase is not as sharp when the comparison is made with the base year, because the imports have fallen in 2011-12 vis-à-vis the base year 2010-11. Even though increase is noticed, it is important to note that in this case, the rise in imports has been insignificant/marginal in comparison to demand in 2012-13 when compared with the base year. However, even if it cannot be concluded that there is a continuous surge in imports over the entire POI, it is noted that there has been significant increase in imports during POI so as to cause serious injury.
- (ii) On analysis of the data for the period April to June, 2013 and 2013-14(A), to arrive at a fair conclusion, it is observed that the position of the domestic industry has improved on account of factors of market share, production, sales and capacity utilization. Even the imports have declined. Based on the above, it is concluded that there is no threat of serious injury to the Domestic Industry.
- (iii) DI's assertion that imports are displacing DI in the Indian market for MAA does not seem to be correct as discussed hereinbefore. In fact, it is the restrictive/regulated production of MAA in accordance with their own suitability by the DI, that is affecting the imports of the product, especially in view of the fact that DI has claimed to have excess capacity than the total demand of the product in question.
- (iv) The domestic industry has not been able to demonstrate that the developments in the market for the Product under Consideration were unforeseen. On the contrary, even the information supplied by them does not support their case, as examined in detail in the relevant paragraphs above. Therefore, it is concluded that the DI has not been able to substantiate its claim of unforeseen circumstances leading to surge in imports of the PUC with any concrete/tangible evidences.
- (v) The DI has not been able to clearly demonstrate that the imposition of the safeguard duty on the PUC for four years is absolutely in Public Interest. When there is no threat of serious injury and the fact that imports are coming in at competitive prices establish that the DI is unable to establish that imposition of Safeguard duty as per their petition for the same would be in Public Interest.

106. In view thereof, no safeguard duty on the imports of Methyl Acetoacetate is recommended.

[F. No. D-22011/8/2013/Part A/1562]  
RAM TIRATH, Director General